R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 । अंक : 10
16 से 29 फरवरी 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

करोड़ों का घोटाला मिनटों में निपटारा

हर साल विधानसभा में पेश होने वाली कैग की रिपोर्ट केवल खानापूर्ति

योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार-लापरवाही से सरकार को अरबों की चपत

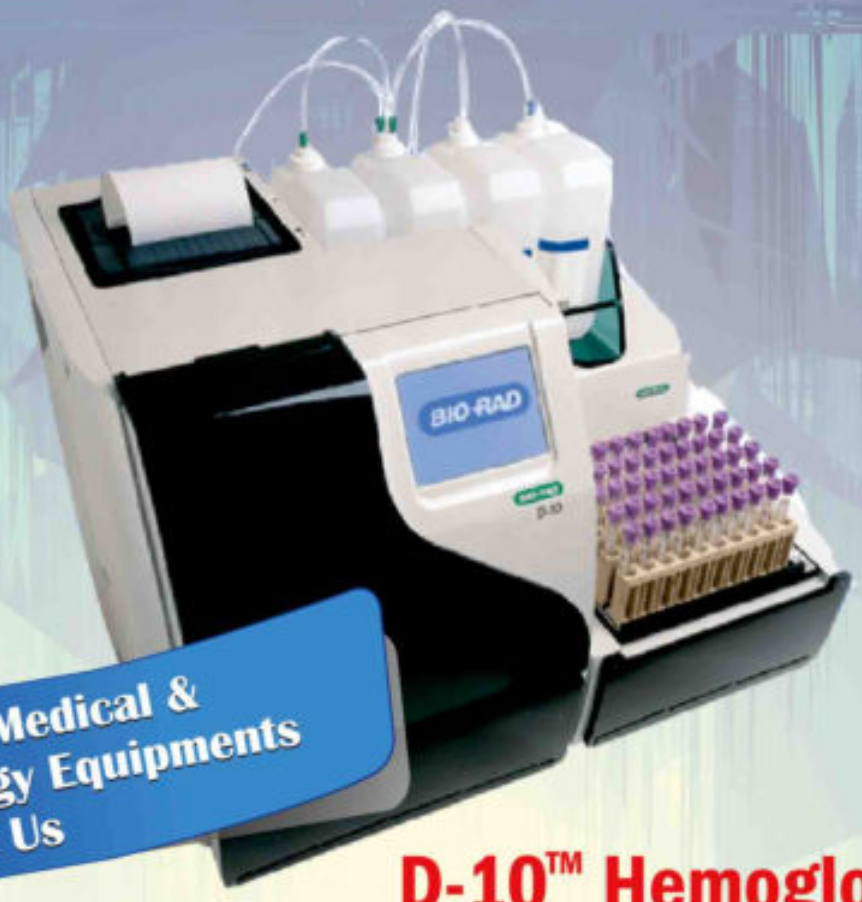

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

पहल

9 | सिंहस्थ से पहले क्षिप्रा होगी...

मप्र की क्षिप्रा नदी को अविरल बनाने के लिए केआरबीए यानी क्षिप्रा नदी कछार प्राधिकरण बनेगा। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। प्राधिकरण क्षिप्रा नदी को अविरल बनाने पर काम करेगा।

राजपथ

10-11 | मोहन 'राज' पर बढ़ा...

दो दशक के दौरान मप्र की जनता ने चार मुख्यमंत्रियों को देखा और परखा है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने शासन-प्रशासन के संचालन और विकास के लिए जो इनोवेशन किया है उससे प्रदेश की...

भर्राशाही

14 | 2 के भरोसे सूचना आयोग

जिस आयोग के जिम्मे लोगों को जनहित की सूचनाएं दिलाना है, वह सूचना आयोग इस समय दम तोड़ता हुआ नजर आने लगा है। इसकी वजह है आयोग में 11 आयुक्तों में से महज अब दो आयुक्तों का ही रह जाना। आश्चर्यजनक तो यह है कि...

विकास

18 | नई तकनीक के साथ...

मप्र में रोड और फ्लाईओवर का जाल बिछाया जाएगा और अगले दो सालों में 17 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट अमल में लाएंगे। जनप्रतिनिधियों के क्षेत्रों में भी लगभग 3 हजार करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विकास कार्य होंगे। लोक निर्माण विभाग को अत्याधुनिक बनाया जाएगा...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

वाकई मप्र अजब है, गजब है! तभी तो हर साल विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। उस पर विपक्ष भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करता है, तथा सरकार तथ्यों की जांच कर दोषियों को सजा देने का ऐलान करती है, लेकिन अब तक कैग की रिपोर्ट के आधार पर किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस स्थिति पर यही कहा जा रहा है कि करोड़ों के घोटाले का सरकार मिनटों में निपटारा कर देती है।

राजनीति

30-31 | पराजयवादी मानसिकता...

देश के दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने के तौर तरीकों में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। 2014 और 2019 की तरह ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी यह फर्क साफ दिख रहा है। 2019 के...

महाराष्ट्र

35 | मराठवाड़ा का गणित सेट

लोकसभा चुनाव करीब है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी कुछ ही महीने बाद होने हैं। सियासत के इस चुनावी मौसम में भाजपा के लिए बसंत और कांग्रेस के लिए पतझड़ की स्थिति बनती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में पहले मिलिंद देवड़ा, फिर बाबा सिद्दीकी और अब पूर्व...

बिहार

38 | बिहार में खेल अभी खत्म नहीं

129 विधायकों के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार विधानसभा में अपना बहुमत तो सिद्ध कर दिया, लेकिन खेला करने के दावों और प्रतिदावों के बीच खेल का रोमांच अंत-अंत तक बिल्कुल वैसे ही बना रहा, जैसे लास्ट बॉल तक चले...

6-7 अंदर की बात
40 विदेश
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

आईना वही, चेहरा बदल गया...

कवि और गीतकार आनंद बक्शी का लिखा फिल्म शालीमार का यह गीत...

आईना वो ही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं,
आंखों में रुकते नहीं जो, आंसू निकल जाते हैं।

वर्तमान समय में मप्र सरकार पर सटीक बैठ रहा है। दरअसल, प्रदेश में दो दशक से भाजपा की सरकार है। इस दौरान 4 मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री भले ही बदलते रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय सरकार भाजपा की ही रही है। सबसे अधिक दिन शिवराज सिंह चौहान के हाथों में प्रदेश की कमान रही है। इस कारण अधिकांश नौकरशाह उनके करीबी बन गए हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मुख्यमंत्री के सबसे करीबी और चहेते अफसरों को पसंद नहीं कर रही है। सत्ता का चेहरा बदलते ही प्रदेश की प्रशासनिक धुरी रहे अफसरों के बुरे दिन शुरू हो गए। मंत्रालय में न उनका कोई रुतबा बचा है, न नाम और न ही कोई काम है। हालात यह हैं कि कई अफसरों को तो अब मंत्रालय आने में भी शर्म महसूस होने लगी है। प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में तो अब यह कहा जाने लगा है कि वर्तमान समय में जो अधिकारी हाशिए या फिर छोटे विभागों की कुर्सी पर हैं, वे सभी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे खास अधिकारियों में शामिल हैं। शिवराज सिंह की सरकार में जो नौकरशाह प्रशासन की आंख, नाक और कान माने जाते थे, उन्हें लगभग साइडलाइन कर दिया गया है। अब उन अफसरों को ऐसे विभाग दिए गए हैं, जिनकी उन्होंने कभी कल्पनाएं भी नहीं की थीं। यही नहीं नए मुख्यमंत्री ने विगत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कई फैसलों को पलट दिया। सबसे चौंकाने वाला मामला मध्यप्रदेश गान से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि मध्यप्रदेश गान राष्ट्र गान से बड़ा नहीं है। यही नहीं, गत दिनों नए मध्यप्रदेश ने 46 लोगों से ओहदा छीन लिया जिन्हें विभिन्न संस्थाओं का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाकर कैबिनेट या राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। कहा जा रहा है कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने की पूरी कोशिश जारी है। पहले तो उनके तैनात किए गए अफसरों को लेकर संशय बरकरार रहा कि उन्हें कब, कहां, किस मंत्री के पास या किस जगह पदस्थ किया जाएगा। मंत्रियों के स्टाफ में तैनात पुराने अफसर तक बदल दिए गए और सख्त ताकीद दे दी गई कि कोई भी मंत्री पुराने अफसरों की डिमांड नहीं करेगा। भले ही वो अफसर उनका कितना भी खास ही क्यों न रहा हो। अफसरों के बाद अब मोहन यादव की तलवार की धार घूमी है निगम मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के तहत, जिन्हें अचानक हटाने का फरमान जारी कर दिया गया है। अचानक हुआ ये फैसला निगम मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर किसी बिजली की तरह गिरा है। आपको बता दें कि किसी भी निगम मंडल के अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ये एक तरफ से उपकृत करने वाली पोस्टिंग मानी जाती है, जिसे लाभ का पद भी कहा जाता है। लाभ का पद इसलिए क्योंकि निगम मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनकर नहीं लाए जाते न ही सत्ता में इनकी सीधे तौर पर भागीदारी होती है। इन जगहों पर ऐसे नेताओं को पदस्थापना दी जाती है जो किसी न किसी तरह से पार्टी के लिए फायदेमंद हों, जो नेता बहुत वरिष्ठ हों, लेकिन उन्हें विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाया गया हो या ऐसे असंतुष्ट हों जिन्हें चुनाव में उतारकर जीत मिलना मुश्किल है, लेकिन बाहर का रास्ता दिखाने से भी नुकसान हो सकता है।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 10, पृष्ठ-48, 16 से 29 फरवरी, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

लोकसभा की तैयारी...

मिशन 2023 को फतह करने के बाद भाजपा मिशन 2024 में जुट गई है। पार्टी विधानसभा चुनाव की ही तरह लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसके तहत पार्टी टिकटों की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। सांसद के टिकट के लिए कई नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है।

● **अमन शर्मा,** कटनी (म.प्र.)

सख्ती दिखाए सरकार

मप्र में अधिकारियों के आपा खोने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कलेक्टर से लेकर एसडीएम तक अपने बर्ताव के कारण सुर्खियों में रहे। सरकार को ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, जो आम जनता से बुरा व्यवहार करते हैं।

● **प्रिया नागर,** भोपाल (म.प्र.)

...भा रहा हमारा मप्र

देश–दुनिया के सैलानियों के लिए मप्र मनपसंद बनता जा रहा है। सांची स्तूप से लेकर हनुवंतिया टापू तक ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इन दिनों इंदौर भी सैलानियों के लिए खास बना हुआ है। दूर–दूर से लोग यहां आ रहे हैं।

● **रूपेश अग्रवाल,** इंदौर (म.प्र.)

फिट बैठ रहे हैं नए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव ने सरकार की तरफ से, अब तक जो निर्णय लिया है, वह जनता के बीच सराहा जा रहा है। मप्र की जनता को लग रहा है कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए फिट हैं। उनके द्वारा जो पहला निर्णय लिया गया था वह लाउडस्पीकर और डीजे का अनियंत्रित प्रयोग प्रतिबंधित करने का था। इसी के साथ खुले में मांस, मछली की बिक्री पर प्रतिबंध। हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान। तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रुपए किया। वहीं उन्होंने दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के विस्तार के लिए 5 हजार करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी। उनके इन निर्णयों से लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है।

● **प्रिंस ठाकुर,** सीहोर (म.प्र.)

आखिर किस फिराक में हैं वसुंधरा

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोई नया विकल्प तलाश रही हैं? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है। अटकलों का बाजार इसलिए गर्म हुआ कि वसुंधरा राजे लोकसभा चुनाव के लिए बुलाई गई पहली बैठक से दूर रहीं। यही नहीं राजस्थान में 3 दिसंबर को रिजल्ट के बाद बड़े कार्यक्रमों से वसुंधरा राजे ने दूरी बना ली थी। वसुंधरा राजे कैंप के तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है। सियासी जानकार इसे तूफान के पहले की शांति बता रहे हैं।

● **मनीष कटारिया,** जबलपुर (म.प्र.)

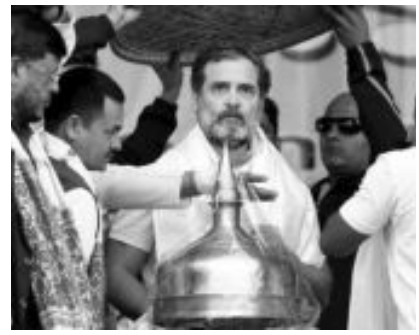

कांग्रेस की यात्रा

लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी–अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी अपनी तैयारी में लग चुकी है। राहुल गांधी इन दिनों अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि वे लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर सकें। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की यह यात्रा फीकी सी पड़ चुकी है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी।

● **सौरभ भारद्वाज,** विदिशा (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका?

उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रत्याशी चयन को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा प्रदेश की वीआईपी सीट हरिद्वार की हो रही है। कांग्रेस का एक खेमा प्रियंका गांधी वाड्रा को हरिद्वार सीट से चुनाव मैदान में उतारने की मांग कर रहा है। इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि इस सीट से प्रियंका को लड़ाने के बाद किसी तरह का विवाद नहीं होगा और सब एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार-प्रसार करेंगे। अभी तक हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की दावेदारी सामने आ चुकी है। दोनों ही इस सीट से प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रियंका का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की मानें तो जिलाध्यक्षों की बैठक में कुछ पदाधिकारियों ने प्रियंका को हरिद्वार सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठाई थी। माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी अपने स्तर पर लोकसभा क्षेत्रों में सर्वे कराएगी। इसके बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कांग्रेस इस बार चुनाव में किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। पार्टी उसी प्रत्याशी पर दांव खेलना चाहेगी जो जीत दिला सके। समीकरण के हिसाब से यहां पर कांग्रेस भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है।

खतरे में इंडिया गठबंधन

इंडिया गठबंधन का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार के पाला बदलने से सकते में आए इस गठबंधन को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर रोज नया झटका दे विपक्षी दलों की एकता को खतरे में डालने का काम कर रही हैं। गत सप्ताह राहुल गांधी की न्याय यात्रा बंगाल से गुजर रही थी। इस यात्रा में शामिल होने के बजाय ममता ने कांग्रेस पर हमला बोलने का काम कर दिखाया। उन्होंने कहा, मुझे संदेह है कि क्या कांग्रेस 40 सीटें भी सुरक्षित कर पाएगी या नहीं। ममता का यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया है। तृणमूल कांग्रेस के इस फैसले को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए ममता कांग्रेस पर खूब बरसीं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस 300 में से 40 सीटें भी जीतेगी या नहीं। फिर यह अहंकार क्यों है? आप बंगाल आए मगर मुझे बताया भी नहीं। हम तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। अगर आप में हिम्मत है तो वाराणसी में भाजपा को हराकर दिखाइए, आप उन जगहों पर भी हार गए जहां पहले जीतते थे।

अब राजनीति में करेंगे शिरकत!

भोजपुरी फिल्मों का एक जाना माना नाम है पवन सिंह का। उनकी एक्टिंग और अंदाज को काफी पसंद किया जाता है। लंबे समय से पवन को लेकर एक चर्चा चल रही है कि वे इस साल होने वाले आम चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। इन दिनों एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद इन अटकलों को हवा मिलने लगी है। हाल ही में पवन सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। उनकी इस मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसे देखने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन अब सिनेमा से सियासत में एंट्री ले आम चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा पवन सिंह ने मीडिया से भी बातचीत की और चुनाव लड़ने के सवाल पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं चुनाव लडूंगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। इससे पहले भी पवन सिंह चुनाव लड़ने को लेकर बात कर चुके हैं। उन्होंने पटना भाजपा कार्यालय में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में कहा था कि उनकी पार्टी जो कहेगी वो वहीं करेंगे। किसको आगे बढ़ने का मन नहीं करता। अब उनके इन बयानों को लेकर चर्चा है कि वे जल्द ही जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम उसके सिम्बल पर चुनावी मैदान में शिरकत करते नजर आएंगे।

फिर सिरदर्द बने सिद्धू

पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी का दौर शुरू हो गया है। आगामी आम चुनाव को लेकर हाल ही में हुई पार्टी की अहम बैठक में वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू जाने की बजाय कांग्रेस के तीन पूर्व प्रधानों लाल सिंह, शमशेर सिंह दुलों और मोहिंदर केपी से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर लिखा कि पंजाब के राजनीतिक हालात पर चार पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्षों ने बैठक की। इसके बाद से ही सियासी हल्कों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिद्धू पार्टी के लिए ऐसा सिरदर्द बनते जा रहे हैं जिसे नासूर बनने से पहले नष्ट किया जाना चाहिए। अन्यथा इसके परिणाम जैसे कि पार्टी पहले देख चुकी है उसके लिए तैयार रहे। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से नवजोत सिंह सिद्धू की पैरेलल बैठक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह अनुशासनहीनता है।

बदलने लगे उद्धव के सुर

आगामी लोकसभा और साल के अंत में प्रस्तावित महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर देश की सियासत गरमाने लगी है। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के सूत्रधार नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद चर्चा जोरों पर है कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना (यूटीबी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के रूप में इंडिया का एक और विकेट गिर सकता है। इस बात को हवा मिली हाल ही में एक जनसभा के दौरान उद्धव के बदलते सुरों से। उद्धव ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह कभी प्रधानमंत्री के दुश्मन नहीं थे और न ही हैं। मोदी ही वह व्यक्ति थे, जिन्होंने शिवसेना के साथ संबंध जोड़ने का फैसला किया था। हम आपके साथ थे। शिवसेना आपके साथ थी, लेकिन बाद में आपने हमें खुद से दूर कर दिया। उद्धव के इस बयान के बाद चर्चा है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब शायद महाराष्ट्र में भी गठबंधन में फूट डलने वाली है और ठाकरे फिर से एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं।

ये अजब सिंह कौन है... ?

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक नाम सबसे अधिक चर्चा में है। यह नाम है अजब सिंह...ये जनाब न तो कोई नौकरशाह या अधिकारी हैं और न ही नेता। फिर भी इस व्यक्ति का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। आलम यह है कि इस व्यक्ति को अधिकांश अफसर पहचानते भी नहीं हैं, लेकिन इनकी चर्चा खूब हो रही है। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि साहब एक मंत्री जी के चहेते हैं। इन्हें मंत्रीजी ने अपने पास रख रखा है और अपना गोपनीय काम उन्हें सौंप रखा है। दरअसल, ये जनाब मंत्रीजी के लिए लक्ष्मीजी की कृपा बटोरने का काम करते हैं। सूत्रों का कहना है कि अजब सिंह सुबह से ही अधिकारियों, ठेकेदारों, सप्लायरों को फोन करके कहते हैं कि आपसे मंत्रीजी मिलना चाहते हैं। यही नहीं उनके खिलाफ शिकायतों का हवाला देने से भी नहीं चूकते हैं। इस तरह का तिकड़म कर जनाब मंत्रीजी के नाम पर उगाही कर रहे हैं। बताया जाता है कि इन महाशय के किस्से अब प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चटखारे लगाकर सुनाए जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार ने सुशासन के नाम पर मंत्रियों को अपनी पसंद का सरकारी स्टाफ रखने पर पाबंदी लगा रखी है, वहीं दूसरी तरफ मंत्री निजी स्टाफ रखकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बता दें यहां जिस मंत्रीजी की बात हो रही है वे ग्वालियर-चंबल अंचल से आते हैं।

दूसरी पत्नी की गुहार...

हम सभी ने यह बात तो हमेशा सुनी है कि पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां करवाचौथ का व्रत करती हैं। लेकिन इन दिनों प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में एक अधिकारी की पत्नी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल, उक्त महिला अपने पति की अच्छी पोस्टिंग के लिए गुहार लगाती फिर रही हैं। जिस साहब की पत्नी की यहां बात हो रही है, वे 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। साहब डीआईजी के पद पर काबिज हैं। साहब का चाल और चरित्र कैसा होगा इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो महिला उनकी अच्छी पदस्थापना की गुहार लगा रही है, वह उनकी दूसरी पत्नी हैं। बताया जाता है कि पुलिस मुख्यालय से लेकर राज्य मंत्रालय तक साहब और उनकी दूसरी पत्नी को लेकर तरह-तरह के किस्से भी सुनाए और गढ़े जा रहे हैं। इसके पीछे कितनी हकीकत और कितना फसाना है यह तो साहब और उनकी दूसरी पत्नी ही जानती हैं। लेकिन जहां कुछ लोग साहब की दूसरी पत्नी को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उनकी हिम्मत की दाद भी दे रहे हैं।

ये नाटू-नाटू क्या है... ?

प्रदेश में इस समय सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ हो रही है। हर कोई सरकार के मुखिया और उनकी जीरो टॉलरेंस नीति का बखान कर रहा है। जिस तरह सरकार के मुखिया अफसरों को छोटी-छोटी बात पर हटा रहे हैं, जनता को सर्वोपरि बता रहे हैं उससे सभी को लग रहा है कि प्रदेश में वाकई अब जाकर सुशासन आया है। लेकिन इसके पीछे की कहानी चौंकाने वाली है। जहां एक तरफ सरकार के मुखिया ने मंत्रियों को अपने स्टाफ में ईमानदार और बेदाग अफसरों को रखने की हिदायत दे रखी है, वहीं उन्होंने अपने पास एक ऐसे निजी व्यक्ति को रख रखा है जो साहब के सभी काम का संभाले हुए है। प्रशासनिक वीथिका ने इन दिनों चारों तरफ नाटू-नाटू ही सुनाई दे रहा है। लेकिन बाद में सबको पता चला कि ये साहब नाथू हैं। हर विभाग के अफसर इस नाम से वाकिफ हो गए हैं। जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि यह व्यक्ति सरकार के मुखिया का सारा काम संभाले हुए है। यह व्यक्ति उनके गृह क्षेत्र का है और उनका सबसे विश्वसनीय भी है। इसलिए माननीय ने उसके हवाले अपने सारे काम सौंप दिए हैं। गृह विभाग हो, परिवहन विभाग हो या कोई अन्य विभाग वहां किसके साथ क्या करना है, किसको उपकृत करना है, किसको किनारे करना है ये सारे काम नाथू ने ही संभाल रखे हैं। आलम यह है कि अफसर मंत्रियों से अधिक नाथू को महत्व दे रहे हैं। यह नाम सुनते ही सभी के कान खड़े हो जाते हैं।

...तो भाजपा कार्यालय बना दो

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में एक बार फिर से पलायन का दौर शुरू हो गया है। जो नेता विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को कोस रहे थे, और भाजपा जिन नेताओं पर तंज कस रही थी, अब वे भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों के दौरान कांग्रेस के नेता हर दिन पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में अब लोग कहने लगे हैं कि रोज-रोज पार्टी बदलने से अच्छा है कि कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय को भाजपा का उप कार्यालय घोषित कर दिया जाए। ऐसे में नेताओं को पार्टी बदलने का तामझाम भी नहीं करना पड़ेगा। अब तो स्थिति यह दिख रही है कि जिस नेता से नाराज होकर महाराज ने कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा का दामन थाम लिया था, अब वे नेता भी पुत्र और समर्थकों के साथ कमलदल में शामिल होने की कवायद में लगे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपाई कांग्रेस मुक्त देश की बात कर रहे थे, लेकिन आज भाजपा ही कांग्रेस युक्त हो गई है। ऐसे में रोज-रोज पार्टी बदलने का खेल खेलने से अच्छा है कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को भाजपा का दफ्तर मान लिया जाए।

सेर को मिला सवा सेर

प्रदेश के एक सबसे महत्वपूर्ण विभाग की बड़ी कुर्सी मिलने के बाद से एक आईएएस अधिकारी के हाव-भाव बदल गए हैं। इसकी वजह यह है कि विभाग में साहब की स्थिति सेर को मिला सवा सेर वाली हो गई है। यानी विभाग में उनसे भी बड़े एक साहब हैं। जिनके आते ही साहब को कुर्सी से उठना पड़ता है। इसलिए साहब को यह विभाग पसंद तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मन मारकर काम कर रहे हैं। विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद जब पहली बार विभाग में गए तो उन्होंने सबसे पहले सेक्शन का दौरा किया। वहां फाइलों को भंडार देखकर उन्होंने मातहतों को पहले तो फटकार लगाई उसके बाद झाड़फूंक कर उनको निपटाने का निर्देश दिया है। यही नहीं साहब खुद फाइलों को गोदने में लगे हुए हैं। साहब की इस स्थिति को देखकर उनके मातहत चुटकी लेते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे साहब हथेली पर दूब उगा देंगे। गौरतलब है कि इससे पहले साहब जिस विभाग में रहे हैं, वहां उनकी मंत्री से भी नहीं पटी थी। अब यह देखना है कि साहब इस विभाग में किस तरह काम करते हैं और कितने दिन टिक पाते हैं।

> मप्र में मुख्यमंत्री की कमान संभालते ही डॉ. मोहन यादव सुशासन और विकास पर सबसे अधिक जोर दे रहे हैं। लेकिन उनकी राह में आर्थिक स्थिति बाधा बनकर खड़ी है। दरअसल, चुनाव के दौरान की गई घोषणाएं सरकार को भारी पड़ने लगी हैं और उनके लिए हर माह अरबों रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है।

चुनावी सौगात... बढ़ा कर्ज का भार

मप्र पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार को बाजार से हर माह अरबों रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है। मप्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार से लगातार कर्ज ले रही है। राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से अपनी गवर्मेंट सिक्युरिटीज का विक्रय कर दो हिस्सों में कुल 3 हजार करोड़ रुपयों का कर्ज बाजार से लिया है। इसमें 1500 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 16 वर्ष और 1500 करोड़ रुपए का दूसरा ऋण 17 साल में चुकाया जाएगा। दोनों ही कर्ज पर साल में दो कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा।

वर्तमान वित्तवर्ष में मप्र सरकार अब तक कुल 24 हजार 500 करोड़ रुपयों का बाजार से कर्ज ले चुकी है और गत दिनों लिए गए 3 हजार करोड़ रुपए के कर्ज को मिलाकर कुल कर्ज 27 हजार 500 करोड़ रुपए का हो गया है। इसके पहले भी जनवरी 2024 में ढाई हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। प्रदेश के ऊपर मार्च 2023 की स्थिति में 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण है। वहीं अब तक के कुल कर्ज को मिलाकर मप्र सरकार पर कर्ज का कुल भार साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।

प्रदेश पर कर्ज के साथ-साथ लगातार ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में लगातार ऐसी योजनाओं की झड़ी लगी है जिसके कारण सरकार का खजाना खाली भी होता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं जिनसे सरकार पर भार लगातार बढ़ता जा रहा है। इन योजनाओं में लाड़ली बहना योजना, किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोत्तरी, मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरण, मेधावियों को स्कूटी वितरण शामिल हैं। इसके आलावा सरकारी कर्मचारियों पर भी लगातार सौगातों की बरसात हो रही है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने 23 हजार रोजगार सहायकों का वेतन दोगुना किया, पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान दिया, कर्मचारियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाया, अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना किया, कॉलेज के अतिथि विद्वानों का मानदेय 20 हजार बढ़ाया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाया गया। इसके साथ ही लाड़ली बहना का बजट भी लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि योजना में लगातार प्रावधान किए जा रहे हैं।

वित्तीय संकट से जूझ रही मप्र सरकार लोन लेकर काम चला रही है। सरकार ने गत दिनों बाजार से 3 हजार करोड़ रुपए का लोन लिया है। डॉ. मोहन यादव सरकार का यह तीसरा लोन है। यह राशि लाड़ली बहना योजना समेत विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। सरकार पिछले 51 दिन में 7500 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है। डॉ. मोहन यादव सरकार ने 2 हजार करोड़ रुपए का पहला लोन 20 दिसंबर को लिया था। इसके बाद 18 जनवरी को 2500 करोड़ रुपए और 6 फरवरी को 3 हजार करोड़ का लोन लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि लोन लेने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली जाती है। वित्तीय स्थिति के आधार पर राज्य सरकार कितनी सीमा तक लोन ले सकती है, इसकी लिमिट तय की गई है। उसी के दायरे में सरकार लोन ले रही है। जानकारी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में सरकार 9 महीने (मई से जनवरी तक) में 29 हजार 500 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है। आचार संहिता लगने से पूर्व सरकार ने सितंबर में चार किश्तों में कुल 12 हजार करोड़ रुपए का लोन लिया था। यहां तक की विधानसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील रहते सरकार ने अक्टूबर व नवंबर में तीन किश्तों में 5 हजार करोड़ का लोन लिया था। नई सरकार बनने पर दिसंबर में 2 हजार करोड़ और जनवरी में 2500 करोड़ का लोन लिया गया। अब 3 हजार करोड़ का लोन सरकार ने लिया है। इसे मिलाकर चालू वित्त वर्ष में लोन की कुल राशि 32 हजार 500 करोड़ रुपए हो जाएगी।

● **कुमार विनोद**

साढ़े तीन लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज

प्रदेश सरकार पर 3 लाख 50 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। बजट में कर्ज के लिए 3 लाख 85 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। दरअसल, वित्तीय संकट को देखते हुए मप्र सरकार पिछले महीने 38 विभागों की 150 से ज्यादा योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा चुकी है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आमतौर पर वित्त वर्ष के आखिरी महीनों (जनवरी से मार्च तक) सरकार ज्यादा लोन लेती है, लेकिन इस बार चुनाव से पूर्व की गई लोकलुभावन घोषणाओं को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में ही सरकार को बड़ा लोन लेना पड़ा। मौजूदा बजट के मुताबिक सरकार की आमदनी 2.25 लाख करोड़ रुपए है, जबकि खर्च इससे करीब 54 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार की ओर से पिछले महीनों में की गई घोषणाओं पर बड़ी राशि खर्च होने के कारण सरकार का हर महीने का खर्च 10 प्रतिशत बढ़ गया है। सरकार का प्रति माह 20 हजार करोड़ का खर्च था, जो जून के बाद से बढ़कर 22 हजार करोड़ प्रतिमाह के पार पहुंच गया है।

सिंहस्थ से पहले क्षिप्रा होगी अविरल

मप्र की क्षिप्रा नदी को अविरल बनाने के लिए केआरबीए यानी क्षिप्रा नदी कछार प्राधिकरण बनेगा। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। प्राधिकरण क्षिप्रा नदी को अविरल बनाने पर काम करेगा। बता दें कि प्राधिकरण साल 1996 से पहले जैसी प्रवाहमान और स्वच्छ नदी बनाने का काम करेगा। 1996 से पहले क्षिप्रा नदी अविरल और स्वच्छ थी। इसके लिए सिंहस्थ 2028 से पहले तक का टारगेट तय किया जाएगा। क्षिप्रा नदी कछार प्राधिकरण में करीब 12 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकरण गठित होगा। जल संसाधन मंत्री और विभाग के चीफ इंजीनियर उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। नगरीय प्रशासन, एनवीडीए, ग्रामीण विकास, राजस्व, वन, कृषि, पीएचई विभाग के मंत्री सदस्य हो सकते हैं। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम नगरीय निकायों के प्रमुखों को भी स्थान मिल सकता है।

सिंहस्थ से पहले उज्जैन को पूरी तरह विकसित किया जाएगा। इसके तहत जहां क्षिप्रा नदी को स्वच्छ और अविरल बनाया जाएगा, वहीं शहर को भी संवारा जाएगा। अस्तित्व के संकट से जूझ रही सनातन धर्म की पवित्र नदियों में से एक क्षिप्रा को बचाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही क्षिप्रा नदी कछार प्राधिकरण (केआरबीए) का गठन करने जा रही है। जल संसाधन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद इसका नोटिफिकेशन जल्द हो सकता है। प्राधिकरण सिंहस्थ 2028 से पहले क्षिप्रा नदी को 1996 से पहले जैसी प्रवाहमान और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से काम करेगा। प्रदेश में 4 साल बाद वर्ष 2028 में सिंहस्थ होने जा रहा है। राज्य शासन ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित होने वाले इस प्राधिकरण का उपाध्यक्ष जल संसाधन मंत्री और कन्वीनर जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर को बनाने की तैयारी है। प्राधिकरण में लगभग 12 सदस्य होंगे, जिनमें नगरीय प्रशासन, एनवीडीए, ग्रामीण विकास, राजस्व, वन, कृषि, पीएचई विभाग के मंत्रियों समेत इंदौर, उज्जैन, धार, देवास और रतलाम जिलों के नगरीय निकायों के प्रमुख शामिल होंगे। क्षिप्रा नदी कछार प्राधिकरण के अधीन एक एक्जीक्यूटिव कमेटी का भी गठन होगा, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, और कन्वीनर बोधी (ब्यूरो ऑफ डिजाइन, हाइडल एंड इरिगेशन) के पदेन चीफ इंजीनियर को बनाया जाएगा। जिन विभागों को नदी पुनर्जीवन से जुड़े काम दिए जाएंगे, उनके प्रमुख अधिकारी समिति का हिस्सा होंगे।

जानकारी के अनुसार क्षिप्रा नदी कछार प्राधिकरण गंगा और मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकारण की तर्ज पर उज्जैन में सिंहस्थ तीर्थ क्षेत्र एवं आसपास के नगरों में विकास कार्यों को अंजाम देगा। प्राधिकरण में मुख्यमंत्री समेत 6 विभागों के मंत्री एवं एक दर्जन विभागों के अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव सदस्य हैं। प्राधिकरण का मूल ढांचा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से लिया गया है। जल्द ही कैबिनेट से क्षिप्रा नदी कछार प्राधिकरण पर मुहर लग जाएगी। प्राधिकरण का गठन करने का दायित्व जल संसाधन विभाग को सौंपा गया है। नए प्राधिकरण की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। जल्द ही इसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। इसमें शामिल विभाग मिलकर कार्यों को करेंगे। यानी एक विभाग दूसरे विभाग के काम में अड़ंगा नहीं लगाएगा।

क्षिप्रा के शुद्धिकरण से लेकर नालों, सड़क, पुल, सीवेज, भवन, जल वितरण आदि कार्य प्राधिकरण के जरिए ही होंगे। ये विभाग शामिल प्राधिकरण में वित्त, वन, पंचायत, पीएचई, नर्मदा घाटी विकास विभाग, जल संसाधन, राजस्व, नगरीय प्रशासन, पर्यावरण, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, धर्मस्य विभाग के मंत्री, प्रमुख सचिव और इंदौर, उज्जैन संभाग के आयुक्त शामिल हैं। प्रदेश में उज्जैन घोषित धार्मिक नगरी है। सिंहस्थ से पहले इसे धार्मिक दृष्टि से विकसित किया जाएगा। अवंतिका के इतिहास को उकेरा जाएगा। इसके लिए पूरी रूपरेखा बनेगी। प्राधिकरण गठित होने के बाद मप्र का दल काशी, मथुरा-वृंदावन एवं अन्य धार्मिक नगरों का दौरा कर वहां प्राधिकरण के जरिए किए गए विकास कार्य देखेगा। क्षिप्रा को निर्मल एवं अविरल बनाने, कछार क्षेत्र के नदी-नालों के दूषित पानी को क्षिप्रा में छोड़ने से पहले साफ करना, प्राधिकरण के कार्यों के लिए वित्तीय सहायता एवं अतिरिक्त संसाधन जुटाना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद से नदी संरक्षण के लिए प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करना, कछार क्षेत्र में निर्माण कार्यों की समन्वित कार्य योजना बनाना आदि क्षिप्रा नदी कछार प्राधिकरण का कार्य होगा। अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग राजेश राजौरा का कहना है कि क्षिप्रा नदी कछार प्राधिकरण का गठन प्रक्रिया में है। इसको लेकर विचार-विमर्श अंतिम दौर में है।

● **राकेश ग्रोवर**

विकास की भेंट चढ़ी क्षिप्रा

जल संसाधन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 1996 तक क्षिप्रा नदी में अविरल धारा होने की जानकारी मिलती है। तब तक नदी प्रदूषण से लगभग मुक्त थी। नदी का उद्गम और सबसे बड़ा वाटरशेड (जल ग्रहण क्षेत्र) एरिया इंदौर जिले में आता है। पिछले 30 साल में जिस तेजी से इंदौर शहर और उसके आसपास शहरीकरण और औद्योगिक विकास हुआ है, उसी गति से क्षिप्रा की धार टूटती चली गई और नदी प्रदूषण का शिकार होती चली गई। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े रहे पर्यावरण और नदी पुनर्जीवन विशेषज्ञ डॉ. सीताराम टैगोर का कहना है कि क्षिप्रा नदी पर पैदा हुए संकट के पीछे कई प्रमुख कारण माने गए हैं, जिसमें वाटरशेड एरिया में वन-आवरण घटना, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण बड़े हिस्से में लैंडयूज में आया बदलाव, भू-जल के अनियोजित दोहन से वाटर टेबल में गिरावट, जलवायु परिवर्तन और वर्षा चक्र में बदलाव शामिल हैं। यदि नदी को पुनर्जीवित करना है तो पूरे कैचमेंट एरिया में काम करना होगा।

दो दशक के दौरान मप्र की जनता ने चार मुख्यमंत्रियों को देखा और परखा है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने शासन-प्रशासन के संचालन और विकास के लिए जो इनोवेशन किया है उससे प्रदेश की जनता का विश्वास सरकार पर दोगुना हुआ है। अल्प समय में ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मप्र ही नहीं देशभर में अपनी छाप छोड़ी है।

मोहन 'राज' पर बढ़ा विश्वास

करीबन दो माह पहले मप्र में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा की प्रचंड जीत को देखा। इसके बाद भाजपा ने भी बदलाव की बयार को अंगीकार कर पीढ़ी परिवर्तन की राह पर कदम बढ़ा दिए। तमाम कयास, अनुमान और आंकलन को पीछे छोड़कर महाकाल की नगरी उज्जैन से विधायक डॉ. मोहन यादव को सूबे का नया सरदार बनाया गया। दो उपमुख्यमंत्रियों के साथ शपथ लेते ही नए मुख्यमंत्री ने जिन तेवरों के साथ प्रदेश की नई सरकार की तस्वीर पेश की, उसने प्रदेश की जनता के मन में उम्मीद की नई किरण जगाई है। बरसों-बरस से कागजों पर ही मौजूदगी दर्शा रहे आदेश कुछ घंटों में ही जमीन पर उतर आए। जन के लिए तंत्र को मैदान में तुरंत उतारकर समस्या के त्वरित निराकरण की यह शैली जनता को खूब भा रही है, लेकिन इस शुरुआत को अंजाम तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता पार करना होगा। पूरी तस्वीर बदलने के लिए अभी जिम्मेदारों को और अधिक जवाबदेह बनाना होगा। वर्ष 2003 के बाद से यदि कांग्रेस का डेढ़ वर्ष का शासनकाल छोड़ दिया जाए तो 2023 तक भाजपा ही सत्तासीन रही है। इस दौर में निश्चित ही मप्र ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ भी है। इस बार फिर प्रदेश की जनता ने भाजपा को चुनकर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए पांच वर्ष दे दिए हैं। नई सरकार से अब प्रदेश की जनता को जो कुछ मिल रहा है उससे कहीं अधिक देने की ओर बढ़ना होगा। प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ने के अवसर और मूलभूत सुविधाएं कैसे मिलें, यह सुनिश्चित भी करना होगा।

मप्र की मोहन यादव सरकार लगातार इनोवेशन कर रही है। राजधानी भोपाल से सरकार चलाने की जगह मुख्यमंत्री मोहन यादव संभागीय लेवल पर भी मॉनीटरिंग की व्यवस्था बना चुके हैं। इनोवेशन के इसी क्रम में सरकार की पहली अधिकारिक कैबिनेट बैठक गत दिनों जबलपुर में की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में **सरकार ने कई बड़े फैसले लिए** हैं। इसी कड़ी में अब मप्र सरकार को लगभग दो महीना पूरा हो गया है। सरकार ने अपने कार्यकाल को रामराज्य बनेगा हमारी पहचान, मोदी जी की गारंटी का परिणाम टैगलाइन दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हम मप्र को जनहित और विकास में सबसे अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। 21वीं सदी के भारत में अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं। हम प्रधानमंत्री के मोदी मार्गदर्शन में मप्र को जनहित और विकास में सबसे अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मप्र के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव ने जिस मजबूत इच्छाशक्ति के साथ जनता के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है, उससे पूरे राज्य में एक सकारात्मक संदेश गया है कि यह सरकार जनता की सेवा के लिए है। यह सरकार जनभावनाओं के अनुरूप विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के तुरंत बाद डॉ. मोहन यादव का पहला फैसला मप्र में धार्मिक स्थानों पर जोर से लाउडस्पीकर बजाने और खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर सख्ती से रोक का रहा। इस फैसले का सभी ने स्वागत किया। प्रदेश के धार्मिक स्थलों में लगाए गए कानफोड़ू लाउडस्पीकर लंबे समय से आम जनता की परेशानी का सबब बन गए थे। चूंकि यह मामला धार्मिक था, इसलिए इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक झटके में इस पर एक्शन लेकर अपने मजबूत इरादों को पहले दिन ही जता दिया। यही नहीं, खुले में मांस से लेकर अंडा बेचने पर भी उन्होंने रोक लगा दी। विपक्षी दलों ने इस आदेश में भाजपा और उसके अनुषांगिक संगठनों का साम्प्रदायिक एजेंडा देखा

वन-धन केंद्र खोलेगी सरकार

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन के तहत मप्र सरकार विशेष जनजातियों के विकास के लिए 18 जिलों में 201 नए वन-धन केंद्र खोलेगी। प्रदेश में बैगा, सहरिया और भारिया विशेष जनजातियां घोषित हैं। इन जनजातियों को वन विभाग के अंतर्गत संचालित लघु वनोपज संघ द्वारा नए वन-धन केंद्र खोलकर आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जाएगा। वन-धन केंद्रों में लघु वनोपजों का प्रसंस्करण कर उन्हें बाजार में अच्छी दरों पर बेचने का कार्य किया जाता है। मप्र में बैगा जनजाति की संख्या 3 लाख 63 हजार 47, सहरिया की 5 लाख 78 हजार 557 तथा भारिया की 33 हजार 517 जनसंख्या है। वहीं परिवार के छोटे-बड़े सभी सदस्यों को मिलाकर इनकी संख्या 11 लाख से अधिक है। प्रदेश के दतिया में 3, डिंडोरी में 20, गुना में 12, ग्वालियर में 12, कटनी में 2, मंडला में 19, मुरैना में 8, उमरिया में 5, रायसेन में 2, नरसिंहपुर में 5, शहडोल में 31, श्योपुर में 16, शिवपुरी में 15, सीधी में 6, अनूपपुर जिले में 13, अशोकनगर में 4, बालाघाट में 9 और छिंदवाड़ा में 19 वन-धन केंद्र खोले जाने हैं। ये वन-धन केंद्र सरकार स्वीकृत करती है और इसके लिए राशि भी उपलब्ध कराती है।

और इसे मुसलमानों के खिलाफ बताने की भी कोशिश की, लेकिन प्रदेश की आम जनता ने इसका स्वागत ही किया, क्योंकि यह नियम प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के लिए समान रूप से लागू किया गया था। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इस फैसले को देखें, तो खुले में मांस को बिक्री सेहत के लिए हानिकारक है। यही वजह रही कि जनता की तरफ से इस फैसले की सराहना हुई। इसके अलावा सरकार ने अन्य कई निर्णय लिए हैं जिसने जनता का मन मोह लिया है। जिनमें डीजे का अनियंत्रित प्रयोग प्रतिबंधित, खुले में मांस, मछली की बिक्री पर प्रतिबंध, हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान, तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3 हजार प्रति बोरा से बढ़ाकर किया 4 हजार, 35 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 165 करोड़ रुपए का लाभ, यातायात सुगमता के लिए भोपाल में बीआरटीएस हटाने का निर्णय, श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में किसानों को प्रति किलो के 10 का अतिरिक्त प्रोत्साहन, दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के विस्तार के लिए 5.5 हजार करोड़ की परियोजनाएं मंजूर, नागरिकों की सुविधा के लिए प्रदेश में संभाग, जिले, तहसील एवं पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ, एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को पदोन्नति, उज्जैन, इंदौर और धार जिले में जहां-जहां भगवान श्रीकृष्ण के चरण पड़े हैं वहां तीर्थ स्थलों का विकास होगा।

प्रदेश में श्रीराम वन पथ गमन के विकास की कार्य योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती की प्रेरणादायी वीरगाथा के विषय को शामिल करने का निर्णय, हर जिले में एक शासकीय महाविद्यालय का पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय के रूप में उन्नयन, 350 करोड़ लागत से 6.67 किमी का इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, ग्रीन बॉल्ड जारी कर जुटाए गए 308 करोड़ रुपए की राशि से खरगोन जिले के जलूद गांव में ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, स्वच्छ सर्वेक्षण अवॉर्ड 2023

में मप्र फिर आगे, इंदौर को लगातार सातवीं बार देश की स्वच्छतम सिटी कर अवॉर्ड, भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानी आदि।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने अब तक के शासनकाल में दिखा दिया है कि प्रदेश नवाचारों से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के उद्देश्य से हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का निर्णय भी लिया है। यही नहीं सरकार उच्च शिक्षा में प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में डिजीलॉकर सिस्टम लाकर छात्र-छात्राओं की समस्याओं के निवारण हेतु गंभीर दिखी है। जमीनों के फर्जीवाड़े को रोकने की दिशा में रजिस्ट्री के साथ अब नामांतरण की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। प्रदेश में जन समस्याओं से जुड़ा एक मुद्दा जिलों, तहसीलों और थानों की सीमा **के पुनर्निधारण** का है, जिसके लिए एक कमेटी बनाने का फैसला मोहन सरकार ने किया है। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर संभाग से की जाएगी। राज्य में कई तहसीलों और थानों की भौगोलिक सीमाएं ऐसी हैं जो स्थानीय नागरिकों की पहुंच से सरकार और प्रशासन की खाई को चौड़ा करती है। मोहन सरकार ने अपने दूरदर्शी फैसले से इसे पाटने की कोशिश की है। मोहन सरकार ने इस विषय में पहल कर जनता को प्रशासन के करीब लाने की दिशा में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं। नए साल में देशभर में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से आम जनता को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मोहन सरकार ने इसे देखते हुए ट्रांसपोर्टरों से सीधे बातचीत करने का फैसला किया, जिसमें प्रशासन ने बड़ी भूमिका निभाई। ट्रांसपोर्टरों के साथ बातचीत में जब शाजापुर के जिलाधिकारी ने एक ड्राइवर को औकात बताने की नसीहत दी, तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संवेदनशीलता को मिसाल पेश करते हुए जिलाधिकारी को पद से हटाने में देरी नहीं की। इससे मुख्यमंत्री ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी नई सरकार में ड्राइवर का भी महत्व है। आम जनता के साथ जो अफसर बदतमीजी करेगा, उनकी सरकार में यह बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार का मतलब जनता की सरकार है और अधिकारी को जनता का सम्मान भी करना होगा। संवेदनशील मुखिया का ऐसा भरोसा जनता में भी नई आशा को जगाता है। डॉ. मोहन यादव का स्वभाव ऐसा है कि वह जनता की समस्याओं के प्रति हर पल बेहद संवेदनशील रहते हैं। जनता की सेवा के लिए वह देर रात में भी औचक निरीक्षण करने से भी परहेज नहीं करते। जनता को किसी भी तरह का कष्ट न हो, इसके लिए उनकी मुस्तैदी देखते ही बनती है।

● **कुमार राजेन्द्र**

भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन के लिए कमेटी

मप्र सरकार ने करप्शन और विभागीय अनुपालन के मामले में कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य करप्शन और अनुशासन के मामलों में जांच करना है, और उसकी रिपोर्ट में संभावित कार्रवाई का सुझाव देना है। इस कमेटी के गठन के बाद से यह माना जा रहा है कि मोहन यादव सरकार करप्ट अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस कमेटी में शामिल अधिकारियों की श्रेणी व्यापक है और उनमें विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण अधिकारी शामिल हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि जांच निष्पक्ष और प्रभावी हो। अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार सामान्य प्रशासन विभाग, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश कुमार राजौरा नर्मदा घाटी विकास विभाग, प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव राजस्व विभाग, और सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग उमेश पांडे इस कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी के गठन से एक साफ संदेश मिलता है कि सरकार करप्शन और अनुपालन के मामलों में सख्त एक्शन लेगी। इसके लिए जरूरी है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि विश्वास और न्याय की प्रक्रिया में समानता बनी रहे।

अभी भी नाथ-दिग्गी का दबदबा

कांग्रेस हाईकमान ने भले ही प्रदेश में पार्टी का चेहरा जीतू पटवारी को बनाकर बदल दिया है, लेकिन उन्हें काम टीम कमलनाथ से कराना पड़ रहा है। इसकी वजह है उनके प्रदेशाध्यक्ष बनने के एक माह बाद भी वे अब तक प्रदेश संगठन में किसी भी पद पर एक भी नियुक्ति नहीं कर सके हैं। आलम यह है कि पटवारी की कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का दबदबा है। गौरतलब है कि पार्टी ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह द्वारा तैयार की गई रणनीति के आधार पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद भी यह दोनों वरिष्ठ नेता अब भी प्रदेश में दखल रख रहे हैं। दरअसल इन दोनों ही नेताओं की अपने-अपने नेता पुत्रों को राजनीति में पूरी तरह से स्थापित करने की इच्छा है। वे इसके लिए पहले भी प्रयास करते रहे हैं, और प्रयास अब भी जारी रखे हुए हैं। भले ही कमलनाथ के पास अब पार्टी का कोई बड़ा दायित्व नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उनके द्वारा जिस तरह से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश को प्रसारित किया गया, उससे यह तय माना जा रहा है कि वे अब भी प्रदेश की राजनीति से दूर नहीं होना चाहते हैं। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता कर जिस तरह से ईवीएम और वीवीपेट को लेकर आरोप लगाए उसके भी मायने निकाले जा रहे हैं।

हालांकि पटवारी के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद माना जा रहा था कि उनके द्वारा प्रदेश पदाधिकारियों की नई टीम बनाई जाएगी, जिसमें युवाओं को तरजीह देते हुए, उन्हें अधिक मौका दिया जाएगा। इसकी वजह थी उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करते ही प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग करने की घोषणा करना। इस दौरान उनके द्वारा पार्टी के मोर्चा विभागों और पूर्व गठित जिला कार्यकारिणियों को भंग करने की जगह पूर्व की तरह काम करने को कहा गया था। अब प्रदेश अध्यक्ष पद पर जीतू पटवारी की नियुक्ति को करीब डेढ़ माह का समय होने जा रहा है, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। इसकी वजह से माना जा रहा है कि अब शायद ही लोकसभा चुनाव के पहले वे अपनी नई टीम का गठन कर पाएं। इसकी वजह से उन्हें लोकसभा चुनाव में भी पुरानी टीम से ही काम चलाना पड़ेगा। अहम बात यह है कि अब भी पार्टी के नेता प्रदेश कार्यकारिणी भंग होने के बाद भी अपने नामों के साथ पूर्व के पदों का उल्लेख करने में पीछे नहीं रह रहे हैं। उधर, इसकी वजह से कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति प्रदेश में तब बनी हुई है, जबकि भाजपा पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के मोड में आ चुकी है। भाजपा अपने मैदानी स्तर तक के संगठन को पूरी तरह से चुनाव के लिए सक्रिय कर चुकी है। इसके उलट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अभी प्रदेश कार्यकारिणी तक का गठन नहीं कर सके हैं। माना जा रहा है कि अगले माह के पहले पखवाड़े के बाद कभी भी लोकसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस को बगैर प्रदेश कार्यकारिणी के ही चुनावी समर में उतरना होगा। ऐसे में पार्टी का काम कैसे होगा समझा जा सकता है। इस तरह की स्थिति में पार्टी को उन्हीं जिला इकाईयों के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ना होगा, जिनके नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरी थी और उसे हार का सामना करना पड़ा है।

जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी हाईकमान ने तीन युवा चेहरों को प्रदेश में कमान सौंपी है, उससे यह तो साफ हो गया है कि कांग्रेस प्रदेश में भाजपा की तरह पीढ़ी परिवर्तन करना चाहती है। प्रदेश में जहां जीतू पटवारी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है, वहीं उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही यह भी माना जाने लगा है कि प्रदेश में वृद्ध हो चुकी कांग्रेस की पीढ़ी के दिन अब लदने वाले हैं। दरअसल पार्टी में अब तक प्रदेश में उम्रदराज हो चुके नेताओं के पास ही महत्वपूर्ण पद रहे हैं। नए पदाधिकारियों की घोषणा न होने से अभी प्रदेश में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी ही पार्टी में कामकाज कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जब भी पटवारी अपनी टीम बनाएंगे, उसमें नए और युवा चेहरों को भरपूर मौका दिया जाएगा। इसमें युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के नेताओं को तबज्जो मिलने की उम्मीद है।

● **अरविंद नारद**

कमलनाथ की जिद के आगे बौने पड़े जितेंद्र और जीतू

वक्त है बदलाव का यह स्लोगन कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दरमियान जारी किया था। स्लोगन का असर न तो मतदाताओं पर पड़ा और न ही कांग्रेस जनों पर दिखाई दे रहा है। अलबत्ता बदलाव के नाम पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई अप्रत्याशित हार के बाद पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को नया अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। नेताओं और कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि अब कांग्रेस में बदलाव होगा पर ऐसा नहीं हो रहा है। कमलनाथ के जमाने के वही पदाधिकारी आज भी महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं। यही कारण है कि प्रदेश प्रभारी महामंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एआईसीसी सदस्य को बहाल नहीं करवा पा रहे हैं। दरअसल, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एआईसीसी सदस्य सिवनी के राजा बघेल को निष्कासित कर दिया था। यह बात अलग है कि एआईसीसी के सदस्य को निष्कासित करने का अधिकार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं है पर कमलनाथ का कद कांग्रेस में इतना ऊंचा है कि पार्टी हाईकमान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तक बौने नजर आते हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी हाईकमान से लेकर प्रदेश के मुख्य प्रभारी जितेंद्र सिंह तक ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लिखित और मौखिक आदेश देने के बाद भी आज तक राजा बघेल की बहाली नहीं हो पाई है।

कागजों पर नहरों का जाल

मप्र में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की भर्राशाही और लापरवाही किसानों की परेशानी का सबब बन गई है। दरअसल, विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई हैं। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के दावों के अनुसार प्रदेश में नहरों का जाल बिछा हुआ है। लेकिन विडंबना यह है कि कई जगह किसानों के खेतों तक नहर ही नहीं पहुंची है। वहीं जहां नहर पहुंची है, वह कहीं भी और कभी भी टूट जा रही है। इससे किसान परेशान हैं। किसानों की परेशानी और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की नाकामी को लेकर लोकायुक्त में शिकायत की गई है।

गौरतलब है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए), सरकार का एक संगठन है। नर्मदा बेसिन में जल संसाधन विकास की योजना बनाने और परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मप्र सरकार का गठन किया गया। लेकिन एनवीडीए की नाकामी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। यह स्थिति तब है जब सरकार प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ने के बड़े-बड़े दावे करती रही है। लेकिन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने केवल कागजों पर ही मजबूत और सुव्यवस्थित नहरों का जाल दिखा रहा है, जबकि हकीकत उससे काफी अलग है। खेतों में सिंचाई के लिए किसान पूर्णतः नहरों पर आश्रित है, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते कई नहरों से पानी व्यर्थ बह रहा है, तो कहीं पर किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं।

मप्र की ओंकारेश्वर परियोजना के तहत नहरों का निर्माण किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की नाकामी की वजह से किसानों के खेत पानी को तरस रहे हैं। नहर टूटी पड़ी है, काम पूरा नहीं किया गया, लेकिन ठेकेदार का भुगतान पूरा कर दिया गया है। तमाम शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई, उल्टे उन्हें उपकृत किया जा रहा है। कार्रवाई के लिए अब मामले की शिकायत लोकायुक्त से की गई है। लोकायुक्त में शिकायत भोपाल के अरविंद मिश्रा ने की है। शिकायत में कहा गया है कि विभाग स्तर पर ओंकारेश्वर परियोजना की नहर को लेकर कोई सुनने वाला नहीं है। ऊपर से नीचे तक बहुत सारी शिकायतें की गई हैं, लेकिन किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा है। यह नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की नाकामी का नतीजा है। करोड़ों रुपए की लागत से नहर बनाई गई, लेकिन किसानों के निकलने के लिए नहर पर डामरीकरण सड़क नहीं बनाई गई। वंशावली नदी के एक्वाडक्ट के पास नहर का लेवल खराब होने से पानी व्यर्थ बह रहा है। खमलाय व वंशावली के बीच और बड़गांव रोड से अरिहंत नगर तक नहर का लेवल खराब है। खमलाय से लगाकर अमलाथा व बाड़ी के बीच नहर में लीकेज है। कसराड नाले पर पुल बनना था। वहां नीचे से पाइप डालकर पानी की निकासी के लिए रास्ता बनाना था। कई स्थानों पर पुलिया बनानी थी, लेकिन पाइप डालकर पानी की निकासी का रास्ता बना दिया गया। मोगावा रोड से मंडलेश्वर रोड तक और अरिहंत नगर से डोंगरगांव तक नहर का साइज छोटा बनाया। कई जगह रास्ते नहीं बनाए। डोंगरगांव से बालसमुद तक नहर बनी ही नहीं है।

ओंकारेश्वर परियोजना को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे। इन दावों पर विश्वास करते हुए किसानों ने भी बड़े-बड़े सपने देखे थे। लेकिन किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचा है। उल्टे परियोजना की राशि जरूर पानी में बह गई है। कमांड एरिया की 25 से 30 किमी की नहर के जरिए किसान 16 साल से पानी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि नहर का निर्माण तत्कालीन अधीक्षण यंत्री हृदयराम चौहान के कार्यकाल में किया गया था। प्राधिकरण द्वारा समस्त तकनीकी एवं गुणवत्ता युक्त कार्य के लिए चौहान को अधिकृत किया गया था, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से भी की गई है। शिकायत में कहा गया है कि गुणवत्ता की कमी व भ्रष्टाचार के चलते ओंकारेश्वर परियोजना की नहरों का पानी क्षेत्र के किसानों को नहीं मिल रहा है। तकरीबन 30 किमी लंबी नहर सूखी पड़ी है। करीब 10 हजार किसान व 30 हजार एकड़ भूमि को इसका पानी नहीं मिल पा रहा है। नहर का 25 से 30 प्रतिशत काम अधूरा है। फिर भी अधिकारियों की मिलीभगत से नहर बनाने वाले ठेकेदार को राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया। यहां तक की सिक्योरिटी की राशि भी निकालकर दे दी है। अनुबंध के अनुसार 2008 तक काम पूरा होना था। तय अवधि में काम नहीं होने के बाद भी कभी पेनाल्टी नहीं लगाई गई। मजेदार बात तो यह कि चौहान के कार्यकाल में की गई गड़बड़ी सामने आने और तमाम शिकवा-शिकायतों के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब उन्हें उपकृत जरूर कर दिया गया है। चौहान अभी इंदिरा सागर परियोजना (नहर) सनावद में प्रभारी मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत थे। तकरीबन आठ दिन पहले उन्हें वर्तमान दायित्व के साथ सदस्य (अभियांत्रिकी) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल के रिक्त पद पर अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है।

● **प्रवीण सक्सेना**

नहर के लीकेज से फसलें हो रही खराब

ओंकारेश्वर परियोजना के तहत बनी नहरों का हाल यह है कि कहीं पानी ओवर फ्लो या लीकेज हो रहा है और कहीं पानी पहुंच ही नहीं रहा है। परियोजना के तहत मुख्य नहर में पानी आने से किसानों को बेहतर फसल उत्पादन की आस बंधी थी, लेकिन यह पानी अब किसानों के लिए अभिशाप बन गया है। ग्राम टवलाई के समीप कुछ किसानों के खेतों में माइनर नहर के लीकेज होने से पानी खेतों में भर जाता है। इससे खेत तालाब में तब्दील हो जाते हैं। इससे उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। किसान नरेंद्र जायसवाल का कहना है कि मुख्य नहर से माइनर नहर में जो पानी छोड़ा जा रहा है, वह नहर से फूटकर खेतों में आ रहा है। इससे खेतों ने दल-दल का रूप ले लिया है। आसपास के कई खेत जिनमें गेहूं, चना व अन्य फसल बो रखी है, वे अब तालाब में तब्दील हो गए हैं। इसको लेकर दो से तीन बार मनावर के राजस्व और एनवीडीए अधिकारियों से मौखिक शिकायत की गई, लेकिन कोई भी जिम्मेदार मौके पर झांकने नहीं आया। विभाग की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि माइनर नहर कई जगह से लीकेज हो रही है और निर्माण के बाद से ही इसकी मरम्मत नहीं हुई है। पानी के रास्ते में कई जगह जंगली झाड़ियां और घास निकल आने से बहाव अवरूद्ध हो रहा है और पानी खेतों सहित आम रास्तों पर इधर-उधर बह रहा है।

2 के भरोसे सूचना आयोग

जिस आयोग के जिम्मे लोगों को जनहित की सूचनाएं दिलाना है, वह सूचना आयोग इस समय दम तोड़ता हुआ नजर आने लगा है। इसकी वजह है आयोग में 11 आयुक्तों में से महज अब दो आयुक्तों का ही रह जाना। आश्चर्यजनक तो यह है कि जब से आयोग गठित हुआ है, तब से लेकर आज तक आयोग के लिए तय सभी पद पूरी तरह से नहीं भरे गए हैं। इससे समझा जा सकता है कि सूचना आयोग को लेकर सरकारें कितनी गंभीर रही हैं। अब प्रदेश में नई सरकार बन चुकी है, लिहाजा माना जा रहा है कि मोहन सरकार जल्द ही रिक्त पदों में से कुछ पदों पर आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है।

आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाले आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस आयोग के हाल अभी यह हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा सिर्फ आयुक्त का एक ही पद भरा हुआ है, जबकि शेष 9 आयुक्त के पद रिक्त चल रहे हैं। रिक्त पदों पर अगर जल्द ही नियुक्ति नहीं की जाती है तो 20 मार्च के बाद सूचना आयोग के सभी प्रमुख पद रिक्त हो जाएंगे। दरअसल, मप्र राज्य सूचना आयोग में मुख्य सचिव आयुक्त समेत आयुक्त के कुल 11 पद हैं। आयोग के गठन से लेकर अभी तक 7 से अधिक पद कभी भी नहीं भरे गए हैं।

गौरतलब है कि पूर्व की शिवराज सरकार में रिक्त पदों को भरने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने ऑनलाइन आवेदन बुलाए थे। जिसमें 135 से ज्यादा आवेदन आए थे। आवेदन करने वालों में सेवानिवृत्त अधिकारी, पत्रकार एवं अन्य लोग भी शामिल हैं। इन आवेदनों को बुलाने के बाद सरकार ने इन पर गौर ही नहीं किया, जिसकी वजह से कार्यरत आयुक्तों का कार्यकाल समाप्त होता गया और पद रिक्त होते चले गए। मौजूदा कार्यरत आयुक्तों में शामिल मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद शुक्ला और आयुक्त राहुल सिंह का भी कार्यकाल 20 मार्च को पूरा हो जाएगा। यदि इससे पहले सरकार ने नियुक्ति नहीं की तो फिर सूचना आयोग में कोई भी आयुक्त नहीं बचेगा।

पूर्व की शिवराज सरकार ने ढाई महीने पहले चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले 9 अक्टूबर 2023 को सुबह 9 बजे सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक बुलाई थी। इसको लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने सवाल उठाते हुए मनमानी बताया था और न्यायालय की शरण में जाने की बात भी कह दी थी। उन्होंने बैठक में आने से भी इनकार कर दिया था। इसके कारण यह बैठक निरस्त कर दी गई थी। इसी दिन चुनाव आयोग ने मप्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया था।

मप्र राज्य सूचना आयोग को प्रभावी बनाने में मप्र सरकार की कतई रूचि नहीं है। देश की सूचना आयोग की सबसे खराब स्थिति मप्र की है। आयुक्तों के अलावा कार्यालयीन अमला भी पर्याप्त नहीं है। आयोग के गठन के बाद 2005 में राज्य तिलहन संघ के कर्मचारियों को मर्ज किया गया था। उनमें से ज्यादातर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब आउटसॉर्स से काम चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि आयोग में विधि विशेषज्ञ भी नहीं है। एक साथ 5 से ज्यादा आयुक्तों की नियुक्ति कभी भी नहीं की गई। आयोग में अन्य सुविधाओं पर भी सरकार का ज्यादा ध्यान नहीं है। यदि सरकार ने सूचना आयोग में जल्द नियुक्ति नहीं की तो फिर आयोग के जरिए सूचनाएं ही मिलना बंद हो जाएंगी। फिलहाल सरकार का रवैया ढुलमुल बना हुआ है। प्रदेश में नई सरकार का गठन होने की वजह से अब सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सरकार को नए सिरे से विज्ञापन जारी कर आवेदन बुलाने होंगे। इसके बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार पूर्व सरकार के समय ऑनलाइन बुलाए गए आवेदनों के आधार पर नई सरकार में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। फिलहाल सूचना आयोग आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई हलचल नहीं दिख रही है।

नवंबर 2021 में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आवेदन बुलाए थे। 121 दावेदारों ने आवेदन किए। इनमें रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, कई रिटायर्ड जज से लेकर पत्रकार भी शामिल हैं। लेकिन आवेदन जमा होने के पूरे डेढ़ साल बाद भी कोई नई नियुक्ति नहीं हो सकी है। राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से जीएडी के अधीन हैं। इसमें आयोग का कोई दखल नहीं हैं। सतर्क नागरिक संगठन के मुताबिक मप्र में अपीलों के निराकरण की रफ्तार को देखा जाए, तो मौजूदा अपीलों के निपटारे में अभी 8 महीने का वक्त लगेगा। नई अपीलों की सुनवाई का नंबर इनके बाद ही आ सकेगा। अफसरों पर पेनाल्टी लगाने के मामले में कर्नाटक देशभर में अव्वल है। कर्नाटक ने 1265 अफसरों पर 1.04 करोड़ की पेनाल्टी एक साल में लगाई है। हरियाणा 161 अफसरों पर 38.81 लाख के साथ मप्र के बाद तीसरे स्थान पर है।

● **रजनीकांत पारे**

सूचना छिपाने में मप्र दूसरे नंबर पर

गौरतलब है कि सूचना के अधिकार के तहत जनहित से जुड़ी जानकारियां देने में जानबूझकर लापरवाही के मामले में मप्र के अफसर कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पर हैं। बीते एक साल में आरटीआई एक्ट के उल्लंघन पर मप्र के 222 अफसरों पर 47.50 लाख रुपए की पेनाल्टी राज्य सूचना आयोग ने लगाई है। पेनाल्टी की यह राशि 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 के बीच की है। यह राशि कर्नाटक के बाद सर्वाधिक है। सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली संस्था सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में मप्र में आरटीआई में जानकारी नहीं दिए जाने की 9005 शिकायतें और अपीलों का निराकरण किया गया हैं। वहीं इस अवधि में 8413 नई सेकंड अपीलें भी दायर हुई हैं। वर्तमान में आरटीआई की 5929 सेकंड अपीलें राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं।

राम वनगमन पथ परियोजना लेगी आकार

अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना के बाद अब राम वनगमन पथ परियोजना की चर्चा भी प्रारंभ हो गई है। दरअसल, यह वह मार्ग है जिस पर अयोध्या से श्रीलंका तक राम, लक्ष्मण और जानकी वनवास के समय चले थे। 2015 में केंद्र सरकार ने रामायण सर्किट नाम से एक परियोजना बनाकर भगवान राम से जुड़े 21 स्थानों को पर्यटन के एक कॉरिडोर से जोड़ने और तीर्थों के विकास की योजना बनाई थी। राम से जुड़े जिन ऐतिहासिक स्थलों की पहचान की गई उनमें उप्र में पांच, मप्र में तीन, छत्तीसगढ़ में दो, महाराष्ट्र में तीन, आंध्रप्रदेश में दो, केरल में एक, कर्नाटक में एक, तमिलनाडु में दो और श्रीलंका में एक स्थान शामिल था। जिन तीर्थों की पहचान की गई थी उनकी संख्या 248 थी।

केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए 13 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए थे। यदि केंद्र की यह परियोजना साकार होती है तो भारत में न केवल पर्यटन को बल्कि आर्थिक तंत्र को भी मजबूती मिलेगी। वर्तमान में कई राज्यों में रामायण सर्किट और राम वनगमन परियोजना से जुड़े विकास कार्य चल रहे हैं किंतु निर्माण स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं है। कहीं परियोजना राजनीति का शिकार हुई तो कहीं सरकारी बाबुओं ने फाइल दबा ली। राम वनगमन परियोजना के अंतर्गत उप्र में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र सरकार की सहायता से नया नेशनल हाईवे बनाकर अयोध्या को चित्रकूट से जोड़ने का काम शुरू किया है। यह वही सड़क होगी जहां से होते हुए राम ने अयोध्या से चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया था। 210 किलोमीटर लंबा यह राम वनगमन मार्ग अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जेठवारा, श्रृंगवेरपुर, मंझनपुर और राजापुर के माध्यम से अयोध्या को चित्रकूट से जोड़ता है। वहीं राज्य सरकार द्वारा चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत और मंदिर पर भी सुविधाओं का विकास किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाते हुए अयोध्या से चित्रकूट के बीच के तीर्थों को विकसित किया जा रहा है।

उप्र सरकार ने भगवान राम के जनकपुर जाने और वहां से माता सीता को लेकर आने के मार्ग को रामायण सर्किट और स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित करने का खाका तैयार किया है। लेकिन चित्रकूट के बाद जहां से मप्र की सीमा शुरू होती है वहां यह परियोजना अधर में लटकी हुई है। 2007 में पहली बार मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम वनगमन पथ के निर्माण का ऐलान किया और इस परियोजना को आध्यात्म एवं आनंद विभाग के अंतर्गत सौंप दिया। शिवराज सिंह स्वयं इस विभाग के मुखिया थे। 2008 में संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार बैठक लेते हुए विद्वानों की समिति का गठन कर शोध कार्य करने का खाका तैयार किया किंतु सरकार की उदासीनता के चलते अगले 7 वर्षों तक परियोजना फाइलों में दबी रही।

2015 में केंद्र सरकार ने रामायण सर्किट का ऐलान किया तो तत्कालीन शिवराज सरकार ने प्रदेश की राम वनगमन परियोजना को रामायण सर्किट में शामिल करा लिया ताकि परियोजना की 40 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार से प्राप्त हो सके। इसके बाद राम वनगमन परियोजना को केंद्र की रामायण सर्किट योजना में मर्ज कर संस्कृति मंत्रालय को सौंप दिया गया। 2018 में कमलनाथ सरकार ने परियोजना को धर्मस्व विभाग को सौंपते हुए 22 करोड़ रुपए स्वीकृत करते हुए 600 करोड़ रुपए की योजना का खाका तैयार किया किंतु काम आगे बढ़ता, इससे पहले ही कमलनाथ सरकार गिर गई। 2020 में शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के पश्चात परियोजना को पुन: संस्कृति मंत्रालय को सौंप दिया और 2023 के विधानसभा चुनाव से पूर्व राम वनगमन पथ ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया। भाजपा चुनाव जीती और डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही ट्रस्ट गठन के 7 महीने बाद चित्रकूट में पहली बैठक ली। हालांकि ट्रस्ट में शामिल 33 सदस्यों में से 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। वर्तमान में परियोजना का यह हाल है कि इसे फाइलों से जमीन पर उतारने में भी एक वर्ष से अधिक का समय लगने वाला है।

गौरतलब है कि मप्र में राम वनगमन परियोजना तीन चरणों में पूरी होना है जिसमें प्रथम चरण में चित्रकूट के कामदगिरी परिक्रमा पथ को विकसित किया जाना है। द्वितीय चरण में चित्रकूट में ही 84 कोसी परिक्रमा पथ के विकास का रोडमैप तय है और तृतीय चरण में श्रीराम के वनवास के समय के मार्ग को विकसित करना है। मप्र से ज्यादा बेहतर स्थिति छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है। वनवास का अधिकांश समय उन्होंने यहीं व्यतीत किया था। यहां की लोक गाथाओं में श्रीराम के वनवास के वर्षों का जिक्र मिलता है।

● **विकास दुबे**

रामायण सर्किट परियोजना में शामिल

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने यहां श्रीराम के मार्गों को चिन्हित करते हुए राम वनगमन परिपथ परियोजना को केंद्र की रामायण सर्किट परियोजना में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था किंतु इसे मंजूरी नहीं मिली तो तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने अपने दम पर इस परियोजना का काम आगे बढ़ाया। परियोजना के लिए 75 स्थलों की पहचान की गई, जहां श्रीराम के चरण पड़ने के साक्ष्य मिले हैं। परियोजना के प्रथम चरण में 9 स्थानों का विकास हो चुका है जिनमें सीतामढ़ी-हरचौका (कोरिया) में 7 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से राम वाटिका के अलावा श्रीराम की विशाल प्रतिमा, सियाराम कुटीर, रामायण व्याख्या केंद्र, कैफेटेरिया, पर्यटक सूचना केंद्र आदि का निर्माण पूर्ण हो चुका है। रायपुर जिले के चंदखुरी के कौशल्या मंदिर में श्रीराम बाल रूप में अपनी माता की गोद में विराजमान हैं। मंदिर को भव्य स्वरूप दिया गया है। वहीं रामगढ़ में श्रीराम की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई है तो जांजगीर-चांपा में सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। लोक मान्यता है कि यहीं राम-लक्ष्मण ने माता शबरी के जूठे बेर खाए थे। इसके अलावा राजिम, धमतरी, सुकमा, जगदलपुर, बलौदाबाजार में विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। हालांकि यहां भी परियोजना भाजपा-कांग्रेस की राजनीति का शिकार रही है और सरकार बदलने के बाद इसकी गति इसका भविष्य तय करेगी।

राम मंदिर उद्घाटन के बाद से ही भाजपा लगातार मास्टर स्ट्रोक खेल रही है और विपक्षी खेमे को नैरेटिव की लड़ाई में हराने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। इन प्रयासों में काफी हद तक सफल भी दिख रही है। भाजपा जानती है कि नैरेटिव की लड़ाई जीतना भी उतना ही जरूरी है, जितना चुनावी मैदान में विपक्ष को हराना। मोदी और राम मंदिर की लहर तो चल ही रही है, लेकिन सीटों का टारगेट छूकर नए रिकॉर्ड बनाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है।

जाटों पर फोकस, साउथ पर नजर...

चुनावी साल में भारत रत्न दिए जाने का नया रिकॉर्ड बन गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 17 दिन के भीतर पांच शख्सियतों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। गत दिनों खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर सिलसिलेवार तीन पोस्ट किए। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही महान वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया। एक दिन में तीन भारत रत्न की घोषणा किए जाने से चुनावी माहौल में चर्चाएं भी तेज हो गईं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया था। ये ऐलान कर्पूरी ठाकुर की जयंती से ठीक एक दिन पहले किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 3 फरवरी को पूर्व उपप्रधानमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की। चुनावी साल में पांचों भारत रत्न के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं।

राम मंदिर उद्घाटन के बाद से ही भाजपा लगातार मास्टर स्ट्रोक खेल रही है और विपक्षी खेमे को नैरेटिव की लड़ाई में हराने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। इन प्रयासों में काफी हद तक सफल भी दिख रही है। भाजपा जानती है कि नैरेटिव की लड़ाई जीतना भी उतना ही जरूरी है, जितना चुनावी मैदान में विपक्ष को हराना। मोदी और राम मंदिर की लहर तो चल ही रही है, लेकिन सीटों का टारगेट छूकर नए रिकॉर्ड बनाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि भाजपा 2019 में जिन सीटों पर कम वोटों के अंतर से चुनाव हारी थी, वहां दो साल से फोकस कर रही है। जिन राज्यों में खुद को कमजोर पाती है, वहां क्षेत्रीय दलों से हाथ मिलाने में पीछे नहीं हट रही है।

पश्चिमी उप्र में क्लीन स्वीप की तैयारी

भाजपा इस बार पश्चिमी उप्र की सभी 24 सीटें जीतना चाह रही है। इसके लिए आरएलडी से अलायंस हो गया है। तय फॉर्मूले के मुताबिक आरएलडी 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये दो सीटें बागपत और बिजनोर होंगी। इसके अलावा जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को एक राज्यसभा सीट भी दी जाएगी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के भाजपा के कदम को जाट समुदाय तक पार्टी की पहुंच के रूप में देखा जा रहा है। इसी वोट बैंक की बदौलत जाटों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह 2 बार उप्र के मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, उपप्रधानमंत्री और फिर देश के पांचवें प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए थे। वैसे तो जाट समुदाय की आबादी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रभावी है, लेकिन खासकर उप्र के पश्चिमी जिलों में स्थिति बेहद मजबूत है। उप्र में जाट प्रभाव वाले जिलों में मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बदायूं का नाम शामिल है। कुछ समय बाद हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव हैं। आरएलडी का साथ मिलने से पार्टी को वहां भी जाट समुदाय को साधने में मदद मिलेगी।

सबसे पहले बात बिहार की। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को बड़ा समाजवादी चेहरा माना जाता है। ठाकुर को जननायक के रूप में भी पहचान मिली है। वे बिहार में आज भी अपनी सरलता और सादगी के लिए जाने जाते हैं। जदयू प्रमुख नीतीश ठाकुर लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठा रहे थे। भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से एक दिन पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा करके इंडिया ब्लॉक में भी तोड़फोड़ कर दी है और इस विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार जदयू प्रमुख नीतीश कुमार को वापस अपने पाले (एनडीए) में कर लिया। इतना ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर के जरिए भाजपा ने चुनावी जीत का ताना-बाना भी बुन लिया। बिहार में ओबीसी का बड़ा वर्ग कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानता है। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया तो आरजेडी को भी केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना पड़ा। चुनाव से पहले के सर्वे भी बता रहे हैं कि नीतीश की वापसी के बाद एनडीए और मजबूत हुआ है और भाजपा को बिहार साधने के लिए बड़ा चेहरा मिल गया है।

इधर, 22 जनवरी को अयोध्या में पूरे देश के हिंदू समुदाय की 500 साल पुरानी मुराद पूरी हुई है। नए राम मंदिर में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा हो गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन तक कठोर व्रत और नियमों का पालन किया। राम मंदिर उद्घाटन के 10 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मोदी ने आडवाणी के कामों को याद किया और देश के विकास में उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। आडवाणी को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने अपने संगठन को भी मैसेज दिया और यह बताया कि भाजपा में हर

किसी के सम्मान का ख्याल रखा जाता है। आडवाणी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न दिया गया था।

भाजपा की पॉलिटिक्स के केंद्र में हिंदू कोर वोटर्स हैं। राम मंदिर का श्रेय भी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। लेकिन, इसके पीछे सालों की मेहनत और बड़े आंदोलन को नहीं भुलाया जा सकता। 1990 के दशक में इस आंदोलन के अगुवा और भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी रहे। राम मंदिर को लेकर जब रथयात्रा निकाली गई तो उसे सफल बनाने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में थी। आडवाणी गुजरात से चुनाव लड़ते रहे हैं और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का गुरू माना जाता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर इसका जिक्र कर चुके हैं। साल 2002 के गुजरात दंगों के वक्त जब मोदी की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर आंच आई, तो आडवाणी उनके लिए ढाल बनकर खड़े हो गए थे। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी मतभेद हो गए थे।

महान वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन को भी मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। डॉ. स्वामीनाथन को देश में हरित क्रांति लाने का जनक माना जाता है। इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दरअसल, जब देश आजाद हुआ, तब भूख और अकाल जैसे हालात थे। अंग्रेज देश को खोखला छोड़ गए थे। 1960 के दशक के मध्य में देश भयंकर सूखे से त्रस्त हो गया था। ना खाने को अनाज था, ना पीने के लिए ठीक से पानी। सिंचाई के लिए व्यवस्था दूर की कौड़ी थी। ऐसे में हमारा देश अनाज के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर हो गया था। पश्चिम बंगाल में भीषण अकाल पड़ने से लाखों लोग मारे गए। देश में खाद्यान्न संकट बढ़ता जा रहा था। उस समय गांधीवादी वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन ने धान की ज्यादा उपज देने वाली किस्में विकसित कीं। इससे कम आय वाले किसानों के घर खुशियां आ गईं और ज्यादा पैदावार करने का एक जरिया मिल गया। देश में वही हरित क्रांति थी। उसके बाद देश के किसानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

तमिलनाडु के चेन्नई में जन्मे हरित क्रांति के जनक डॉ. एमएस स्वामीनाथन ऐसी शख्सियत हैं, जिनका देश में आज भी पूरा वैज्ञानिक समुदाय सम्मान करता है। वे तमिलनाडु की शान माने जाते हैं और लोगों की उनसे भावनाएं जुड़ी हैं। स्वामीनाथन के जरिए भाजपा ने दक्षिण भारत में अपनी पैठ मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दक्षिण भारत के राज्यों में भाजपा गठबंधन के लिए सहयोगी दलों की तलाश में है। कर्नाटक में जेडीएस के साथ भाजपा का गठबंधन हो चुका है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके से रिश्ता टूटने के बाद भाजपा अब वहां छोटे दलों को साथ लाना चाह रही है। 2019 के चुनाव में भाजपा का तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ अलायंस था और 30 फीसदी से ज्यादा वोट हासिल किए थे। इस बार भाजपा को वहां सर्वे में बड़ा झटका लगने का अनुमान है।

पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नरसिम्हा राव को देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने वाला नेता बताया है। पीवी नरसिम्हा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा के सदस्य के रूप में भी रहे हैं। उन्हें 1991 में देश को आर्थिक संकट से निकालने का श्रेय भी दिया जाता है। वे लगातार 8 बार चुनाव जीते और कांग्रेस में 50 साल से ज्यादा समय तक काम किया। राजनीतिक लिहाज से देखें तो पीवी नरसिम्हा राव को देश की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था। वे 10 भाषाओं में बातचीत करने में मास्टर माने जाते थे। उनका जन्म आंध्रप्रदेश में हुआ और पढ़ाई तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुई। दोनों राज्यों की राजनीति में प्रभावशाली भी बने रहे। राव को 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए भी अपनी ही पार्टी में आलोचना का सामना करना पड़ा था।

एक और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। पश्चिमी उप्र में जाट और किसानों के बीच चौधरी साहब की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। चौधरी चरण सिंह की विरासत को पहले उनके बेटे चौधरी अजित सिंह ने आगे बढ़ाया। अब अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी सियासी विरासत को आगे ले जा रहे हैं। आम चुनाव से पहले पश्चिमी उप्र में जाट, किसान और मुसलमानों को साधने की कवायद चल रही है। वैसे तो पिछले दो चुनावों में भाजपा जाटलैंड में छाई है। लेकिन वो इस बार क्लीन स्वीप के मूड में है और यही वजह है कि भाजपा ने जयंत की पार्टी आरएलडी को भी एनडीए में लाने के लिए हर शर्त पर मुहर लगा दी है। जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुई तो सबसे पहले जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट को रीट्वीट किया और लिखा- दिल जीत लिया।

● श्याम सिंह सिकरवार

साउथ के राज्यों पर भाजपा का फोकस

भाजपा लगातार साउथ को लेकर मिशन मोड में काम कर रही है। साउथ में फिल्म डायरेक्टर एसएस राजामौली को फिल्म आरआरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवॉर्ड दिया गया था। इससे पहले 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तेलुगू सिनेमा ने सबसे ज्यादा 11 नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीते थे। इसका संदेश भी साउथ में सकारात्मक गया था। अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा में बेहतरीन अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। देवी श्री प्रसाद को भी इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला था। दक्षिण भारत के कुछ और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं में कमल हासन, ममूटी, जोजू जॉर्ज का नाम शामिल था। भाजपा ने केरल की रहने वाली एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा सदस्य बनाया था। इसके अलावा, दक्षिण भारत की मान्यताओं को सम्मान देने की दिशा में भी मोदी सरकार ने कदम उठाए। काशी-तमिल संगमम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम देश के उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों के कई पहलुओं का जश्न है। इसका व्यापक उद्देश्य ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं (उत्तर एवं दक्षिण की) को करीब लाना, साझा विरासत की समझ विकसित करना है। इतना ही नहीं, मई 2023 में जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो तमिलनाडु के सदियों पुराने मठ के आधीनम महंतों की मौजूदगी में सेंगोल की स्थापना की गई। दरअसल, सेंगोल राजदंड सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि राजा के सामने हमेशा न्यायशील बने रहने और जनता के प्रति समर्पित रहने का भी प्रतीक रहा है।

नई तकनीक के साथ सड़कों का निर्माण

मप्र में रोड और फ्लाईओवर का जाल बिछाया जाएगा और अगले दो सालों में 17 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट अमल में लाएंगे। जनप्रतिनिधियों के क्षेत्रों में भी लगभग 3 हजार करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विकास कार्य होंगे। लोक निर्माण विभाग को अत्याधुनिक बनाया जाएगा और इसके लिए विभिन्न राज्यों के दौरे भी करवाएंगे और साउथ की तर्ज पर ही सड़कों-पुलों का निर्माण होगा और हर कार्य की लगातार मॉनीटरिंग भी करवाई जाएगी। एफडीआर तकनीक से भी सड़कों के निर्माण करवाने की योजना पर काम किया जा रहा है।

अभी पिछले दिनों ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी मप्र में कई बड़े रोड प्रोजेक्टों का शुभारंभ किया और उन्होंने कहा कि जल्द ही अमेरिका से ज्यादा सड़कों का निर्माण अकेले मप्र में ही हो जाएगा। वहीं लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने भी अधिकारियों की बैठक ली और उसमें आने वाले दो से तीन वर्षों के मुताबिक प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए, जिस पर लगभग 17 हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च होना है। इतना ही नहीं, फूल डेप्त रिक्लेमिनेशन यानी एफडीआर तकनीक से भी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें मौजूदा सड़कों को बिना तोड़े उसके ऊपर ही मशीनों के द्वारा रिक्लेमिनेशन सामग्री के इस्तेमाल से नई और मजबूत रोड निर्मित की जाती है। इसी तरह अन्य राज्यों में जो तकनीक अपनाई जा रही है उसका भी अध्ययन विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों को करवाया जा रहा है। तमिलनाडु और गुजरात की तकनीक का इस्तेमाल सड़कों के पेंचवर्क करने पर किया जा रहा है, जिसके लिए एक जेट पैचर मशीन भी मंगवाई गई है। विदेशों में भी इसी तरह की मशीन की मदद से चंद मिनटों में ही पेंचवर्क यानी गड्ढ़ों की मरम्मत हो जाती है।

अभी पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में अन्य राज्यों में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी जानकारी लेने के निर्देश दिए थे। खासकर साउथ यानी दक्षिणी राज्यों में जिस तरह सड़कों-पुलों के निर्माण में उच्च गुणवत्ता और बेहतर कार्य प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह अब मप्र में भी काम कराए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ सड़क विकास निगम और एमपी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के इंजीनियरों को भी नई तकनीक, परियोजना, वित्त पोषण विकल्प, जनभागीदारी, वार्षिक योजना निर्माण से लेकर अन्य मामलों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह अन्य राज्यों ने जिस तरह की तकनीक इस्तेमाल की, उसकी भी जानकारी जुटाकर तीन माह में रिपोर्ट बनाने को कहा गया है।

दूसरे राज्य की तकनीक से भरे जा रहे गड्ढे

दूसरे राज्यों से सीख लेकर नया करने का सिलसिला पीडब्ल्यूडी ने पिछले साल ही शुरू कर दिया था। सड़कों के गड्ढे भरने के लिए तमिलनाडु व गुजरात की तकनीक का इस्तेमाल किया। विभाग के कैपिटल जोन में पहली बार इस पर अमल किया गया। खास तौर से जेट पैचर मशीन मंगाई। इस मशीन से भोपाल व सीहोर की 185 किमी लंबाई की सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं। विदेशों में विकसित इस मशीन की मदद से गड्ढे की मरम्मत महज पांच मिनट में की जा रही है। इससे लागत आधी रह गई है और समय भी 40 प्रतिशत तक कम लग रहा है। गोवा, गुरुग्राम आदि में भी इस मशीन से सड़कों की मरम्मत की जा रही है। इसके साथ ही खराब सड़कों की शिकायत करने के लिए मोबाइल एप्प लाया जा रहा है। आम आदमी इस पर समस्या बता सकेंगे। इसका निराकरण तय समयसीमा में किया जाएगा। ध्यान देने लायक बात यह है कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों की शिकायत के लिए आसान पहुंच वाली ऐसी कोई व्यवस्था अब तक नहीं थी।

मप्र में सड़क-पुल के निर्माण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सरकार दक्षिण-पश्चिम के कुछ राज्यों की तकनीक अपनाएगी। गौरतलब है कि मप्र में हर साल हजारों किमी सड़कें थोड़ी सी बारिश और भारी वाहनों के दबाव से खराब हो जाती है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र के साथ ही दक्षिणी राज्यों में सड़क, पुल व बिल्डिंग निर्माण की बेस्ट प्रैक्टिसेज को मप्र में लागू किया जाएगा। इसकी स्टडी के लिए चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी की अगुवाई में पांच सदस्यीय टीम महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना व गुजरात का दौरा करेगी। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता कार्यालयों, सड़क विकास निगम और एमपी बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के इंजीनियर टीम में रहेंगे।

गौरतलब है कि सरकार का फोकस है कि लोक निर्माण से लोक कल्याण के संकल्प के साथ कार्य कर मप्र को अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कार्यों के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाई जाए, कार्यों की गुणवत्ता के लिए मॉनीटरिंग की विशेष व्यवस्था के साथ क्वालिटी ऑडिट किया जाए, बड़ी योजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए पृथक सैल गठित किया जाए, योजनाएं विधानसभावार बनाई जाएं, इसके लिए विषय विशेषज्ञों की राय भी ली जाए। कार्यों में पारदर्शिता हो और जनता को इनकी पूरी जानकारी हो।

दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले महीने पीडब्ल्यूडी के कामकाज की समीक्षा की थी। उन्होंने महाराष्ट्र व दक्षिण भारतीय राज्यों में सड़क, पुल व भवन निर्माण व्यवस्थाओं, निर्माण तकनीकों, कार्यप्रणालियों, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रगति निगरानी, वित्तीय प्रबंधन आदि का अध्ययन व तुलनात्मक विश्लेषण करने के निर्देश दिए थे। इन राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेज को चिन्हित कर पीडब्ल्यूडी को प्रस्ताव बनाने के लिए कहा था। इस पर अमल करते हुए पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने पांच सदस्यीय टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। टीम को मुख्यमंत्री के निर्देशों के साथ ही वार्षिक योजना निर्माण, जनभागीदारी परियोजनाओं, परियोजना वित्त पोषण के विकल्प, नई तकनीकों के उपयोग व सड़कों के रखरखाव का विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। साथ ही दूसरे राज्यों में किए अभिनव प्रयासों की अलग से रिपोर्ट बनाने की भी जिम्मेदारी दी है। इसके लिए तीन महीने की समय सीमा तय की है।

● **लोकेश शर्मा**

काबू में नहीं आ रही महंगाई

महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने व्यापारियों से चावल व धान के स्टॉक की जानकारी देने को कहा है। इस आदेश के चलते सभी व्यापारियों व मिलर्स को टूटे चावल, गैर-बासमती सफेद चावल, उबला चावल, बासमती चावल, धान की स्टॉक की ताजा स्थिति सात दिन के भीतर घोषित करनी होगी। साफ है कि सरकार के तमाम प्रयासों के बाद खाद्य वस्तुओं की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्राइस मॉनीटरिंग सेल के मुताबिक 2 फरवरी 2024 को चावल का औसत खुदरा मूल्य 43.96 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो पिछले साल यानी 2 फरवरी 2023 में 38.63 रुपए प्रति किग्रा था। चूंकि कुछ माह बाद ही आम चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार ने चावल की कीमतों पर काबू पाने के लिए व्यापारियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है।

एक ओर सरकार जहां चावल की खुदरा कीमतों पर काबू पाना चाहती है, वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 80 करोड़ गरीबों को राशन भी देना है। हालांकि 2 फरवरी 2024 को सरकार ने दावा किया कि खरीफ विपणन सीजन 2023-24 (खरीफ फसल) के दौरान 600 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद पूरी हो चुकी है, जबकि केंद्रीय पूल में लगभग वार्षिक आवश्यकता के मुकाबले 525 एलएमटी से अधिक चावल है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सभी कल्याणकारी योजनाओं के तहत 400 लाख टन चावल की सालाना आवश्यकता होती है।

व्यापारियों की नकेल कसने से सरकार के दोनों मकसद हल हो सकते हैं। केंद्र सकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारी चाहे थोक हो या खुदरा, प्रोसेसर हो या मिलर्स के स्टॉक पर नजर रखने का निर्णय लिया है। इसके चलते उन्हें हर शुक्रवार को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर स्टॉक की ताजा स्थिति अपडेट करनी होगी। इसके अलावा खाद्य वस्तुओं की महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने आम उपभोक्ताओं के लिए भारत चावल की खुदरा बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में तीन एजेंसियों नैफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के माध्यम से भारत चावल ब्रांड के अंतर्गत खुदरा बिक्री के लिए 5 लाख मीट्रिक टन चावल आवंटित किया गया है। भारत चावल की बिक्री का खुदरा मूल्य 29 रुपए प्रति किग्रा होगा, जिसे 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के बैग में बेचा जाएगा।

भारत चावल शुरुआत में खरीद के लिए मोबाइल वैनों और तीन केंद्रीय सहकारी एजेंसियों की दुकानों से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा, और यह बहुत जल्द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहित अन्य खुदरा श्रृंखलाओं के माध्यम से भी उपलब्ध होगा। सरकार द्वारा जारी बयान में स्वीकार किया गया है कि इस खरीफ में अच्छी फसल, भारतीय खाद्य निगम के पास चावल का पर्याप्त स्टॉक व निर्यात पर विभिन्न नियमों के बावजूद चावल की घरेलू कीमतें बढ़ रही हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले खुदरा कीमतों में 14.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चावल की कीमतों पर अंकुश लगाने के प्रयास में सरकार की ओर से पहले ही कई कदम उठाए जा चुके हैं। सरकार की ओर से बताया गया है कि एफसीआई के पास अच्छी गुणवत्ता वाले चावल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, जिसे व्यापारियों व थोक विक्रेताओं को ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत 29 रुपए प्रति किग्रा के आरक्षित मूल्य पर दिया जा रहा है। खुले बाजार में चावल की बिक्री बढ़ाने के लिए, सरकार ने चावल का आरक्षित मूल्य 3100 रुपए क्विंटल से कम करके 2900 रुपए क्विंटल कर दिया और चावल की न्यूनतम और अधिकतम मात्रा को क्रमश: 1 मीट्रिक टन और 2000 मीट्रिक टन तक संशोधित किया गया। 31.01.2024 तक 1.66 लाख मीट्रिक टन चावल खुले बाजार में बेचा जा चुका है, जो ओएमएसएस (डी) के तहत किसी भी वर्ष में चावल की सबसे अधिक बिक्री है।

टूटे हुए चावल की निर्यात नीति को 1 फरवरी 2017 से मुक्त से निषिद्ध में संशोधित किया गया है। 9 सितंबर, 2022 को गैर-बासमती चावल के संबंध में, जो कुल चावल निर्यात का लगभग 25 प्रतिशत है, 20 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया गया है। इसके बाद गैर-बासमती सफेद चावल की निर्यात नीति को 20 जुलाई 2023 से संशोधित कर निषिद्ध कर दिया गया। उबले चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया गया है जो 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगा। इन सभी उपायों के बावजूद घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में वृद्धि की गति पर अंकुश नहीं लग पाया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग कीमतों को नियंत्रित करने और गेहूं के स्टॉक की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने और गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार 28 जून 2023 से साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं को बाजार में उतार रही है। सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत एफएक्यू के लिए 2150 रुपए क्विंटल और यूआरएस के लिए 2125 रुपए क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर उतारने के लिए कुल 101.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया है।

● **सुनील सिंह**

दुनिया में कम हो रही महंगाई

यहां खास बात यह है कि दुनिया में खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आ रही है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के मुताबिक गेहूं-मक्के के साथ-साथ मांस की कीमतों में आई गिरावट के चलते वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक (फूड प्राइस इंडेक्स) में जनवरी 2024 के दौरान भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतों में उछाल जरूर देखा गया, लेकिन अनाज और मांस की कीमतों में आई गिरावट ने उसकी भरपाई कर दी है। खाद्य कीमतों में आई गिरावट का ही नतीजा है कि जनवरी 2024 में वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक करीब तीन वर्षों के अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर जिन खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है उनको ट्रैक करता है।

जांच पूरी...रिपोर्ट का पता नहीं

मप्र में किसी भी गंभीर घटना की जांच के लिए जिस तत्परता से न्यायिक जांच आयोग गठित होते हैं, उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई में उतनी ही सुस्ती बरती जाती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि आयोगों द्वारा जांच तो पूरी हो चुकी है, लेकिन उनकी रिपोर्ट का अता-पता नहीं है। सन् 2008 से अब तक विभिन्न घटनाओं की जांच के लिए गठित सात आयोगों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन इनमें से एक पर ही कार्रवाई हो पाई है, बाकी ठंडे बस्ते में है। इन्हीं में से एक है पेंशन घोटाले की रिपोर्ट। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हुई गड़बड़ियों की जांच तो सरकार ने न्यायिक आयोग बनाकर करा ली, पर 11 वर्ष बाद भी इसकी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकी है। यह कोई अकेला मामला नहीं है।

मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट भी जून 2018 से गृह विभाग में लंबित है। इसको लेकर न्यायालय में याचिका भी लग चुकी है। इसी तरह भोपाल यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव जांच, गोसपुरा मानमंदिर ग्वालियर की पुलिस मुठभेड़ में हुई जांच की रिपोर्ट पर भी कार्यवाही ही चल रही है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस इस विषय को उठाने की तैयारी में है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में गड़बड़ी की शिकायतों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने जस्टिस एनके जैन आयोग बनाकर जांच कराई थी। प्रदेश में नगरीय निकायों और पंचायतों के माध्यम से हितग्राहियों का सत्यापन कराया गया। इसमें यह बात प्रमाणित हुई कि कई मृतकों के नाम पर पेंशन जा रही थी और इसके वितरण की प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं थी। आयोग की अनुशंसा पर व्यवस्था में सुधार कर सीधे खातों में राशि के अंतरण की व्यवस्था बनाई गई, पर आयोग की रिपोर्ट अब तक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की गई है।

इसी तरह मंदसौर गोलीकांड में मारे गए किसानों की मौत के मामले की जांच के लिए गठित जैन आयोग की रिपोर्ट करीब पांच साल गुजर जाने के बावजूद सार्वजनिक नहीं की गई है। जबकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि आत्मरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिस्थितिवश गोलीचालन की स्थिति बनी थी। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर याचिका भी लग चुकी है। गौरतलब है कि मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में छह जून 2017 को किसान आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने के बाद गोली चालन की घटना हुई थी। इस घटना में पांच किसानों की मौके पर मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए गठित जस्टिस जेके जैन की अध्यक्षता वाली आयोग ने 2018 को राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी। जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के अनुसार शासन का यह दायित्व है कि छह महीने के अंदर जांच आयोग की रिपोर्ट तथा रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर कार्यवाही करे और इस कार्यवाही से राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए 12 जून 2017 विधानसभा को अवगत कराएं। जैन आयोग की ओर से शासन को रिपोर्ट दिए हुए करीब पांच साल का समय हो गया था। लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार ने रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश नहीं की है। इसको लेकर विधानसभा में विधायकों ने अलग-अलग सवाल भी लगाए थे। इस पर सरकार ने जवाब भी अलग-अलग दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बाला बच्चन जांच रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत नहीं करने को लेकर प्रश्न भी उठा चुके हैं, पर सरकार की ओर से यह उत्तर दिया जा रहा है कि कार्यवाही प्रचलन में है।

वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही पूर्ण करने पर रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी। गौरतलब है कि बजट सत्र के दौरान भी कांग्रेस विधायकों ने आयोगों की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। वहीं उन्होंने हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में न्यायिक जांच कराने की मांग भी की।

● **जितेंद्र तिवारी**

सात जांच आयोग में से एक में कार्यवाही

बता दें कि प्रदेश में 2008 से 2017 के बीच घटित हुई गंभीर घटनाओं की जांच के लिए 7 जांच आयोग गठित हुए हैं, जिनमें से एक की ही रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई। बाकी 6 में सरकार का जवाब है कि कार्यवाही प्रचलन में है। जबकि जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3(4) में साफतौर पर कहा गया है कि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार को छह महीने में दोषियों पर कार्यवाही कर रिपोर्ट विधानसभा में रखना जरूरी होगा। अभी तक सरकार ने पेटलावद में मोहर्रम जुलूस को रोके जाने की घटना के लिए गठित जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषियों पर कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन विधानसभा में रखा है। हाल ही में लटेरी गोलीकांड की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया है। विधानसभा में सरकार द्वारा विभिन्न मामलों में दिए जवाब के अनुसार कई आयोगों की रिपोर्ट पर कार्यवाही प्रचलन में है। इनमें नगर निगमों में पेंशन घोटाले की जांच के लिए आयोग 8 फरवरी 2008 को गठित किया गया। जस्टिस एनके जैन आयोग ने रिपोर्ट 15 सितंबर 2012 को सरकार को सौंप दी। मौजूदा स्थिति में सामाजिक न्याय विभाग में कार्यवाही प्रचलन में है। भिंड गोली चालन में 12 जुलाई 2012 को न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। जस्टिस सीपी कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट गृह विभाग को 17 जनवरी 2018 को भेजी गई, तब से कार्यवाही प्रचलन में है। भोपाल यूनियन कार्बाइड में जहरीली गैस रिसाव मामले में जांच आयोग 25 अगस्त 2010 को गठित किया गया। जस्टिस एसएल कोचर ने रिपोर्ट 24 फरवरी 2015 को सौंप दी। इस पर गैस राहत विभाग में कार्यवाही प्रचलित है। आयोगों की रिपोर्ट पर कार्यवाही न होने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले पूर्व विधायक पारस सकलेचा का कहना है कि आयोग का गठन सच्चाई जानने के लिए होता है, लेकिन यहां सरकार इसलिए रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रख रही है जिससे दोषियों के नाम सामने न आ सकें।

नैनो यूरिया पर पूरा भरोसा नहीं

दो हेक्टेयर जमीन पर होगा उर्वरक का प्रयोग

कृषि विज्ञानी डॉ. एकता जोशी का कहना है कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय को बाजारा, चना और सोयाबीन की फसल पर नैनो यूरिया के प्रभाव को देखना है। इसके लिए इन फसलों को दो हेक्टेयर भूमि में बोया गया है। जिस पर मशीन की मदद से नैनो यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है। इसी तरह से दिल्ली की आईआरआई कृषि यूनिवर्सिटी को गेहूं और सरसों की फसल पर शोध करना है। वहीं महाराष्ट्र की दोनों यूनिवर्सिटी में जिन फसलों पर नैनो यूरिया का शोध किया जाना है उन फसलों पर उर्वरक का छिड़काव ड्रोन की मदद से होगा। जिससे इस बात का भी पता चलेगा कि नैनो यूरिया का छिड़काव सामान्य हाथ की मशीन या ड्रोन से करने पर अधिक प्रभावी होगा।

देश में किसानों की सुविधा और पैदावार को देखते हुए सरकार ने नैनो यूरिया को उपयोग के लिए बाजार में उतार दिया है, लेकिन विडंबना यह है कि किसान नैनो यूरिया पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा है। दरअसल, हर साल किसानों की फसलें विभिन्न कारणों से खराब हो रही हैं। ऐसे में वह अपने खेतों में कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, जिसकी कोई प्रमाणिकता न हो। इसको देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने नैनो यूरिया को भरोसेमंद बनाने के लिए उस पर शोध शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि सरकार ने जबसे नैनो यूरिया लॉन्च किया है, तबसे लेकर अब तक कम ही किसान इसका उपयोग कर रहे हैं। जब कृषि मंत्रालय ने इसकी पड़ताल करवाई तो यह बात सामने आई कि किसान इसका उपयोग करने से डर रहे हैं।

फसलों पर नैनो यूरिया के प्रभावों को पता करने के लिए ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय व ईफको सहित आठ इंस्टीट्यूट एवं विश्वविद्यालयों के कृषि विज्ञानी शोध कर रहे हैं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय को बाजरा, चना और सोयाबीन की फसल पर नैनो यूरिया के प्रभाव का पता लगाने की जिम्मेदारी मिली है। अन्य विश्वविद्यालय के विज्ञानी अलग-अलग फसलों पर नैनो यूरिया के प्रभाव व दुष्प्रभाव का पता लगा रहे हैं। यह शोध वर्ष 2025 में पूरा होगा और साइंटिफिक डेटा जनरेट किया जाएगा। यह डेटा स्टेट डिपार्टमेंट, ईफको और केंद्रीय कृषि मंत्रालय को भेजा जाएगा। जिसके बाद किसानों को नैनो यूरिया की उपयोगिता और उसके प्रभाव से अवगत कराते हुए उपयोग करने की सलाह दी जाएगी।

असल में ईफको ने नैनो यूरिया तैयार किया और उसे बाजार में लेकर आ चुका है। लेकिन किसान अभी नैनो यूरिया पर पूरी तरह से भरोसा नहीं जता पा रहे हैं जिसके कारण उसकी उपयोगिता नहीं बढ़ी है। इसी को लेकर अब सरकार ने कृषि विज्ञानियों को नैनो यूरिया के विषय में पूरी पड़ताल करने की जिम्मेदारी दी है। जिससे किसानों को उसके लाभ के विषय में बताया जा सके। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह राष्ट्रव्यापी प्रकल्प है। जिसको लेकर अब भारत सरकार नैनो डीएपी जल्द लेकर आने वाला है। इसके साथ ही मालनपुर में नैनो यूरिया की एक यूनिट लगाने के लिए जगह भी एक कंपनी को आवंटित की गई है।

ग्वालियर की कृषि यूनिवर्सिटी सहित देश की आठ कृषि यूनिवर्सिटी के विज्ञानी फसलों पर नैनो यूरिया के प्रभाव का पता लगाने के लिए शोध कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को तमिलनाडु एग्रीकल्चर कृषि यूनिवर्सिटी नेतृत्व कर रही है। इसके अंतर्गत इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में गेहूं और सरसों पर शोध हो रहा है, क्रीडा हैदराबाद में मक्का और अरहर व जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर उत्तराखंड में धान व सरसों पर शोध होगा। वहीं बसंत राव नायक मराठबाड़ा परभणी महाराष्ट्र में अरहर मक्का, गेहूं पर शोध होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी मोहाली पंजाब में माइक्रो न्यूट्रीयंट्स में बायोलाजिकल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ग्रीनहाउस गैसेस का इम्यूनिशन आदि का पता किया जाएगा। जबकि ग्वालियर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय सरसों चना और सोयाबीन पर शोध हो रहा है इसको ओवर ऑल यूनिवर्सिटी के संपर्क में ईफको रहेगा।

नैनो यूरिया पर चार तरीके से शोध होगा। इसमें सुपर नैनो यूरिया, सुपर नैनो यूरिया के साथ सल्फर, नैनो एनपीके जिसमें नाइट्रोजन पोटाश और फास्फोरस शामिल है। नैनो ट्रेस एलिमेंट्स जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें मैंगनीज मोलीविडनम, कापर, जिंक, आयरन कैल्शियम शामिल है। इनका पौधे की पत्ती और मिट्टी पर तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका पता लगाया जाएगा। नैनो पर जो लोग शोध कर रहे हैं, इसमें ग्वालियर के विज्ञानी डॉ. एकता जोशी, डॉ. सुषमा तिवारी, डॉ. निशांत, डॉ. अंकित साहू और डॉ. प्रियदर्शनी की टीम काम कर रही है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार, नैनो यूरिया का फसल पर छिड़काव में ड्रोन व सामान्य पद्धति के प्रयोग से होने वाले अंतर, फसल पर नैनो यूरिया कैसे काम करता है, नैनो यूरिया से कितने बैग यूरिया रिप्लेस होगा, नैनो यूरिया के प्रयोग बढ़ने से किसान की आय पर क्या प्रभाव होगा, कितनी बचत होगी, फसल की उत्पादकता पर क्या प्रभाव होगा, मिट्टी के स्वास्थ्य, पर्यावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा आदि विषयों पर शोध किया जाएगा। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरविंद शुक्ला का कहना है कि नैनो उर्वरक फसल के लिए कितना प्रभावी है इसका विज्ञानी पता लगा रहे हैं। यह शोध दो साल चलने वाला है। जिसके बाद जो डेटा आएगा उसके आधार पर किसानों को सलाह दी जाएगी। किस फसल पर नैनो यूरिया का प्रयोग किस तरह से करें जिससे लागत कम हो और लाभ अधिक हो।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

1390 करोड़ से संवरेगा मप्र का वन क्षेत्र

मप्र में कैम्पा योजना (क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) के तहत वन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने, वन्य प्राणी प्रबंधन और वन क्षेत्र में भू-जल संरक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। मुख्य सचिव वीरा राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया। प्रदेश के वनों पर 1390 करोड़ रुपए खर्च करने की कैम्पा योजना को राज्य स्तरीय समिति ने हरी झंडी दे दी है।

असल में क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण की वार्षिक योजना को लेकर मुख्य सचिव ने इसमें 1390 करोड़ की योजना का अनुमोदन किया। योजना में बिगड़े वनों को संवारने से लेकर आधुनिक तकनीक और उपकरणों के साथ सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है। 1,82,606 हेक्टेयर में 290 करोड़ से वनों का रखरखाव का काम और 199 करोड़ से 25,694 हेक्टेयर में बिगड़े वनों के सुधार पर विशेष काम। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) महेंद्र सिंह धाकड़ का कहना है कि बीते वर्ष 1070 करोड़ की योजना को राज्य से अनुमोदन और केंद्र से मंजूरी मिली थी। सभी काम हो चुके हैं। इस वर्ष राज्य से 1390 करोड़ की योजना को अनुमोदित किया है, जो बीते वर्ष की तुलना में 320 करोड़ अधिक है। उम्मीद है कि कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी मिलेगी।

चीतों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पहली आधुनिक केयर यूनिट बनाने के प्रस्ताव को भी शामिल किया है। इस पर 65 लाख रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। यह यूनिट गांधीसागर अभयारण्य में बनेगी। इसके अलावा सतना में सवा तीन करोड़ से 30 हेक्टेयर में बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना, 6 करोड़ से राज्य प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को भी शामिल किया है। योजना केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। राष्ट्रीय समिति की स्वीकृति और राशि मिलने के बाद प्रदेश में काम शुरू होगा। आपको बता दें कि पिछले साल देश में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत जहां मप्र से की गई, वहीं अब दूसरे चरण में भी चीतों को मप्र ही लाकर बसाया जाएगा। लेकिन यह जगह कूनो नहीं बल्कि, उनके दूसरे या कहें कि दूसरे घर के रूप में तैयार हो रही है। इन नए चीतों के लिए दूसरा घर मंदसौर के गांधी सागर वन अभयारण्य में बसाया जा रहा है। 30 करोड़ की लागत से 67 वर्ग किमी के क्षेत्र में चीतों का बाड़ा बन रहा है। मंदसौर के इस गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के 67 वर्ग किमी में बाड़ा बनाने का काम पूरे जोर-शोर से जारी है। उम्मीद की जा रही है कि सबकुछ अच्छा रहा तो नए साल में गांधी सागर अभयारण्य में चीते दौड़ते नजर आएंगे।

चंबल नदी के एक छोर पर यह बाड़ा बनाया जा रहा है। यहां 12 हजार 500 गड्ढ़े खोदकर हर तीन मीटर की दूरी पर लोहे के पाइप लगाए हैं। इन पिलर पर तार फेंसिंग के साथ लोहे से 28 किलोमीटर लंबी और 10 फीट ऊंची दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार पर सोलर तार लगाए जा रहे हैं। ये तार सोलर बिजली से कनेक्ट रहेंगे। ऐसे में यदि कोई भी चीता बाउंड्रीवॉल को लांघने की कोशिश करता है तो उसे करंट का झटका लगेगा। आपको बता दें कि गांधीसागर वन अभयारण्य 369 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 28 किलोमीटर लंबे बाड़े की जाली लगाने में करीब 17 करोड़ 70 लाख रुपए से अधिक की लागत आई है। वन क्षेत्र में कैमरे भी लगाए गए हैं। इस नए घर को बसाने और चीता प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए इस पर 30 करोड़ रुपए का खर्च होना है। दरअसल एक्सपर्ट के मुताबिक चीतों के लिए ऐसी जगह बेहद मुफीद मानी गई हैं, जहां बड़े जंगल हों, आराम करने के लिए घास हो और उनकी पसंद का खाना हो और ये सारी सुविधाएं मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य में उपलब्ध हैं। यही कारण है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया ने चीतों के लिए पहले कूनो, फिर गांधी सागर, नौरादेही और राजस्थान के अभयारण्य को चिन्हित किया था। इनमें से एक्सपर्ट ने पहले कूनो फिर गांधी सागर को चीता प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट स्थानों में चुना। वहीं नौरादेही और राजस्थान के अभयारण्य की तुलना में गांधी सागर में लागत आधी आ रही थी। यह एल शेप में है और चंबल नदी के किनारे पर बसा है। कुल मिलाकर यह स्थान चीतों के लिए नेचुरली बेहतरीन साबित होगा।

मप्र के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे, उनमें अब सिर्फ 17 जीवित बचे हैं और 10 चीतों की मौत हो चुकी है। हालांकि इन चीतों को भारत का मौसम रास नहीं आ रहा है या फिर कोई दूसरी वजह है, ये अब तक क्लीयर नहीं हो पाया है। अभी हाल ही में नामीबियाई चीता शौर्य की मौत हो गई, सितंबर 2022 के बाद से ये 10वीं मौत है। शौर्य की मौत किन वजहों से हुई, इसको लेकर वन विभाग ने बताया कि इसकी वजह स्पष्ट नहीं है। मार्च 2023 से, कूनो में अलग-अलग वजहों से शौर्य समेत 7 वयस्क चीतों और तीन शावकों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। अब तक मरने वाले वयस्क चीतों में तीन मादा और चार नर शामिल हैं। इनमें 27 मार्च को साशा, 23 अप्रैल को उदय, 9 मई को दक्ष, 11 जुलाई को तेजस, 14 जुलाई को सूरज, 2 अगस्त को धात्री और 16 जनवरी को शौर्य की मौत हो गई। हालांकि 23 जनवरी को 3 और शावकों का जन्म हुआ है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

सुरक्षा पर खर्च होंगे 100 करोड़ से अधिक

कैम्पा बैठक में कई प्रमुख कार्यों का अनुमोदन किया गया। बैठक में वनों की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई और तकरीबन 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के प्रस्ताव बनाए गए। इसके तहत 85 लाख से वाच टावर लगेंगे, आधुनिक उपकरण व सेफ्टी किट पर 12 करोड़, वन चौकी, वन उपज जांच नाका निर्माण पर 2.73 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जिन अन्य कार्यों का अनुमोदन दिया गया, उनमें 4906 हेक्टेयर में 82 करोड़ से नवीन प्रतिपूरक क्षतिपूर्ति वनीकरण, 30880 हेक्टेयर में 79 करोड़ से प्रतिपूरक वनीकरण रखरखाव, 47871 हेक्टेयर में 62 करोड़ से कैचमेंट क्षेत्र शोधन योजना पर काम, 38 करोड़ से वन्यप्राणी प्रबंधन किया जाएगा। जंगली हाथियों के उत्पात से निपटने पर 2 करोड़, 2 करोड़ से वन्यप्राणियों के लिए आधुनिक रेस्क्यू उपकरण खरीदे जाने को अनुमोदित किया है। स्ट्रांग रूम, कैमरे, अतिक्रमण विरोधी खेती निर्माण पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमोदन किया गया है। इनमें 12 करोड़ से वायरलेस खरीदी, 19 करोड़ से रोपणियों में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, 2.83 करोड़ से काष्ठांगार उन्नयन, 10 करोड़ से स्मार्ट फोन खरीदी भी शामिल है।

गोरा पत्थर की खदान बंद होने की कगार पर

एक समय टीकमगढ़ जिले के गोरा पत्थर की डिमांड विदेशों तक थी, लेकिन अब यहां पत्थर खदानें धीरे-धीरे बंद हो रही हैं। जितनी खदानें इस समय चल रही हैं वो भी 4 से 5 साल बाद बंद हो जाएंगी। नई खदानों को मंजूरी नहीं मिली है। एक्सपर्ट इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि सरकार ने अब तक खनिज ब्लॉक का ऑक्शन ही नहीं किया है। जबकि दो दिन पहले ही मप्र ने खनिज ब्लॉक की नीलामी में पहला स्थान हासिल किया है।

गोरा पत्थर का वैज्ञानिक नाम पाइरोफिलाइट है। ये ऐसा खनिज है जिसका इस्तेमाल कई वस्तु जैसे गुलाल, डिटर्जेंट पाउडर, सिंथेटिक डायमंड, रबर, पेंट, कपड़ा आदि बनाने में होता है। एशिया में चीन के बाद बुंदेलखंड ऐसा इलाका है, जहां बड़ी संख्या में पाइरोफिलाइट पाया जाता है। मप्र के माइनिंग डिपार्टमेंट का दावा है कि देश का 48 फीसदी पाइरोफिलाइट मप्र में पाया जाता है। इसके बावजूद पाइरोफिलाइट की खदानें बंद क्यों हो रही हैं, इसके कारोबार पर क्या असर पड़ा है। टीकमगढ़ से 20 किमी दूर कारी गांव के आगे जंगलों से गोरा पत्थरों की खदान शुरू होती है। खदान तक पहुंचने के लिए जंगल के ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ता है। यहां की इक्का-दुक्का खदान से खनन हो रहा है। बाकी खदानें बंद पड़ी हैं। यहां के कर्मचारियों का कहना है कि कुछ खदान निवाड़ी जिले में चली गई हैं। नई खदानों को मंजूरी ही नहीं मिली है। जो खदान चल रही हैं वो पिछले कई सालों से चल रही हैं। उनकी लीज अभी खत्म नहीं हुई है। कारी गांव की खदानों में 30 से 35 फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं। लगातार हो रही खुदाई के चलते दो बड़े तालाब बन गए हैं।

पाइरोफिलाइट खनिज का इस्तेमाल कई उत्पाद बनाने में होता है। इस कारोबार से जुड़े राजेंद्र जैन का कहना है कि इस पत्थर का मल्टी यूज है। इसलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। साबुन, कपड़ा, रंग, कागज, दवाई, खाद, कांच, रबर, पेंट, दवा और कॉस्मेटिक उत्पाद में इसका इस्तेमाल होता है। यहां तक कि बुंदेलखंड में बनने वाली कुछ मिठाइयों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये घुलनशील होता है। राजेंद्र जैन कहते हैं कि इसकी क्वालिटी से तय होता है कि इसका इस्तेमाल कहां होगा। पाइरोफिलाइट पत्थर को निकालने के बाद इसे पीसा जाता है। पीसने के बाद ये जितना बारीक होगा उससे इसकी क्वालिटी का पता चलता है। इसके पाउडर की बारीकी को मापने की इकाई मेस होती है। पाइरोफिलाइट के पाउडर 150 से 1200 मेस तक के होते हैं। पेस्ट्री पाउडर में 1200 मेस का उपयोग होता है। कागज-कपड़ा में 500 मेस का, टाइल्स, साबुन, रंग, गुलाल में 200 मेस का पाउडर उपयोग होता है। वहीं पेंट, रबर की हार्डनेस बढ़ाने में भी ये उपयोग किया जाता है।

इस कारोबार से जुड़े प्रणब जैन कहते हैं कि पाइरोफिलाइट से चीन में काफी समय से आर्टिफिशियल डायमंड बनाया जा रहा है। अब ये तकनीक भारत में भी आ चुकी है। गुजरात के सूरत में एक कंपनी इस पर काम कर रही है। यहां से पाइरोफिलाइट की सप्लाई आर्टिफिशियल डायमंड बनाने वाली कंपनी को की जा रही है। जो लोग हीरा नहीं खरीद सकते उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प है। वे कहते हैं कि चेहरे पर लगाने के लिए जिस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी पाइरोफिलाइट पत्थर के पाउडर का इस्तेमाल होता है। होली के रंग और गुलाल बनाने में भी इसके पाउडर का इस्तेमाल होता है। रंग और गुलाल बनाने के लिए इसकी डिमांड उप्र के हाथरस में सबसे अधिक है।

राजशाही दौर में पाइरोफिलाइट के साथ डायस्पोर से ईंट बनाई जाती थी। डायस्पोर में एल्युमिना की मात्रा 60 प्रतिशत से अधिक होती है। ये पदार्थ हाई टेम्प्रेचर सहन करने की क्षमता रखता है। पाइरोफिलाइट की खदानों से औसतन 10 प्रतिशत डायस्पोर निकलते हैं। इसकी कीमत प्रति टन 12 हजार रुपए से अधिक होती है। इससे बने ब्रिक्स 1400 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान आसानी से सहन कर सकते हैं। चिमनी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय खान ब्यूरो से मान्यता प्राप्त रजिस्टर क्वालिफाइड पर्सन (आरक्यूपी) पुष्पेंद्र सिंह चौहान कहते हैं कि 2019 से पहले बुंदेलखंड की इन खदानों ने चीन के वर्चस्व को चुनौती दी थी।

दरअसल, चीन के जिजियान और खुजियान प्रांत में पाइरोफिलाइट और डायस्पार खनिज बड़ी संख्या में मिलता था। वहां से इसकी सप्लाई स्पेन, अमेरिका, ब्रिटेन तक होती थी। प्रदूषण के चलते चीन में इन खदानों पर रोक लग गई। जब स्पेन को माल मिलना बंद हुआ तो व्यापारियों ने भारत की तरफ रुख किया। वे कहते हैं कि बुंदेलखंड से निकाले गए इस पत्थर पर नक्काशी का काम होता है। ये काम उप्र के आगरा में होता है। विदेश के व्यापारियों ने आगरा के व्यापारियों से संपर्क किया तब उन्हें यहां की खदान के बारे में पता चला। इसके बाद यहां से बड़ी संख्या में पत्थर एक्सपोर्ट होने लगा था। एक्सपर्ट पुष्पेंद्र सिंह इसकी दो वजह बताते हैं। पहली, नई खदानों को मंजूरी नहीं और दूसरी, सरकार की नीति में बदलाव। पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि पाइरोफिलाइट खनिज की नई खदानों को मंजूरी ही नहीं मिल रही, क्योंकि अब आवंटन ऑक्शन के जरिए होता है। पाइरोफिलाइट के लिए अभी तक ऑक्शन ही नहीं हुआ है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

खदान बंद होने से खत्म हो गई इंडस्ट्री

पुष्पेंद्र कहते हैं कि अभी जो 5-6 खदानें चल रही हैं उनकी लीज भी अगले 4 या 5 साल में खत्म हो जाएगी। नई खदानों को मंजूरी मिली नहीं है, इसलिए इस कारोबार से जुड़े मजदूर भी पलायन करने लगे हैं। वे कहते हैं वैसे भी बुंदेलखंड से मजदूर पलायन कर दिल्ली और दूसरे राज्यों या शहरों में जाते हैं। जब तक खदानों की संख्या ज्यादा थी तो मजदूरों को यहीं पर काम मिल रहा था। इस कारोबार से जुड़े प्रणब जैन का कहना है कि उनके पास 300 मजदूर काम करते हैं। वे पाइरोफिलाइट को विदेशों में सप्लाई करते हैं। अब जितनी डिमांड है उसके हिसाब से वे सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कच्चा माल नहीं निकल रहा। वे कहते हैं कि सबसे लॉ क्वालिटी का गोरा पत्थर भी हजार रुपए टन की कीमत में बिक जाता है। गोरा पत्थर की देश में खपत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घड़ी डिटर्जेंट के देशभर में संचालित 32 प्लांट के लिए हर महीने 10 हजार टन गोरा पत्थर की जरूरत पड़ती है। अब कच्चा माल न निकलने से गोरा पत्थर की डिमांड कम हो गई है।

करोड़ों का घोटाला मिनटों में निपटारा

हर साल विधानसभा में पेश होने वाली कैग की रिपोर्ट केवल खानापूर्ति

योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार-लापरवाही से सरकार को अरबों की चपत

वाकई मप्र अजब है, गजब है! तभी तो हर साल विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। उस पर विपक्ष भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करता है, तथा सरकार तथ्यों की जांच कर दोषियों को सजा देने का ऐलान करती है, लेकिन अब तक कैग की रिपोर्ट के आधार पर किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस स्थिति पर यही कहा जा रहा है कि करोड़ों के घोटाले का सरकार मिनटों में निपटारा कर देती है।

● राजेंद्र आगाल

मप्र के बजट सत्र में जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पेश की गई तो यह तथ्य सामने आया कि अफसरों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण सरकार को हर साल अरबों रुपए की चपत लग रही है। कैग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कैग ने अपनी 2021 की रिपोर्ट जारी करते हुए मप्र के कई सरकारी विभागों में भारी वित्तीय अनियमितता के आंकड़े जारी किए हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए आरोप लगाया है कि सरकार की योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। उधर, विपक्ष के हमलावर रुख को देखते हुए सरकार का कहना है कि वह कैग की रिपोर्ट का अध्ययन कराएगी और दोषियों पर कार्यवाही होगी। यह पूरा मामला किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा है, क्योंकि हर साल जब कैग की रिपोर्ट पेश होती है तो यही दृश्य और यही डायलॉग देखे और सुने जाते हैं। इसके आगे शायद ही कभी बात बढ़ी है।

गौरतलब है कि राज्यपाल ने कैग की सालाना रिपोर्ट पेश की तो मप्र के सरकारी विभागों में अफसरों द्वारा की जा रही गड़बड़ी, अनियमितताएं और नियम विरुद्ध फैसले लेने का खेल भी सामने आ गया। कैग की रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग, वन, पर्यावरण और उद्योग विभाग में भारी गड़बड़ियां सामने आईं, जिससे सरकार को हुए नुकसान के बारे में भी बताया गया। गौरतलब है कि कैग के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह देशभर के राज्यों और केंद्रीय विभागों की ऑडिट रिपोर्ट का अध्ययन कर वास्तविकता से उसका मिलान करती है। निष्कर्षों के साथ वास्तविक रिपोर्ट के आंकड़े जारी करके इससे विभागों की परफॉर्मेंस, खामियां और गड़बड़ियों का भी पता चलता है। कैग संबंधित मंत्रालयों, विभागों में अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा इकाइयों के जरिए यह रिपोर्ट तैयार कर राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखते हैं।

रिपोर्ट केवल खानापूर्ति

मप्र में पिछले डेढ़ दशक के दौरान खूब विकास हुआ है। प्रदेश में विकास की गति जैसे-जैसे बढ़ती गई भ्रष्टाचार के मामले भी बढ़ते गए हैं। हर साल जब विधानसभा में कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है तो भ्रष्टाचार की पोल खुलती है। इस बार भी बजट सत्र के दौरान 8 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत कैग की रिपोर्ट में प्रदेश के कई विभागों में कई बड़े घोटालों का खुलासा हुआ है। कई विभागों में हुई अनियमितताओं के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कैग की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा और उद्योग विभाग सहित अन्य विभागों में हुई अनियमितताओं के चलते शासन को 1400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि अफसरों के गलत डिसीजन, कोयले के कम उत्पादन और रॉयल्टी वसूली में कमी के चलते सरकार को ये खामियाजा उठाना पड़ा। सड़कों की गुणवत्ता और ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं करने के चलते भी सरकार पर देनदारी बढ़ी है। रिपोर्ट की मानें तो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियरों ने सड़क गुणवत्ता की गलत रिपोर्ट पेश की। जंगलों के सुधार के लिए कैंपा फंड में भी बड़े स्तर पर घोटाला हुआ। वन विभाग ने अनियमित रूप से अपात्र गतिविधियों में 50 करोड़ से अधिक खर्च किया गया। पीएचई विभाग में फर्जी सिक्योरिटी डिपोजिट से ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने खरीदी में भी घोटाले किए हैं। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, गलत निर्णय, कोयले के उत्पादन में कमी और रॉयल्टी वसूलने पर ध्यान नहीं दिया गया। जिससे सरकार को

घंटों में सिमट रहा सत्र

लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद हो या विधानसभा, जनता के मुद्दों पर चर्चा, सवाल-जवाब और फिर निर्णय पर पहुंचना ही आदर्श संसदीय व्यवस्था है, लेकिन अब स्थितियां बदलती जा रही हैं। विधानसभा सत्रों में चर्चा के नाम पर हंगामा, विरोध और फिर कार्यवाही का स्थगन। बीते कई वर्षों में यही चिंताजनक ट्रेंड मप्र विधानसभा में दिखाई दे रहा है। मप्र की 16वीं विधानसभा के बजट सत्र में 9 बैठकों के साथ 13 दिन चलने वाली कार्यवाही 5 दिन पहले ही खत्म हो गई। यानी बजट सत्र कुल 28 घंटे 9 मिनट चला और छह बैठकें हुईं। अगर आंकड़ों को देखें तो मप्र में साल दर साल विधानसभा सत्रों की संख्या भी कम हो रही है। 12वीं विधानसभा में 275 दिन का कुल सत्र 159 दिन सत्र चला था। 13वीं विधानसभा में 262 दिन के सत्र में 167 दिन सदन चला था। 14वी विधानसभा में 182 दिन के सत्र में 135 दिन सदन चला था। वहीं 15वीं विधानसभा में 132 दिन के सत्र में 83 दिन ही सदन चला था। मप्र की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया था। 4 दिन का यह सत्र पूरे दिन चला। लेकिन बजट सत्र अधूरा ही रह गया। जारी अधिसूचना के अनुसार इस बार मप्र विधानसभा का सत्र 7 फरवरी से 19 फरवरी तक का था, लेकिन इसे 14 फरवरी की कार्यवाही के साथ स्थगित कर दिया गया। यह पहला मौका नहीं, जब मप्र विधानसभा का सत्र निर्धारित अवधि से पहले स्थगित किया गया। मप्र में पांच वर्षों से विधानसभा सत्र की अवधि सिमटती जा रही है। 15वीं विधानसभा में कोई भी सत्र पूरे दिन नहीं चला। वहीं 16वीं विधानसभा का पहला सत्र महज शपथ ग्रहण की औपचारिकता के लिए था। जबकि 7 फरवरी से शुरू हुआ बजट सत्र पूरे समय तक नहीं चल पाया। विधानसभा सत्रों में चर्चा के नाम पर हंगामा, विरोध और फिर कार्यवाही का स्थगन। बीते कई वर्षों में यही चिंताजनक ट्रेड मप्र विधानसभा में दिखाई दे रहा है।

करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा जंगलों के सुधार के लिए कैंपा फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। कैग की रिपोर्ट के अनुसार, सड़कों के निर्माण में गुणवत्ताहीन काम ठेकेदार करते रहे। इसके बाद भी अफसरों ने काम की जांच बेहतर नहीं की। हालांकि उस दौरान ठेकेदारों का पेमेंट रोका गया। इसके बाद ठेकेदारों ने **बकाया राशि को लेकर सरकार** से ब्याज के तौर पर रकम ली। प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को लेकर भी कैग ने कहा कि कोयले की कमी के चलते अतिरिक्त भार उत्पादन में आया है। जिसकी वजह से सरकार को करीब 90 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कैंपा के फंड से वाहन खरीदी और भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता है। विभाग ने अनियमित रूप से अपात्र गतिविधियों पर 53 करोड़ रुपए खर्च कर दिए।

बिजली उत्पादन में गड़बड़ी

रिपोर्ट में बताया गया है कि कोयले की बिलिंग चरण से लेकर उत्पादन तक (कोयला खदान से लेकर उत्पादन क्षेत्र तक पहुंचाने) में गड़बड़ी पाई गई है। 71 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी कोयले की पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था करने में विफल रही, जिसके कारण बिजली उत्पादन में भार आया और दिसंबर 2018, अप्रैल 2019 और जून 2019 तक उत्पादन में नुकसान हुआ। इससे 90 करोड़ रुपए से अधिक की हानि हुई है। इसके अलावा निगरानी के लिए आवश्यक पर्याप्त सुविधाओं के बिना टरबाइन की सफलता और लंबी अवधि के लिए बंद रहने की वजह से 1044 करोड़ रुपए की हानि हुई है। लोक निर्माण विभाग में 3 करोड़ 31 लाख रुपए की वित्तीय देयता की स्थिति उत्पन्न हुई। सड़कों के **निर्माण में कांक्रीटकरण में लापरवाही** पाई गई और काम भी गुणवत्ताहीन हुआ। जिसकी वजह से 54 करोड़ रुपए का गुणवत्ताहीन काम किया गया। साथ ही रॉयल्टी को लेकर 31

1 लाख 45 हजार करोड़ का लेखानुदान पेश

मप्र विधानसभा में गत दिनों उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2024-25 आय-व्यय का लेखानुदान यानी अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए का है। जिसमें विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में खर्च के लिए राशि आवंटित की गई है। लेखानुदान में टैक्स के नए प्रस्ताव नहीं है। ना ही खर्च की कोई नई मद शामिल है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। लेखानुदान की प्राप्त राशि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में शामिल की जाएगी। लेखानुदान के माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की गई है। इसमें द्वितीय अनुपूरक अनुमान में शामिल नई योजनाओं के लिए प्रविधान किए गए हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि लेखानुदान द्वारा प्राप्त राशि चार माह बाद पेश होने वाले मुख्य बजट में शामिल की जाएगी। इस लेखानुदान में औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने संशोधित नीति के अनुरूप अनुदान देने, सड़क नेटवर्क मजबूत करने, एक्सप्रेस-वे निर्माण को गति देने के लिए भी धनराशि का प्रविधान किया गया है। लेखानुदान 4 माह (एक अप्रैल से 31 जुलाई, 2024) के लिए है। वित्तीय वर्ष हेतु बजट में सम्मिलित राशि 3,48,986.57 करोड़ है। लेखानुदान के लिए राशि रुपए 1,45,229.55 करोड़ है। लेखानुदान राशि में मतदेय राशि 1,19,453.05 करोड़ रुपए तथा भारित राशि 25,776.51 करोड़ रुपए है। वित्तमंत्री देवड़ा ने कहा कि लेखानुदान द्वारा प्राप्त राशि चार माह बाद पेश होने वाले मुख्य बजट में शामिल की जाएगी। इस लेखानुदान में औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने संशोधित नीति के अनुरूप अनुदान देने, सड़क नेटवर्क मजबूत करने, एक्सप्रेस-वे निर्माण को गति देने के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी चार माह के लिए अंतरिम बजट लाया गया है। इसमें कोई नई योजना फिलहाल नहीं लाई जा रही है। अंतरिम बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार आम चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। लेखानुदान में मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रति क्विंटल दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

करोड़ रुपए की रॉयल्टी वसूली जानी थी, लेकिन 15 करोड़ रुपए ही वसूल किए गए। करीब 16 करोड़ रुपए की रॉयल्टी में कमी आई। वहीं ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाने की योजनाओं में देरी हुई है। कैग ने पाया है कि संबंधित जल स्रोत में 171 दिनों तक कोई भी पानी उपलब्ध नहीं था। रिपोर्ट में बताया है कि आदेश जारी होने के बाद 18 से 24 महीने के भीतर काम पूरा किया जाना था, लेकिन लेखा परीक्षा में देखा कि 146 कार्यों में से 8 कार्य समय पर पूरे हुए थे, जबकि काम 256 दिनों का था। करीब 18 योजनाओं में से 12 योजनाओं को 580 दिनों में से अधिक समय में पूरा किया और चालू 6 योजनाओं को पूरा करने में 756 दिन लगा दिए।

मप्र में निर्मित पुलों के ऑडिट में कई गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। टोटल 72 पुलों का ऑडिट किया गया था। पाया गया है कि 68 पुल निर्धारित समय पर बनकर तैयार नहीं हुए थे फिर भी ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया। इसके अलावा ठेकेदारों को और भी कई प्रकार के लाभ दिए गए। प्रदेश सरकार ने सन् 2013 में एक नियम निर्धारित किया था कि सरकारी काम उपयोग किए जाने वाले गौण खनिज की रॉयल्टी ली जाएगी। संबंधित सरकारी ठेकेदार को रॉयल्टी अदा करनी होगी। इस नियम के अनुसार जब तक कोई ठेकेदार रॉयल्टी चुकाने के संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र नहीं देता, उसका भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद भी अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच भोपाल और उज्जैन संभाग के छह पुलों के निर्माण में ठेकेदारों का भुगतान कर दिया गया। इनके निर्माण में एक माह से 68 माह तक का विलंब हुआ। ठेकेदारों पर कार्यवाही भी नहीं की गई। शासन ने तर्क दिया कि विभिन्न तरह की अनुमतियां प्राप्त करने के कारण विलंब हुआ। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अंतर्गत प्रधान महालेखाकार मप्र ग्वालियर द्वारा ताजा ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि, मप्र सरकार पर लोन की रकम बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब चिंता की स्थिति बन गई है। सरकारी योजनाओं में कई प्रकार की अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में बताया कि मप्र में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी बुनियादी ढांचे में लगातार कमी होती जा रही है।

सिंगाजी में 2113 करोड़ की गड़बड़ी

कैग ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसके मुताबिक मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी के सिंगाजी पावर प्लांट के निर्माण 2009 से लेकर 2021 तक संचालन के दौरान नियमानुसार ठेकेदार को देरी के कारण कोयले के स्टॉक में कमी की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। प्लांट के निर्माण में देरी की वजह से बिजली की कमी को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से महंगी बिजली खरीदी गई। जिसमें सरकार को 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। यह खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में हुआ है। कैग की यह रिपोर्ट वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को आधार मानकर तैयार की गई है।

कैग की रिपोर्ट के अनुसार सिंगाजी ताप विद्युत गृह के निर्माण और संचालन में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। त्रुटिपूर्ण योजना, ठेकेदार को अग्रिम भुगतान नहीं करने, उसे अनुचित समय विस्तार देने और टरबाइनों की विफलता के चलते शासन को वर्ष 2009 से 2021 तक 2113 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गड़बड़ियां सामने आने के बाद कैग ने अनुशंसा की है कि सभी इनपुट की योजना बनानी चाहिए, जिससे भविष्य में शुरू होने वाली परियोजनाओं में इसका लाभ मिल सके। कंपनी को पर्यावरणीय मानदंडों और विनियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कंपनी ने परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। समय पर फ्यूल लिंकेज की स्वीकृति प्राप्त नहीं की, जिससे 120 करोड़ रुपए छोड़ने पड़े। ठेकेदार को अग्रिम भुगतान में देरी की गई, जिससे मप्र विद्युत नियामक आयोग ने निर्माण

अवधि का ब्याज एवं आकस्मिक व्यय की राशि 215 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कंपनी ने इकाइयों के वाणिज्यिक संचालन तिथि से काफी पहले जल आपूर्ति अनुबंध कर लिया, 67 करोड़ रुपए का गैर जरूरी भुगतान किया गया। निर्धारित समय पर परियोजना पूरी नहीं होने के कारण महंगी दरों पर बिजली खरीदने में 102 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा। कंपनी ने संयंत्र के संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं जुटाईं। ऐसे में उत्पादन हानि के अतिरिक्त 1055 करोड़ रुपए स्थायी लागत की वसूली नहीं हुई।

कैग ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग में भी गड़बड़ी पकड़ी है। कैग ने जल निगम द्वारा चलाई जा रही 58 योजनाओं में से 18 की जांच की। इसमें सामने आया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में गलत व्यय, गलत प्राक्कलन, गांव के सभी घरों को शामिल नहीं करने, ओवर हेड टैंक बनाने के लिए गलत दर पर काम देने और ठेकेदार से अतिरिक्त बैंक गारंटी प्राप्त करने में विफलता के चलते शासन को 283 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच वन भूमि का डायवर्जन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने, डायवर्टेड वन भूमि के उपयोग में अनियमितता, प्राधिकार के बिना वन भूमि का अनियमित डायवर्जन सहित कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। कैग ने 17 वनमंडलों की जांच की थी। कैंपा फंड के अंतर्गत वनीकरण के लिए गलत स्थान का चयन और खरपतवार उन्मूलन पर अनुचित व्यय किया गया है। इससे 364 करोड़ रुपए की हानि सरकार को हुई है। वहीं कैग ने नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना को लेकर भी अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने नर्मदा का पानी क्षिप्रा में छोड़कर इसे एक बारहमासी नदी में बदलने की कोशिश की। कैग ने रिपोर्ट में लिखा कि अफसर इस लक्ष्य से पूरी तरह से भटक गए। साथ ही कैग ने क्षिप्रा को साफ करने के प्रयासों को भी नाकाफी बताया है। खास बात ये है कि 7 जनवरी को उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने क्षिप्रा को सतत् प्रवाह मान बनाए रखने के लिए एक नया प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस प्रयास से सिंहस्थ 2028 और भी सुंदर हो जाएगा। इसके अलावा कैग ने पीएचई और वन विभाग की योजनाओं पर भी सवाल उठाए हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार की कई एजेंसियों के हस्तक्षेप के बावजूद क्षिप्रा नदी प्रदूषित बनी हुई है। देवास, इंदौर और उज्जैन शहर का कचरा इस पवित्र नदी को मार रहा है। नदी घाटी में भूजल की अंधाधुंध निकासी से भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। इसकी वजह से नदी सूख रही है। इसे बचाने के लिए सरकार ने नदी के तटों पर पेड़ लगाने की योजना तो बनाई, लेकिन इसमें भी गड़बड़ी पाई गई। वहीं सीवरेज नेटवर्क, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, नालों, सड़कों और दूसरे सिविल काम में भी बड़ी अनियमितता की तरफ इशारा किया है।

विधानसभा के सत्र चलाने में किसी की रुचि नहीं

दरअसल, सत्तापक्ष हो या विपक्ष किसी की भी रूचि अब अधिक अवधि तक विधानसभा सत्र चलाने में नहीं रह गई है। सरकार का जोर इस बात पर रहता है कि विधायी कार्य पूरे हो जाएं। वहीं, विपक्ष शुरुआत से ही हंगामा करना प्रारंभ कर देता है। स्थिति अब तो यह बनने लगी है कि प्रश्नकाल तक पूरा नहीं हो पाता और अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ती है। बजट सत्र में भी यही स्थिति बनी। इससे अध्यक्ष व्यथित भी नजर आए पर सदन के सुचारू संचालन में पक्ष और विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जाहिर है दोनों पक्ष इसके लिए एक-दूसरे को ही जिम्मेदार बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का आरोप है कि सरकार सदन में चर्चा कराने से भागती है। विपक्ष लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करना चाहता है पर सत्तापक्ष हंगामा करने लगता है। भाजपा के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस कभी जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करती। हंगामा करना ही इनका मकसद रहता है। जबकि, सदन का मंच हमें जनहित पर चर्चा करने के लिए दिया है और सबकी प्रक्रिया निर्धारित है। बड़ी तैयारी के साथ विधायक विधानसभा सत्र के लिए प्रश्न लगाते हैं। एक घंटे के प्रश्नकाल में 25 प्रश्नों का चयन लॉटरी के माध्यम से होता है।

ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नहीं किया

भविष्य की मांग को देखते हुए स्थानीय निकाय ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नहीं किया। हुआ भी तो पूरे भौगोलिक क्षेत्र को कवर नहीं किया। ये काम समय सीमा में पूरे नहीं हुए। स्थानीय निकायों के पास मल-कीचड़ के निपटान की समुचित व्यवस्था नहीं थी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। स्थानीय निकाय ने फ्लड प्लेन जोन में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं की। नदी के तट का विकास सही तरीके से नहीं किया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि क्षिप्रा किनारे संचालित उद्योग बगैर परमिशन काम कर रहे हैं। ऐसे उद्योगों के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्यवाही नहीं

की। जो वैध उद्योग हैं उन्होंने पीसीबी को रिपोर्ट पेश नहीं की। साथ ही ये भी कहा कि ये उद्योग बगैर अपशिष्ट उपचार प्रबंध (ईटीपी) के चल रहे थे। देवास और उज्जैन में सीईटीपी नहीं मिला। जिन उद्योगों की जांच की उनमें केवल 4 में पानी के मीटर पाए गए। कैग ने रिपोर्ट में लिखा कि कम पानी के मौसम में क्षिप्रा में पानी देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया। नर्मदा-क्षिप्रा लिंक प्रोजेक्ट के जरिए नर्मदा के पानी को क्षिप्रा में डाला गया, मगर योजना पूरी तरह से भटक गई। वहीं भूजल निकालने से पहले उद्योगों ने केंद्रीय भूजल बोर्ड से अनुमति नहीं ली। कितना पानी निकाला जा रहा इसकी मॉनीटरिंग के लिए पानी के मीटर नहीं लगाए गए। सिंचाई के लिए पानी की ऑप्शनल व्यवस्था न होने से भूजल स्तर गिर गया। केंद्रीय भूजल बोर्ड क्षिप्रा बेसिन के सात खंडों के लिए दिशा-निर्देश बनाने में नाकाम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कैंपा फंड के अंतर्गत वनीकरण के लिए गलत स्थान का चयन और खरपतवार उन्मूलन पर अनुचित व्यय किया गया है। इससे 364 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हुआ है। बताया गया है कि कैग ने 2017-18 से 2019-20 के बीच 17 वन मंडलों की जांच की थी। जिसमें वन भूमि के डायवर्जन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने, डायवर्ट वन भूमि के उपयोग में अनियमितता, प्राधिकार के बिना वन भूमि का अनियमित डायवर्जन सहित कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं।

अपात्रों को पीएम आवास

मप्र में पीएम आवास योजना में कई गड़बड़ियों के खुलासे हुए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कैग की रिपोर्ट पटल पर रखी। उन्होंने सात अलग-अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। इन रिपोर्ट्स में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के तहत पीएम आवास वितरण (साल 2016 से 2021) की गड़बड़ियां उजागर की गई हैं। कैग की रिपोर्ट में नगरीय प्रशासन, पंचायती राज विभाग सहित और भी कुछ विभागों की योजनाओं का ब्यौरा है। इनमें पंचायती राज संस्थाओं की

कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र और वित्तीय प्रतिवेदित प्रकरणों की रिपोर्ट में पांच साल का ब्यौरा है। रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 से 2021 के दौरान मप्र में पीएम आवास योजना में अपात्रों को भी योजना का लाभ दिया गया, जबकि कई मामलों में तो एक-एक परिवार को तीन-तीन बार पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया है। रिपोर्ट में बात सामने आई है कि आर्थिक तौर से मजबूत कई लोगों ने इस योजना का गलत फायदा उठाया है।

कैग रिपोर्ट के मुताबिक करीब दो हजार लोग ऐसे भी हैं, जो कार-बाइक और स्कूल तक के मालिक हैं, बावजूद इसके उन्होंने पीएम आवास योजना का लाभ लिया। पीएम आवास की किस्त 15 दिन में देने का नियम है, लेकिन 13 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें दूसरी किस्त मिलने में एक दिन से लेकर 1500 दिन का इंतजार करना पड़ा। जबकि 25 लाख स्वीकृत मकानों में से 8 लाख लाभार्थियों को 15 दिन के भीतर ही किस्त मिल गई। मप्र विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल स्वीकृत आवासों में से 18 फीसदी यानि 4.64 लाख मकान अधूरे हैं। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि अपात्रों को दी गई है। जबकि रिपोर्ट में बताया गया है कि एक ही परिवार को 2 से 3 मकान तक दे दिए गए हैं।

निकायों में 53.02 फीसदी पद खाली

कैग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि प्रदेश के 32 नगरीय निकायों में 53.02 फीसदी पद खाली पड़े हैं। इन निकायों के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या के एवज में कर्मचारियों की भारी कमी से कामकाज अत्याधिक प्रभावित हो रहा है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार मप्र की 32 शहरी स्थानीय निकायों की जांच में पाया गया है कि मार्च 21 तक स्वीकृत पद की तुलना में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं गईं हैं। स्थानीय निकायों में 44.73 फीसदी से 54.55 फीसदी तक पद रिक्त पड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 17 निकाय ऐसे भी हैं जहां स्वीकृत कर्मचारियों की तुलना में अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका निगम देवास, नगर पालिका निगम भोपाल और नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में कर्मचारियों की भारी कमी के चलते कामकाज प्रभावित हो रहा है। सर्वाधिक सहायक ग्रेड 3, सहायक राजस्व निरीक्षक, सफाई संरक्षक, ड्राइवर और चौकीदार जैसे पदों पर कर्मचारियों की भारी कमी पाई गई है। कैग द्वारा 32 नगरीय निकायों जिनमें 8 नगर निगम, 13 नगर पालिकाएं और 11 नगर परिषदों को जांच में लिया गया था। इसके अतिरिक्त नगर पालिका निगम भोपाल में अपर आयुक्त की स्वीकृत पद संख्या 4 है, जबकि 6 अपर आयुक्त पदस्थ हैं।

विधानसभा सत्र होते गए छोटे... सरकार ने सारे काम निपटाए

विधानसभा के सत्र भले की आधे-अधूरे हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस दौरान अपने सारे काम निपटा लेती है। 16वीं विधानसभा का बजट सत्र कुल 28 घंटे 9 मिनट चला और छह बैठकें हुईं। जिसमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य संपन्न हुए। सदन ने अन्य वित्तीय कार्यों के अलावा वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा कर लेखानुदान पारित किया, वहीं वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक मांगों को स्वीकृति प्रदान की गई। सत्र में कुल 2,303 प्रश्न प्राप्त हुए। ध्यानाकर्षण की कुल 541 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 40 सूचनाएं ग्राह्य हुईं। दरअसल, पक्ष हो या विपक्ष किसी की भी रूचि अब अधिक अवधि तक सत्र चलाने में नहीं रह गई है। सरकार का जोर इस बात पर रहता है कि विधायी कार्य पूरे हो जाएं। वहीं, विपक्ष शुरुआत से ही हंगामा करना प्रारंभ कर देता है। स्थिति अब तो यह बनने लगी है कि प्रश्नकाल तक पूरा नहीं हो पाता और अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ती है। सदन के सुचारू संचालन में पक्ष और विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जाहिर है दोनों पक्ष इसके लिए एक-दूसरे को ही जिम्मेदार बताते हैं।

अंतरिम बजट में कुछ खास नहीं

सरकार पूंजीगत व्यय के जरिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार

किसानों की आय दोगुनी करने के दावे किए जा रहे थे लेकिन उनकी आय आधी रह गई है। किसान की समस्या है उत्पादन का उचित दाम न मिलना। जब देश में कृषि उत्पादों के दाम ऊंचे होते हैं तो सरकार आयात करके किसानों को मारती है। वहीं जब विश्व बाजार में दाम ऊंचे होते हैं तो निर्यातों पर प्रतिबंध लगाकर सरकार किसान को ऊंचे मूल्य का लाभ उठाने से वंचित करके फिर मारती है। सरकार को इस नीति में बदलाव करना चाहिए था, लेकिन सरकार यहां भी चूक गई। बजट को समग्रता से देखने पर पता चलता है कि सरकार पूंजीगत व्यय के जरिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश कर रही है, इसलिए कुल व्यय में पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी को बढ़ाया है। वित्तमंत्री ने राजकोषीय घाटे को भी 5.1 प्रतिशत तक नियंत्रित रखने का दावा किया है। इस साल जुलाई में प्रस्तुत किए जाने वाले पूर्ण बजट के पहले का यह अंतरिम बजट संकेत दे रहा है कि आगे भी बजटीय प्रावधानों का आकार बड़ा होगा। इससे अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचेगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि समय पर उठाए गए कुछ कदम और नीतिगत निर्णय से हमारी अर्थव्यवस्था कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर रही है। मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई, औद्योगिक उत्पादन, जीएसटी संग्रह जैसे प्रमुख संकेतक संतोषजनक स्तर पर बने हुए हैं। इन्हीं सबको आधार मानकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और इसके ग्लोबल इकोनॉमी का विकास इंजन बनने को लेकर आशान्वित दिख रहा है।

आम जनता को उम्मीद थी कि चुनाव से ठीक पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार राहत उपायों के साथ-साथ नौकरी पेशा मध्य वर्ग को भी लुभाने का प्रयास करेगी, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं कर सरकार ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया है। हालांकि केंद्र की सत्ता पर अपनी तीसरी पारी को लेकर आश्वस्त मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में गरीब, महिला, अति पिछड़ा वर्ग, अन्नदाता किसान को आगे कर अगले 5 साल में 2 करोड़ नए घर, 3 करोड़ लखपति दीदी तैयार कर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देने का दावा किया है।

वर्ष 2019 के अंतरिम बजट में आयकरदाताओं को थोड़ी सहूलियत मिली थी। चुनावी साल होने के कारण इस बार भी लोगों को राहत की उम्मीद थी। वित्तमंत्री ने अंतरिम बजट में छूट न देने की परंपरा को रेखांकित करते हुए बदलाव नहीं करने की बात तो कही लेकिन लगे हाथों कॉरपोरेट टैक्स को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया। मार्च 2025 तक सोवरेन फंड्स पर टैक्स छूट बढ़ा दी है, साथ ही साथ स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट का दायरा भी बढ़ाया गया है। चूंकि यह बजट आसन्न लोकसभा चुनाव की चुनौतियों के ठीक पहले पेश किया गया है इसलिए इसका फोकस और लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट दिखता है और इसमें भ्रम की कोई स्थिति नहीं दिखती। अपनी अगली पारी को लेकर पूरी तरह से तैयार मोदी सरकार ने 2047 तक के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने के रोडमैप को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, और बजट के अधिकतर प्रावधान इसी लक्ष्य की पूर्ति के प्रयास जैसे हैं। चाहे बजट का आकार हो या प्रावधानों के प्रकार दोनों का फोकस इसी बात पर है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार कैसे दी जाए? और शासन सत्ता में बने रहने के लिए समाज के बड़े समूह को कैसे साध कर रखा जाए?

चुनावी लिहाज के हिसाब से महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीब तबके की बड़ी आबादी को जोड़े रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस क्रम में अगले 5 साल में 2 करोड़ नए मकानों का निर्माण, छत पर सौर प्रणाली लगाने से सीधे एक करोड़ परिवारों को जोड़ने का वादा, ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए शीघ्र समिति का गठन, सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए टीकाकरण पर जोर, आयुष्मान भारत योजना से आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को जोड़ने, पशुओं को बीमारी से बचाने, मत्स्य उत्पादन के निर्यात बढ़ाने, 3 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही अंतरिम बजट 2024 में वित्तमंत्री ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने का दावा किया है। साल 2023-24 का रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ रुपए था जो वर्ष 2022-23 की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक था, इस बार यह बढ़कर 6.2 लाख करोड़ हो गया है, यानी रक्षा के क्षेत्र में 3.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजट में भी वृद्धि करते हुए 2.78 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसी तरह वित्त वर्ष 2023 में रेलवे बजट 2.4 लाख करोड़ रुपए का था इस बार इसे बढ़ाकर 2.55 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। अंतरिम बजट में तीन बड़े रेलवे कॉरिडोर की घोषणा हुई है तथा यह भी कहा गया है कि 40000 रेलगाड़ी डिब्बों को वंदे भारत ट्रेन में बदला जाएगा। बुनियादी उपभोक्ता आंदोलन को गति देने के लिए एक विशिष्ट विभाग की आवश्यकता के दृष्टिकोण से जून 1997 में एक अलग विभाग के रूप में गठित उपभोक्ता मामले और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को अंतरिम बजट में 2.3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गृह मंत्रालय के बजट में भी वृद्धि करते हुए पूर्व के 1.96 लाख करोड़ रुपए की जगह अबकी बार 2.03 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरह ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी 1.57 लाख करोड़ रुपए की जगह अंतरिम बजट में 1.7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए, संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए तथा किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

बजट में बुनियादी संरचना पर सरकारी निवेश में वृद्धि की गई है, जो कि सही दिशा में है। वित्त मंत्री को आशा है कि कैशलेस इकोनॉमी से टैक्स की वसूली और अधिक बढ़ेगी, लेकिन हमें ठहर कर यह सोचना होगा कि अंतत यह भार आम आदमी पर ही पड़ेगा। पहले उपभोक्ता नगद में माल खरीदकर उस पर टैक्स अदा करने से बचता था, अब उसी पर टैक्स देगा। वित्तमंत्री ने परंपरा का हवाला देकर आयकर में कोई राहत तो नहीं दी है लेकिन आने वाले समय में टैक्स बढ़ाने की खिड़की खुली छोड़ रखी है।

● **बृजेश साहू**

पराजयवादी मानसिकता की शिकार कांग्रेस

देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी न तो किसी नीति पर कायम है, न ही नियम पर। पार्टी हार की मानसिकता से घिरी हुई है। इस कारण कांग्रेस कोई ठोस रणनीति नहीं बना पा रही है।

देश के दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने के तौर तरीकों में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। 2014 और 2019 की तरह ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी यह फर्क साफ दिख रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटों के प्रचंड बहुमत से सत्ता में लगातार दूसरी बार काबिज हुए मोदी 2024 में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मोदी लोकप्रियता के जिस शिखर पर लगातार बने हुए हैं और विपक्षी गठबंधन जिस तरह से तार तार हो चुका है ऐसे में 400 सीटों का आंकड़ा असंभव जरूर लगे लेकिन 350 सीटों पर भाजपा का पहुंचना संभव लग रहा है। 2014 में 42 और 2019 में 52 सीटों पर सिमटी कांग्रेस ने पिछले 5 साल में ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे यह कहा जा सके कि कांग्रेस मोदी को बहुमत से दूर रखने में कामयाब रहेगी और खुद भी दहाई के आंकड़े को पार कर पाएगी।

अभी भी मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार का घाव ताजा है। मोदी को चुनौती देने के लिए बना विपक्ष का इंडिया गठबंधन अंतिम सांसे ले रहा है। दशक भर से देशभर में पिटी हारी कांग्रेस 60 दिन के भीतर होने वाले आम चुनाव में आत्मसंतुष्ट भाव या पराजयवादी मानसिकता के साथ उतरती दिख रही है। जब राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में रुकना था वह अपनी न्याय यात्रा पर निकल गए। इंडिया गठबंधन की इस दुर्दशा के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है।

नीतीश को संयोजक नहीं बनाया, वह निकल गए। ममता को लगा कि कांग्रेस बंगाल में उनसे ज्यादा तवज्जो वामदलों को दे रही है तो ममता ने भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उप्र में कांग्रेस मायावती को साथ लेने के लिए मना नहीं सकी और मायावती ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली। मायावती के अलग लड़ने के निर्णय ने सबसे ज्यादा सांसद देने वाले राज्य उप्र में भाजपा की राह आसान कर दी है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के नेतृत्व में जिस विपक्षी एकता का ताना बाना 23 जून 2022 को पटना में बुना था, कांग्रेस की उदासी और लापरवाही के चलते खुद नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा के साथ सरकार बनाकर उस इंडिया गठबंधन को तार-तार कर दिया जिसके शिल्पकार वह खुद थे। ऐसे में कांग्रेस की बैसाखी के सहारे खड़े होने वाले उसके सहयोगी दल अब कांग्रेस को एक एसेट की बजाय एक लाइबिलिटी के रूप में देख रहे है।

राजनीति में जोश और रफ्तार की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और भाजपा मोदी के नेतृत्व में जोश और रफ्तार से 2024 के चुनाव में जीत की रणनीति बनाने और उसे अमलीजामा पहनाने में जुट गई है। मोदी के लिए लगातार तीसरा कार्यकाल पहले से ज्यादा आसान और संभव दिख रहा है जो नेहरू के बाद भारत में किसी को नहीं मिला। भाजपा ने जोश और खुशी से लबालब असर पैदा करने और तमाम पुर्जों को जोड़कर विशाल शक्ति पैदा करने के लिए बहुत छोटे-छोटे ब्यौरों को साधने और संजोने में महारत हासिल कर ली है। वहीं कांग्रेस 2019 की तरह चुनाव की पूर्व संध्या पर उदास और लटका चेहरा लिए दिख रही है। कांग्रेस न खुद मोदी को चुनौती देने के लिए अपने दम पर खड़ी हो सकी और न ही गठबंधन को एक रख सकी।

प्रधानमंत्री मोदी की विकसित भारत यात्रा की गाड़ी देश के सफर में निकल चुकी है और मोदी खुद लोगों से संवाद कर रहे हैं। भाजपा का विशाल संगठन मोदी की विकसित भारत की यात्रा को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए दिन-रात एक कर रहा है, वहीं राहुल की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा न किसी तरह का उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जगा रही है और न जनता में उनके नेतृत्व को लेकर कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब कांग्रेस के समर्थक भी इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जिस तरह कांग्रेस खराब तैयारी के साथ लड़खड़ाती हुई चुनावी राजनीति में उतरती है और गुटीय झगड़ों को काबू में नहीं रख पाती और सबसे अहम यह कि वह जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाती, उससे उसका अपना कैडर ही बुझा हुआ है।

राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने कांग्रेस की सांगठनिक कमजोरी को भी सामने ला दिया है। राहुल की न्याय यात्रा से मिली गतिशीलता को कायम रखने के लिए कांग्रेस के पास ऐसा संगठन ही नहीं बचा है कि वह उसे चुनाव के लिए तैयार मशीन बना सके और भाजपा को चुनौती दे सके। ऐसे में मोदी जब राम के रथ पर सवार होकर चुनाव प्रचार अभियान में निकलेंगे तो विपक्ष के लिए मोदी को रोकना लगभग असंभव होगा।

राम मंदिर से बड़ा झटका

विपक्ष कहने लगा है कि भाजपा और संघ परिवार को अगर यह लगता है कि देश के विभिन्न अंचलों के श्रद्धालुओं को भव्य राम मंदिर व दिव्य अयोध्या का दर्शन कराकर वह लोकसभा चुनाव तक उन्हें अपना मुरीद बनाने की सफलता हासिल कर लेंगे, तो यह शायद ही संभव हो। विपक्ष का यह 'शायद' ही उसे सीधे-सीधे हरा रहा है। हिंदुस्तान की हिंदी पट्टी में राम लहर दिख रही है और राम मंदिर के मामले में, विपक्ष अब दावे के साथ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हां, विपक्ष इस बार मोदी सरकार के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी की बात जरूर करने लगा है, लेकिन यह बता नहीं पा रहा है कि एंटी-इनकंबेंसी है कहां? जबकि प्रधानमंत्री मोदी तो भगवान राम के मंदिर की प्रतिष्ठा करवाकर अपनी तीसरी पारी का मार्ग प्रशस्त करने में सफल हो गए हैं। विपक्ष और खासकर कांग्रेस भले ही कहे कि वह राम या राम मंदिर के नहीं, भाजपा व प्रधानमंत्री मोदी के विरूद्ध है। लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों की नीयत राम को लेकर कभी साफ रही नहीं है।

इंडिया गठबंधन से समन्वय नहीं

याद कीजिए कि सन् 2020 में 5 अगस्त को, जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन के समय रामलला को साष्टांग दंडवत के बाद 2022 में उप्र विधानसभा के चुनाव हुए तो भाजपा को कैसी जबरदस्त विजय हासिल हुई और योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने थे। इसलिए, विपक्ष और कांग्रेस राम मंदिर को लेकर भाजपा को जितना कटघरे में खड़ा करेंगे, वे खुद ही कैद होते दिखेंगे। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। पीछे विपक्ष बिखर रहा है। कांग्रेस को ममता बनर्जी, केजरीवाल और उद्धव ठाकरे समझौते में पूरी सीटें तक देने को तैयार नहीं है। फिर विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह व्यंग करे या फिर उद्धव ठाकरे की तरह धमकी दे, लगातार तीसरी बार सत्ता में तो फिर से भाजपा ही आती दिख रही है। राम मंदिर निर्माण भाजपा और मोदी के लिए रामबाण का काम करेगा। विपक्ष को अगर यह नहीं दिखता तो उसकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठना जायज है।

मोदी के काम के साथ राम का नाम भी चुनाव प्रचार में एक प्रमुख अस्त्र बनने वाला है। लेकिन कांग्रेस अभी तक इस बात को ही नहीं समझ सकी है कि मोदी और शाह ने राष्ट्रीय स्तर के चुनावी मुकाबलों को संस्कृति (धर्म), पहचान (राष्ट्रवाद), सुरक्षा और विकास के साथ-साथ मोदी की चार जातियों महिला, युवा, किसान और गरीब पर केंद्रित कर दिया है। इनमें से हर एक मुद्दे पर कांग्रेस अचेत नजर आती है।

कांग्रेस यह समझने में पूरी तरह नाकाम रही कि किसी लोकप्रिय नेता और ताकतवर सरकार को सिर्फ उसके खिलाफ केवल प्रतिक्रियाएं करके और बिना कोई वैकल्पिक नजरिया पेश किए हराया नहीं जा सकता। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वह धर्मनिरपेक्षता को किस तरह परिभाषित करे। कांग्रेस जिस विचारधारा की राजनीति की बात कर रही है क्या वह विचारधारा आज की चुनावी परिस्थिति के अनुकूल है? कांग्रेस की इसी दुविधा और भ्रम ने उसे 1984 में 414 सीटों से 2014 में 44 सीटों के ऐतिहासिक रसातल पर पहुंचा दिया था। अभी भी वह मात्र 52 सीटों के साथ लोकसभा में उपस्थित है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के पास बहुत समय नहीं बचा है। मोदी को कैसे रोकना है इस पर विचार करने की बजाय विपक्षी दलों का गठबंधन एक-दूसरे को अपने राज्य में आने से रोकने की तिकड़म भिड़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में मोदी की राह विपक्ष खुद आसान कर रहा है।

मोदी के नेतृत्व में भाजपा का 50 प्रतिशत वोट और 400 सीटों का लक्ष्य भाजपा की ताकत से ज्यादा विपक्ष की कमजोरी पर निर्भर है। विपक्ष खुद मोदी को उस लक्ष्य की ओर ले जाने में मदद कर रहा है जो भारतीय राजनीति में अभी तक किसी को नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस सहित विपक्ष के सामने सवाल सिर्फ यह रह गया है कि वह भाजपा को 303 पर रोक पाती है या भाजपा राजीव गांधी के 414 के आंकड़े को भी पार कर जाएगी? संसद में खड़े होकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भले ही व्यंग में मोदी के 400 पार वाले जुमले का जिक्र किया हो लेकिन इतना तो तय है कि 400 पार के नारे का तोड़ उनके पास भी नहीं है।

भाजपा वैसे भी अबकी बार 400 पार का नारा उछाल ही चुकी है। राम मंदिर का मुद्दा 2023 के चुनाव के लिए रामबाण का रूप धर चुका है, और भाजपा को केंद्र में अकेले अपने दम पर बहुमत की सीढ़ियां चढ़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक स्तर का महानायक हो जाने का भी बड़ा सहारा मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत पक्की होना ठीक वैसा ही है, जैसे 30 अक्टूबर, 1990 को कारसेवकों ने तमाम बंदिशें तोड़कर बाबरी मस्जिद पर भगवा फहरा दिया था और उसी दिन से यह मान लिया गया था कि हिंदुत्व के विजय अभियान की शुरुआत हो गई है। फिर 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद को जब ढहा दिया गया, तो देश ने उसे हिंदू कार्यकर्ताओं के शौर्य का प्रदर्शन मानकर भाजपा की सत्ता के शुभारंभ का ऐलान कर दिया था।

बाबरी ढांचे पर पहले भगवा फहराया जाना और बाद में उसे ढहाया जाना, ये दोनों ही घटनाएं इतने सालों तक भाजपा की राजनीतिक यात्रा की सफलता का साधन बनी रहीं, तो फिर राम मंदिर का लाभ भाजपा को कैसे नहीं मिलेगा, यह तथ्य किसी भी तर्क से परे है। इसी कारण राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि चुनावी उपलब्धियों को आगामी सफलता में बदलने के लिए भाजपा ने जिस तरह से अब तक हर प्रयास किया है, उसी तर्ज पर अब आगामी लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को फिर से सत्ता में आने से विपक्ष द्वारा उसे रोक पाना संभव नहीं लगता। भाजपा के 400 पार के नारे से देश में एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य चुनावी मुकाबला शुरू होने से पहले ही विपक्ष का उत्साह ठंडा करके उसे वॉकओवर के लिए विवश कर देना है। बिखरे हुए विपक्ष के बीच ऐसा करना बेहद आसान है। राम मंदिर ने भाजपा की फिर से, यानी तीसरी बार सत्ता में आने की लड़ाई का मुकाबला आधा कर दिया है और बाकी आधी जंग को जीतना उसके लिए बाएं हाथ का खेल बना दिया है।

भारत की जनता ने, कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार में हुए हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के प्रति नाराजगी जताते हुए, सन् 2014 में नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल पर भरोसा करके वोट दिया था। तब विपक्ष कहता रहा कि भाजपा और उनके नेता नरेंद्र मोदी राम के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आए, लेकिन अयोध्या की देहरी तक भी नहीं आए। बात सही है। दरअसल, अपनी परिवर्तित छवि को लेकर मोदी इतने सतर्क थे कि कभी उन्होंने राम मंदिर बनाने का नाम तक नहीं लिया। अयोध्या मुद्दे व अयोध्या नगरी से रणनीतिक दूरी भी बनाए रखी, और देश के मूड को समझते रहे। हालांकि, सबकुछ भीतर ही भीतर चलता रहा। लेकिन 2019 में जब वे अपनी जीत में कामयाब होकर दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो उधर का रुख किया और अयोध्या, राम व राम मंदिर के बारे में केवल तीन साल में ही पूरी धारणा को बदलकर नई अवधारणा स्थापित कर दी। अब राम मंदिर अपने साक्षात स्वरूप में हम सबके सामने है और राम नाम की दीवानगी भी अपने साकार स्वरूप में देश में सर्वत्र देखने को मिल रही है। अब जब भारत के कोने-कोने से लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं, ऐसे में विपक्ष जिस राम मंदिर का भाजपा के विरोध में हथियार के रूप में उपयोग करता रहा, उस राम मंदिर का मुद्दा उसे अपने हाथ से जाता दिख रहा है। तब विपक्षी गठबंधन नए तरीके से भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी और संघ परिवार पर हमलों के हथियार तलाश रहा है।

● **विपिन कंधारी**

370 का रखा है टारगेट...

2024 का रण सज चुका है। कुछ ही हफ्ते बचे हैं और भाजपा ने भी कमर कस ली है। इसकी झलक तब देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर जवाब देने उठे। प्रधानमंत्री ने भाषण में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री के भाषण में सरकार का हर मुद्दा साफ हो गया, हर इरादा साफ हो गया और ये भी साफ हो गया कि भाजपा इस बार 400 पार का लक्ष्य लेकर ही चल रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों लोकसभा में कांग्रेस और विपक्ष पर चुन-चुनकर हमले किए। प्रधानमंत्री ने 2024 के चुनावी मुद्दे भी तय कर दिए और भाजपा की मुहिम को भी रफ्तार दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार खुलकर संसद में जीत का टारगेट भी फिक्स कर दिया है। उन्होंने 5 साल पहले जब 2019 का चुनाव जीता था तो सबसे पहले जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करके अपना सबसे पुराना वादा पूरा किया था। अब 2024 के चुनाव में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद से जीत का लक्ष्य भी 370 रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा, आने वाले चुनाव में भाजपा 370 और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतकर आएगी और तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री के इस टारगेट के बाद चर्चाएं होने लगीं कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी नारा है या फिर वाकई भाजपा के पास इस बार 400 पार जाने का कोई ब्लू प्रिंट है?

बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने एक घंटे 40 मिनट लंबे भाषण में कई मुद्दों पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और देश में कमजोर विपक्ष के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं होने के दावे पर विपक्ष से यह भी पूछ लिया कि कब तक विभाजन के बारे में सोचते रहेंगे? मैं देख रहा हूं, बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौंसला भी खो चुके हैं। मैंने सुना है कि बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदले, इस बार भी सीट बदलने की फिराक में हैं। एक ही प्रोडेक्ट बार-बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान में ताला लगने की नौबत आ गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी हैं। पूरा देश कह रहा है अबकी बार मोदी सरकार। मैं आमतौर पर आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि देश का मिजाज एनडीए को 400 पार कराकर रहेगा और भाजपा को 370 सीटें अवश्य देगा। हमारा तीसरा कार्यकाल अगले 1000 सालों के लिए मजबूत नींव रखने का काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा और कहा, विपक्ष ने जो संकल्प किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। इससे मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है क्योंकि विपक्ष ने लंबे समय तक विपक्ष में ही रहने का संकल्प लिया है। अब कई दशकों तक जैसे सत्तापक्ष में बैठे थे, वैसे ही कई दशकों तक अब विपक्ष में बैठने का आपका संकल्प जनता जनार्दन जरूर पूरा करेगी। आप लोग (विपक्ष) जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं। मैं पक्का मानता हूं कि जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप आज जिस ऊंचाई पर हैं, उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में दिखेंगे।

जानकार कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो संसद में कहा, वो पहली बार बोला है। उन्होंने पहली बार भाजपा का लोकसभा चुनाव में सीट का नंबर बता दिया है। एनडीए की सीटों का लक्ष्य बता दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी बता दिया कि

इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी

इस बार भाजपा 2019 की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार उसके सहयोगी दलों की संख्या कम हो गई है। 2019 में भाजपा का पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, महाराष्ट्र में शिवसेना (अब उद्धव गुट), तमिलनाडु में एआईएडीएमके और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ अलायंस था। हालांकि, महाराष्ट्र में शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी का अजित गुट भाजपा के साथ आ गया है। महाराष्ट्र में भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। भाजपा ने 2019 के चुनाव में पंजाब की 13 में से 3, महाराष्ट्र की 48 में से 25 और बिहार की 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं, तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने भाजपा को 5 सीटें दी थीं। इस बार इन राज्यों में भाजपा अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने उप्र में ऐसी 14 सीटों की सूची तैयार की है जहां वो खुद को कमजोर पाती है।

सिर्फ 100 दिन बाद कितनी सीटों से जीतने की गारंटी भाजपा ने तय कर ली है? इसके पीछे कुछ वजहें भी हैं। 400 पार वाली गारंटी का गणित क्या है... भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीट जीती थीं। जबकि भाजपा के सहयोगी दलों ने 50 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसीलिए 370 का नंबर फिक्स करके 67 और सीट जीतने की तैयारी की गई है। ये सीटें भाजपा को कहां और कैसे मिलेंगी? सवाल ये भी है कि आखिर प्रधानमंत्री ने भाजपा के लिए 370 सीटों का कैलकुलेशन कैसे किया?

2019 में भाजपा 436 सीट पर लड़ी थी, 303 सीटों पर जीत मिली थी। 133 सीटों पर चुनाव हार गई थी। इस बार क्या और ज्यादा सीटों पर भाजपा लड़ने जा रही है? क्या एनडीए के लिए 400 पार की बात के पीछे भविष्य में और साथी दलों को जोड़ने की खबर छिपी हुई है? भाजपा का फोकस नॉर्थ के साथ-साथ साउथ पर भी है। क्योंकि नॉर्थ के ज्यादातर राज्यों में भाजपा का ही दबदबा है। इसलिए सिर्फ कमजोर या हारने वाली सीटों पर ही फोकस किया जा रहा है, ताकि पार्टी वहां भी जीत हासिल कर सके। आखिर प्रधानमंत्री के 400 सीटें जीतने के लक्ष्य का आधार क्या है? यह आंकड़ों के जरिए देखा तो भाजपा के पास 95 सीटें ऐसी हैं, जहां से वो पिछले तीन लोकसभा चुनाव के नतीजों में जीतते आ रही है। जबकि कांग्रेस के पास महज 17 सीटें ही ऐसी हैं, जहां वो लगातार तीन बार से जीत हासिल कर रही है। भाजपा शायद इसलिए भी 400 प्लस की गारंटी दे रही है, क्योंकि 173 सीटें ऐसी हैं, जहां कम से कम दो बार भाजपा चुनाव जीतते आ रही है। वहीं, कांग्रेस के पास भी ऐसी 34 सीटें हैं, जहां उसे दो बार से लगातार जीत मिल रही है।

भाजपा 76 सीटों को कमजोर आंकती है, यहां से उसे पिछले तीन चुनाव में सिर्फ एक बार जीत मिली है। बाकी दो बार हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, कांग्रेस के लिए 183 सीटें ऐसी हैं, जहां तीन में से एक चुनाव में जीत मिली है। पिछले तीन चुनाव में 199 सीटें ऐसी हैं, जहां भाजपा कभी नहीं जीती है। वहीं, कांग्रेस के लिए 309 सीटें ऐसी हैं, जहां उसे कभी भी जीत नहीं मिली है। भाजपा की कोशिश है कि नॉर्थ समेत अन्य राज्यों में अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराया जाए। जिन राज्यों और सीटों पर वो जीतते आ रही है, वहां प्रदर्शन बरकरार रखा जाए। इसके साथ ही जिन 89 कमजोर सीटों को चिन्हित किया गया है, वहां भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का प्रयास किया जाए। यही वजह है कि पार्टी किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। एनडीए में सहयोगी दलों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि विपक्षी दलों खासतौर पर क्षेत्रीय दलों को भी किसी तरह की बढ़त हासिल ना हो सके।

भाजपा की रणनीतियों का ही हिस्सा है कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक में बढ़त बनाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा ने बिहार में जदयू को एनडीए में शामिल करके इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका दिया है। वहीं कर्नाटक में देवगोड़ा की पार्टी जेडीएस के साथ गठबंधन किया है ताकि लिंगायत के साथ अन्य समुदायों तक सीधी पहुंच बनाई जा सके। अंतरिम बजट में लक्षद्वीप को लेकर बड़ी सौगात देकर संदेश दिया है। केरल और तमिलनाडु में भी भाजपा सक्रिय है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी भाजपा नेताओं को मैदान में उतारा गया है। यहां लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाकर भेजा गया है। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान से लेकर अन्य दिग्गजों को साउथ के राज्यों में भेजा रहा है और संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य दिया जा रहा है। इसके साथ ही अलायंस को लेकर भी भाजपा सक्रिय है। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण का साथ लिया है। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि टीडीपी को भी एनडीए के साथ लाने के लिए बातचीत का चैनल खुला रखा गया है।

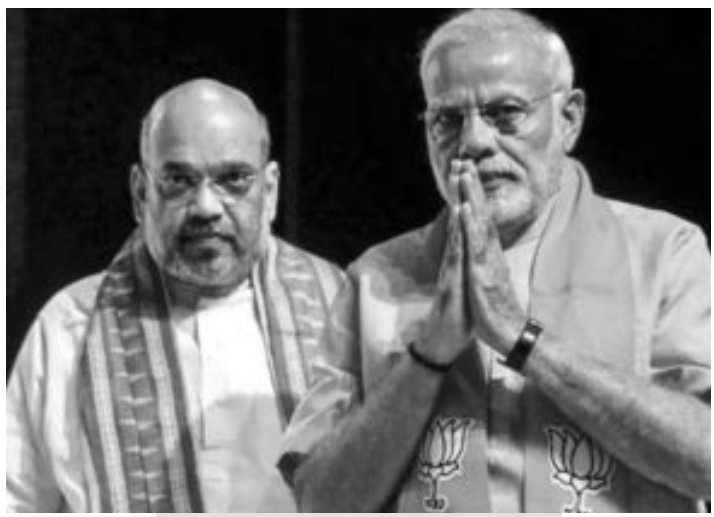

दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में बंपर जीत हासिल की है। यहां दो राज्यों से कांग्रेस को सरकार गंवानी पड़ी है। भाजपा के लिए ये बूस्टर माना जा रहा है। भाजपा ने मप्र में 29 में से 28 सीटें जीती थीं। राजस्थान में सभी 25 सीटें जीती थीं। जबकि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। देश में राम मंदिर उद्घाटन के बाद भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। इन प्रयासों में काफी हद तक सफल होते भी दिख रही है। भाजपा के साथ-साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मिशन साउथ पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में पहले लक्षद्वीप, फिर केरल का दौरा किया था। वहां विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी। राम मंदिर उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरों पर गए और मंदिरों में जाकर दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में भी विजन साफ कर दिया है। हिमाचल प्रदेश पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहां भाजपा एक बार फिर क्लीन स्वीप की तैयारी में है। भाजपा उप्र से लेकर उत्तराखंड तक पूरी तरह आश्वस्त है। 2019 के नतीजों के अनुसार, 190 सीटों के गणित को देखा जाए तो भाजपा का 175 और कांग्रेस का 15 सीटों पर दबदबा है। इनमें 72 प्रतिशत सीटों यानी 136 सीटों पर क्षेत्रीय दलों का रोल नहीं है। सिर्फ 13 सीट ऐसी हैं, जहां तीसरे नंबर की पार्टी का वोट कांग्रेस को पूरा मिलता तो भाजपा चुनाव हार सकती थी। भाजपा को 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिला है। वहां कांग्रेस से सीधा मुकाबला रहा है।

● इन्द्र कुमार

विपक्ष के वोट बंटने से भाजपा को मिलेगा लाभ

एक्सिस माय इंडिया के प्रदीप गुप्ता का कहना है कि राजनीति में संभव तो कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है, उसके लिए मैं इतना कह सकता हूं कि 2019 के चुनाव में एनडीए की 352 सीटें थीं। शिवसेना की 19 सीटें और जदयू की 16 सीटें थीं। शिवसेना (उद्धव गुट) अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। आज की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो भाजपा के टारगेट तक पहुंचने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा नहीं होना चाहिए और मल्टीपल कैंडिडेट खड़े होते हैं तो विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो जाएगा और भाजपा को सीधे फायदा मिलेगा। एलजेपी (रामविलास) के चीफ चिराग पासवान कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से हमें लगता है कि एनडीए को आज ही 400 सीटों का आंकड़ा मिल गया है। नरेंद्र मोदी युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों पर विश्वास करते हैं और उनके बारे में चिंतित हैं। भाजपा सांसद अपराजित सारंगी कहते हैं कि हमें अपने काम की बदौलत एनडीए को 400 सीटें मिलने की उम्मीद है।

बघेल पर शिकंजा

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के समय विवाद का बड़ा कारण बने महादेव सट्टा ऐप के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पहले भी एक आरोपी ने उनका नाम लिया था और पैसे लेने का दावा किया था, जबकि अब ईडी ने आरोपपत्र में बघेल का नाम शामिल किया है। बताया जा रहा है कि जल्दी ही उनको पूछताछ के लिए समन जारी किया जा सकता है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी असीम दास का दावा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर ने चुनाव के दौरान पैसा बघेल को भेजा था। ईडी ने दावा किया था कि असीम दास ने कहा है कि उसने बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए। हालांकि बाद में वह अपनी बात से मुकर गया था। लेकिन अब फिर ईडी ने कहा है कि वह अपने बयान पर कायम है। इस बीच मुंबई से इस केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने दीक्षित कोठारी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश कर 11 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है।

महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी के आरोपपत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आते ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में हड़कंप मच गया है। खबर सामने आने के बाद भाजपा ने छत्तीसगढ़ की जनता के पैसों को लूटने के पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए इसे भाजपा की साजिश बताया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि ईडी जांच एजेंसी नहीं, बल्कि भाजपा की षड्यंत्रकारी एजेंसी बन गई है। उन्होंने कहा कि असीम दास ने अदालत के सामने बयान दिया था कि ईडी ने उससे दस्तखत करवाया था। अब उस बयान को ईडी झुठलाने में लग गई है। उन्होंने दावा किया कि निष्पक्ष जांच में यह साफ हो जाएगा कि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाक साफ हैं।

रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत में 508 करोड़ रुपए से ज्यादा के महादेव ऐप सट्टा के मामले में दाखिल पूरक आरोप-पत्र ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक खास खेमे के नेताओं की परेशानी बढ़ा दी है। जेल में बंद कथित कैश कूरियर असीम दास के बयान के हवाले से आरोप-पत्र में कथित तौर पर कहा गया है कि महादेव ऐप का पैसा पूर्व सरकार के एक बड़े नेता के लिए ही भेजा गया था। पूरक आरोप-पत्र में कथित रूप से बघेल का जिक्र है। इस मामले में भूपेश बघेल ने 6 जनवरी को कहा था, ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर साजिश करके लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उनसे दबावपूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इन बयानों में जो पैसों के लेनदेन के आरोप लगाए गए हैं, उनका कोई आधार नहीं है। बघेल ने बताया कि जिस असीम दास के पास से रुपए बरामद हुए बताए गए, उसने जेल से हस्तलिखित बयान में कह दिया है कि उसे धोखे में रखकर फंसाया गया है और उसने कभी किसी नेता और उससे जुड़े लोगों को पैसा नहीं पहुंचाया। अब ईडी दावा कर रही है कि उसने वह बयान वापस ले लिया है। यह किस दबाव में हो रहा है, उसे सब जानते हैं।

जांच एजेंसी के 1,800 पन्नों के आरोप-पत्र में दावा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बघेल के लिए महादेव ऐप सट्टा प्रमोटर्स की तरफ से 508 करोड़ रुपए भेजे गए थे। उसमें दुबई में 99.46 करोड़ के फ्लैट और एक प्लाट जब्त करने की बात का भी जिक्र है। आरोप-पत्र में महादेव ऐप के कार्यकारी नीतीश दीवान के बयान को भी शामिल किया है जिसके मुताबिक नीतीश महादेव ऐप और उसकी सहायक कंपनी रेड्डी अन्ना बुक के 3200 पैनलों का संचालन करता है, जिससे प्रतिदिन करीब 40 करोड़ रुपए की आय होती थी। बताया जा रहा है कि ईडी पूर्व मुख्यमंत्री बघेल का बयान दर्ज करने उन्हें बुलाने की तैयारी कर चुकी है।

बघेल कहते हैं कि ईडी ने जिस दिन कथित रूप से असीम दास से रुपए बरामद किए थे उस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। इसका मतलब है कि पूरी घटना पूर्व नियोजित थी और इसका मतलब यही है कि इसकी कूटरचना ईडी ने ही की थी। ईडी ने दावा किया है कि चंद्रभूषण वर्मा ने भी अपना पहले का बयान वापस ले लिया है। बघेल कहते हैं कि वे तो शुरुआत से कह रहे हैं कि ईडी मारपीट से लेकर धमकी देने तक हर हथकंडे अपनाकर उनके और उनके सहयोगियों का नाम लेने का दबाव बना रही है। ईडी के नए दस्तावेज से यह और स्पष्ट हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि महादेव ऐप के घोटाले की जांच उन्होंने ही मुख्यमंत्री रहते शुरू की थी ताकि इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो और युवाओं को जुआखोरी की ओर धकेल रहे इस अपराध पर रोक लगे। छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है, जो गुनहगार होगा उसका नाम होना स्वाभाविक है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

40 हजार करोड़ से ज्यादा का खेल

ऑनलाइन सट्टेबाजी के एप महादेव के आरोपियों पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में दो आरोपियों पर ईनाम घोषित किया गया है, दो आरक्षकों को बर्खास्त किया गया है और यह मामला विधानसभा में भी गूंजा। महादेव एप एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का एप है, जिसमें विभिन्न खेलों पर दाव लगाया जाता है और इसका संचालन छत्तीसगढ़ के दुर्ग से होता रहा है, उसके बाद इसका संचालन दुबई से होने लगा। इस एप की जांच की शुरुआत के साथ ही पहली प्राथमिकी दुर्ग पुलिस ने दर्ज की थी। उसके बाद इस मामले में आयकर विभाग और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रवेश हुआ। जांच में पैसे के लेनदेन की बात साफ हुई थी और यह पूरा खेल 40 हजार करोड़ से ज्यादा का बताया गया। ईडी ने जांच के बाद एसीबी में भी एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई। पुलिस ने अभी हाल ही में दो प्रमुख आरोपी और इस एप के संचालक सौरभ चंद्राकर पर 35 हजार का ईनाम घोषित किया है, इसके अलावा एक अन्य आरोपी रवि उप्पल पर भी ईनाम घोषित किया जा चुका है। इस मामले में शामिल दो आरक्षकों अर्जुन सिंह यादव और भीम सिंह यादव को बर्खास्त कर दिया गया है।

मराठवाड़ा का गणित सेट

लोकसभा चुनाव करीब है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी कुछ ही महीने बाद होने हैं। सियासत के इस चुनावी मौसम में भाजपा के लिए बसंत और कांग्रेस के लिए पतझड़ की स्थिति बनती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में पहले मिलिंद देवड़ा, फिर बाबा सिद्दीकी और अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। मिलिंद देवड़ा भाजपा में शामिल हो चुके हैं, वहीं विधायकी से इस्तीफा देकर आए अशोक चव्हाण को भी कमल निशान वाली पार्टी ने राज्यसभा का टिकट थमा दिया है।

अशोक चव्हाण वही हैं जिन्हें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के रहते सबसे चर्चित कथित घोटालों में से एक आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के मामले में नाम सामने आने के बाद साल 2010 में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अशोक चव्हाण के भाजपा में आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करने वाली पार्टी को आदर्श घोटाले के सबसे बड़े चेहरे को अपने पाले में लाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? चव्हाण के साथ आ जाने में भाजपा को आखिर क्या फायदा दिख रहा है? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अशोक चव्हाण सूबे की सियासत में एक्टिव रोल चाहते थे। कांग्रेस में रहते हुए वह विधायक थे, सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे लेकिन उनके पास कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं थी जैसा कि वह चाहते थे। दूसरी तरफ, भाजपा भी उद्धव ठाकरे के साथ नहीं होने की वजह से नुकसान की संभावनाओं को कम से कम करने की कोशिश में है। आधी शिवसेना और आधी एनसीपी के साथ आ जाने के बावजूद सर्वे रिपोर्ट्स में भाजपा को लोकसभा चुनाव में सीटों के नुकसान के अनुमान सामने आ रहे थे। एक वजह यह भी हो सकती है कि भाजपा ने अब ऐसे नेताओं पर फोकस कर दिया है जिनका खास क्षेत्र में अपना जनाधार है और इस सांचे में चव्हाण भी फिट बैठते हैं। अशोक चव्हाण पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण के बेटे हैं। कांग्रेस अगर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखती है तो इसके लिए भी श्रेय शंकरराव चव्हाण को ही दिया जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अशोक चव्हाण ने मोदी लहर के बावजूद नांदेड़ लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में डालकर इसे साबित भी किया था। हालांकि, वह 2019 का चुनाव हार गए और अंतर 40 हजार वोट के करीब था। यह स्थिति तब थी जब भाजपा और एकजुट शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार को 1 लाख 66 हजार से अधिक वोट मिले थे।

वंचित बहुजन अघाड़ी इस बार कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी में है। बदली परिस्थितियों में नांदेड़ की जंग भाजपा को भी मुश्किल लग रही थी और शायद यही वजह है कि इस सीट का नाम भी पार्टी की लिस्ट में मुश्किल कैटेगरी में शामिल किया गया था। कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ में गिनी जाने वाली इस सीट से 1952 से लेकर अब तक हुए चुनावों में केवल चार बार ही गैर कांग्रेसी उम्मीदवार जीत सके। भाजपा को 2004 और 2019 में जीत मिली थी तो वहीं 1977 में जनता पार्टी और 1989 में जनता दल ने यह सीट जीती थी। भाजपा नेताओं को लगता है कि अशोक के पार्टी में आ जाने से यह सीट अब सबसे सुरक्षित सीटों की कैटेगरी में आ गई है। अशोक चव्हाण नांदेड़ में अच्छा प्रभाव रखते ही हैं, उनका मराठवाड़ा रीजन की सभी 16 सीटों पर अच्छा प्रभाव है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। महाराष्ट्र भाजपा भी अपने स्तर पर अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी कड़ी में फोकस उन इलाकों में जमीनी पकड़ रखने वाले दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ लाने पर है जहां पार्टी कमजोर रही है। अशोक चव्हाण के जरिए भाजपा की रणनीति मराठवाड़ा का गणित सेट करने की होगी। इस रीजन में विधानसभा की भी 46 सीटें हैं।

महाराष्ट्र कांग्रेस के जमीनी नेताओं में गिने जाने वाले चव्हाण का ग्रामीण इलाकों में अपना जनाधार माना जाता है। उनकी गिनती ऐसे नेताओं में होती थी जिन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। राहुल के एक अन्य करीबी मिलिंद देवड़ा के बाद अशोक के भी कांग्रेस छोड़ने से ग्रैंड ओल्ड पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर विपरीत असर पड़ सकता है और इसकी गूंज भी दिल्ली तक महसूस होगी। एक तरफ भाजपा अपना कुनबा बढ़ाते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है वहीं विपक्ष का ध्यान चुनावी तैयारी के साथ अपना कुनबा बचाए रखने की ओर भी बंटेगा। भाजपा महाराष्ट्र में जमीनी पकड़ रखने वाले नेताओं को साथ जोड़ने की रणनीति पर चल रही है तो उसका भी अपना गणित है।

● **बिन्दु माथुर**

भाजपा ने किया था जमकर विरोध

भाजपा की ओर से आदर्श हाउसिंग सोसायटी का मामला बड़े पैमाने पर उठाए जाने के कारण ही 2010 में अशोक चव्हाण को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2010 में मुंबई का आदर्श हाउसिंग सोसायटी का घोटाला राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, क्योंकि सेना की हाउसिंग सोसाइटी के लिए आवंटित जमीन पर बनाई गई हाउसिंग सोसायटी में राजनीतिक दलों के नेताओं को फ्लैट अलॉट किए गए थे, जिनमें अशोक चव्हाण के रिश्तेदार भी शामिल थे। इसमें अशोक चव्हाण की सास के नाम पर भी एक फ्लैट था, कुल 25 राजनीतिज्ञों को फ्लैट अलॉट किए गए थे। यह घोटाला 1999 में शुरू हुआ, जब सेना के कुछ पूर्व अधिकारियों ने हाउसिंग सोसाइटी के लिए मुख्यमंत्री के सामने आवेदन किया था। सरकार ने उसी समय कुछ दिनों में ही जमीन अलॉट कर दी, 2004 में जमीन सोसाइटी को सौंप दी गई, लेकिन 2010 में भारतीय नौसेना ने सुरक्षा की दृष्टि से हाउसिंग सोसाइटी बनाने का विरोध किया। बाद में खुलासा हुआ कि कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर इस सोसाइटी में फ्लैट ले लिए थे, जबकि उनका या उनके रिश्तेदारों का सेना से कोई ताल्लुक नहीं था।

अब क्या होगा दिग्गजों का

राजस्थान में पिछले 25 सालों से एक जैसी राजनीति चल रही थी। इस बार उसमें बदलाव कांग्रेस और भाजपा दोनों ने कर दिया है। रोचक बात है कि इस बदलाव में कई बड़े दिग्गज नेताओं का राजनीतिक करियर खुद फंस गया है। वर्ष 2023 के चुनावी परिणाम के बाद से एक ही सवाल भाजपा और कांग्रेस में चल रहा है कि अब इन दिग्गज नेताओं के राजनीतिक करियर का क्या होगा। क्योंकि, इन नेताओं की उम्र एक जैसी ही है। सभी ने 70 साल पार कर लिए हैं। ये अपनी पार्टी के शीर्ष हुआ करते थे। इसमें सभी कई बार सांसद और विधायक रह लिए हैं। इनकी अपनी क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा, शांति धारीवाल और ओम माथुर को लेकर राजस्थान की राजनीति में खूब चर्चा है।

तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने वाले अशोक गहलोत को पार्टी क्या जिम्मेदारी देने वाली है। क्या उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा या उन्हें संगठन में कोई जिम्मेदारी मिलेगी। क्योंकि, उनकी उम्र इस बार 72 साल हो गई है। कांग्रेस ने जिस तरह से 77 साल के कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया है, उससे यही संकेत मिल रहा है कि राज्य में पार्टी किसी भी 70 साल से अधिक उम्र वाले को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देने वाली है। अब सबकी नजरें अशोक गहलोत पर टिकीं हैं। राजस्थान में भाजपा का मजबूत चेहरा वसुंधरा राजे को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। राजे दो बार मुख्यमंत्री रहीं हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकीं हैं। इसके साथ ही राजे ने विधानसभा का चुनाव जीत लिया है, लेकिन आगे की क्या जिम्मेदारी होगी कुछ स्पष्ट नहीं है। इस बात की चर्चा पार्टी में खूब हो रही है। इनकी उम्र 70 पार हो गई है। क्या उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी इस पर भी संशय बना हुआ है। लेकिन, अभी सबकी नजरें इन पर टिकीं हुई हैं।

कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और 80 साल की उम्र पार करने वाले शांति धारीवाल के करियर को लेकर चर्चा तेज है। क्या उन्हें पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी या विधानसभा में विधायक के रूप में ही छोड़ दिया जाएगा। सरकार में नंबर दो की भूमिका पर रहने वाले शांति धारीवाल अब बेहद चुप हैं। उन्हें न तो पार्टी सदन में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है और न ही पार्टी में कुछ दिख रहा है। सबकी नजरें उन पर टिकीं हुई हैं। राजस्थान की राजनीति में पिछले कई दशकों से चर्चा में रहने वाले किरोड़ी लाल मीणा पर सबकी नजरें टिकीं हुई हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके किरोड़ी लाल को क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? सवाल यही उठ रहा है कि अब उनके पास क्या विभाग रहेगा? क्योंकि, किरोड़ी लाल मीणा की उम्र 72 साल हो चुकी है। अब उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी यह सवाल उनके समर्थकों में खूब चल रहा है। राजस्थान में कई जिम्मेदारी निभा चुके ओम माथुर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां पर उनके समर्थक उन्हें लेकर कई सवाल कर रहे हैं। 71 साल के ओम माथुर को क्या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या उन्हें केंद्र की सरकार में कोई रोल मिल सकता है। माथुर के करियर को लेकर पार्टी में भी कई तरह की चर्चाएं हैं। अब मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद और लोकसभा चुनाव के बाद कोई बड़ा फैसला इन पर हो सकता है।

पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड खंगालेंगे तो पाएंगे कि दोनों की परंपरागत सीट पर अक्सर पार्टियों को कमजोर कैंडिडेट ही खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि दोनों के आगे दूसरे प्रत्याशियों का चेहरा फीका पड़ जाता है। यह परंपरा 2023 विधानसभा में भी कायम रही और दोनों दिग्गज नेता आसानी से अपनी सीट पर चुनाव जीत गए। राजस्थान कांग्रेस में जैसी हैसियत अशोक गहलोत की है, वैसी ही शख्सियत राजस्थान भाजपा में वसुंधरा राजे की है। सुग्रीव के भाई बालि के समान दोनों के खिलाफ खड़े दूसरे प्रत्याशियों की ताकत आधी पड़ जाती है।

राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत ऐसे नेता के रूप में शुमार थे, जिनके सामने दूसरा नेता कभी पनप नहीं सका। 2018 में सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, फिर भी पार्टी पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। पायलट को उपमुख्यमंत्री से संतोष करना पड़ा। अंततः टकराव इतना बढ़ा कि पायलट को उपमुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा। पायलट सड़कों पर उतरे फिर भी गहलोत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। गांधीवादी छवि, सादगी, सहज उपलब्धता और क्षेत्र में बड़े स्तर पर विकास कार्यों के कारण गहलोत लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। क्षेत्र के लोगों को पता है कि उनका विधायक मुख्यमंत्री बनता है या विपक्ष में भी बैठकर सारे काम करवा लेता है। 2023 विधानसभा चुनाव में आंतरिक गुटबाजी से संभावित नुकसान से सत्ता को बचाने के लिए भाजपा राजस्थान में मोदी के चेहरे और कमल निशान पर चुनाव में उतरी थी। भले ही एक तरफ मोदी का चेहरा और कमल का फूल था, लेकिन स्थानीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री फेस के आंतरिक डिमांड को पार्टी इग्नोर नहीं करना चाहती थी, जिसके बिना चुनाव में जीतना मुश्किल था।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

नहीं मिला वसुंधरा-गहलोत को टक्कर देने वाला

यह सिलसिला पिछले 25 सालों से चला आ रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने जोधपुर की सरदारपुरा सीट और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने झालावाड़ की झालरापाटन सीट पर टक्कर देने वाला नेता अब तक नहीं मिला है। दोनों ने एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज कर पार्टी आलाकमान को बगले झांकने के लिए मजबूर कर दिया। तीन बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार की योजनाओं, 10 गारंटियों और विजन 2030 डॉक्यूमेंट के दम पर फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की कवायद में जुटे थे, पार्टी हार गई, लेकिन गहलोत नहीं हारे। जबकि दो बार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकीं वसुंधरा विपरीत परिस्थितियों के बाद भी झालरापाटन में फिर विजेता बनकर उभरीं। 2023 विधानसभा चुनाव ने पार्टी आलाकमान इस बार मोदी के चेहरे और कमल फूल के निशान पर चुनाव लड़ी थी, पार्टी जीती तो आलाकमान ने वसुंधरा के हाथों ही भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव करवा दिया।

उप्र का सबसे बड़ा धर्मार्थ बजट

उप्र को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर काम कर रही योगी सरकार ने गत दिनों विधानसभा में राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उप्र के बजट का आकार 7,36,437.71 करोड़ रुपए है। बजट में 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी शामिल हैं। यह बजट पिछले बजट से 6.7 फीसदी अधिक है। इसमें धार्मिक पर्यटन के अलावा रोजगार सृजन और महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार के प्रयासों से राज्य सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटे का अंतर भी कम हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 3.46 फीसदी राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया है।

बजट में धर्मार्थ कार्य के मद में 4,547 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पैसे से धर्मस्थलों वाले जिलों में मूलभूत संरचना का विकास एवं सुदृढ़ीकरण शामिल है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ तथा एयरपोर्ट विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। नैमिषारण्य में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी योगी सरकार ने अपना खजाना खोला है। योगी आदित्यनाथ ने बजट को राम को समर्पित लोकमंगल का बजट बताया। बजट में सरकार ने धार्मिक पर्यटन पर विशेष तौर पर फोकस किया है। पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बनाने की कोशिश की गई है। वर्ष 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक लगभग 37.90 करोड़ से अधिक पर्यटक उप्र आए। इनमें विदेशियों की संख्या 13 लाख 43 हजार रही। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, विंध्याचल, प्रयागराज, मथुरा-वृंदावन, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मां शाकुम्भरी देवी, सारनाथ, बटेश्वरधाम, गढ़मुक्तेश्वर जैसे धर्म से जुड़े स्थलों का विकास धार्मिक पर्यटन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। पर्यटन में राज्य की अर्थव्यस्था का मजबूत आधार बनने की पूरी क्षमता है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना की शुरुआत की जा रही है।

बजट में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। विधवा पेंशन के लिए 4037 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। महिला एवं बाल विकास के लिए कुल 6800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 5129 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि योगी आदित्यनाथ ने पुष्टाहार आपूर्ति का काम बड़ी कंपनियों से लेकर महिला समितियों के हवाले कर दिया था, जिससे लाखों महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। कन्या सुमंगला योजना के लिए सरकार ने 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 31 लाख से अधिक महिलाओं के लिए मासिक पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए की गई है। रोजगार सृजन के लिए सरकार ने अपना खजाना खोला है। 1,54,747 करोड़ रुपए की व्यवस्था रोजगार सृजन के मद में की गई है।

बजट में खर्च और आमदनी के अंतर को कम किया गया है। बजट में 6,06,802.40 करोड़ रुपए की राजस्व तथा 1,14,531.42 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 4,88,902.84 करोड़ रुपए है। इसमें राज्य सरकार का कर राजस्व 2,70,086 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,18,816.84 करोड़ रुपए शामिल है। बजट में 5,32,655.33 करोड़ रुपए का राजस्व लेखे तथा 2,03,782.38 करोड़ रुपए का पूंजी लेखे का व्यय है। सरकार ने 74,147.07 करोड़ रुपए के राजस्व बचत का अनुमान लगाया है। बीते छह सालों में उप्र के बजट का आकार दोगुना से ज्यादा बड़ा हो चुका है। अखिलेश सरकार ने जब वर्ष 2016-17 में अपना आखिरी बजट पेश किया था, तब बजट का आकार 3,46,935 करोड़ रुपए तथा राजकोषीय घाटा 4.04 प्रतिशत था। अपने आर्थिक सुधारों के जरिए योगी सरकार ने उप्र को देश का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना दिया है। राजकोषीय घाटा भी चार फीसदी के अंदर लाया गया है। तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उप्र अब महाराष्ट्र के बाद जीएसडीपी के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

देश की जीडीपी में उप्र की हिस्सेदारी 9.2 फीसदी

सेंसेक्स और क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार देश के जीडीपी में उप्र की हिस्सेदारी 9.2 फीसदी हो चुकी है। महाराष्ट्र 15.7 फीसदी हिस्सेदारी के साथ पहले नंबर पर है। कुछ वर्ष पूर्व तक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, बंगाल और कर्नाटक के बाद उप्र छठवें पायदान पर था, लेकिन प्रदेश सरकार की नीतियों एवं आर्थिक सुधारों की बदौलत देश की जीडीपी में उप्र ने अपनी हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि की है। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 9.1 फीसदी, गुजरात 8.2 फीसदी, पश्चिम बंगाल 7.5 फीसदी, कर्नाटक 6.2 फीसदी जीएसडीपी हिस्सेदारी के साथ उप्र के पीछे छूट चुके हैं। उप्र की जीएसडीपी वर्ष 2023-24 में 24,39,171 लाख करोड़ थी। निवेश के लिए सरकार के प्रयासों से राज्य की जीएसडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बीते छह साल में उप्र का बजट ही नहीं बल्कि जीएसडीपी भी दोगुना हो चुका है। वर्ष 2016-17 में उप्र की जीएसडीपी 12,47,658 लाख करोड़ रुपए थी, जिसके 2024-25 में 26 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन तथा फिल्म सिटी का निर्माण हो जाने के बाद उप्र की आर्थिक प्रगति को और अधिक रफ्तार मिलने की संभावना है। फिल्म सिटी का निर्माण भूटानी समूह और बोनी कपूर की कंपनी एक साथ मिलकर करने जा रहे हैं। आर्थिक सुधारों एवं प्रयासों से उप्र बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलने में सफल रहा है। बीते छह वर्षों में राज्य में प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी हुई है।

बिहार में खेल अभी खत्म नहीं

129 विधायकों के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार विधानसभा में अपना बहुमत तो सिद्ध कर दिया, लेकिन खेला करने के दावों और प्रतिदावों के बीच खेल का रोमांच अंत-अंत तक बिल्कुल वैसे ही बना रहा, जैसे लास्ट बॉल तक चले क्रिकेट मैच में देखने को मिलता है। आखिरकार जब विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 112 के मुकाबले 125 सदस्यों के बहुमत से पास हो गया, तभी स्थिति स्पष्ट हो पाई कि नीतीश सरकार के पास न केवल पर्याप्त बहुमत मौजूद है, बल्कि असली खेला राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो गया है, क्योंकि उसके तीन विधायक नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रह्लाद यादव सदन के अंदर एनडीए पक्ष के साथ खड़े नजर आए। एनडीए का समर्थन करने वाले तीन राजद विधायकों में से एक चेतन आनंद डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए बाहुबली आनंद मोहन के पुत्र हैं। आनंद मोहन को नीतीश सरकार ने पिछले ही साल बिहार जेल नियमावली 2012 में संशोधन करके रिहा कर दिया था।

चेतन आनंद गत दिनों अन्य राजद विधायकों के साथ तेजस्वी यादव के आवास पर ही थे, लेकिन उन्हें वहां से निकालने के लिए पुलिस के इस्तेमाल से एक बड़ा राजनीतिक खेल हुआ। चेतन आनंद के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें तेजस्वी यादव के आवास पर जबरन रोका गया है, जिसके बाद पुलिस तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच गई। इसके बाद चेतन आनंद वहां से जो निकले, तो विधानसभा में एनडीए कैम्प के साथ खड़े नजर आए। वे ठाकुर यानी राजपूत समुदाय से आते हैं और उन्होंने राजद से अपने निकलने का आधार ठाकुर स्वाभिमान को बनाया। गौरतलब है कि राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कुछ महीने पहले संसद में ठाकुर का कुआं नाम की एक कविता पढ़ी थी, जिससे राजपूत समुदाय के अनेक लोग काफी आहत महसूस कर रहे थे।

एनडीए का समर्थन करने वाली दूसरी राजद विधायक नीलम देवी उस बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी हैं, जो फिलहाल जेल में बंद हैं और जिनके खिलाफ अनेकों संगीन मुकदमे दर्ज हैं। लिहाजा अपने बचाव की खातिर सत्ता का संरक्षण प्राप्त करना उनके लिए बेहद जरूरी है। पहले भी अनंत सिंह को नीतीश कुमार का बेहद करीबी समझा जाता था। यहां तक कि एनडीए-1 की सरकार के दौरान कई लोग उन्हें छोटे सरकार तक कहा करते थे। राजद को छोड़कर एनडीए का समर्थन करने वाले तीसरे विधायक प्रह्लाद यादव रहे, जो राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्यों में माने जाते हैं। हालांकि उनकी छवि भी एक दबंग विधायक की ही है और वे वर्तमान उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के इलाके से आते हैं। क्या उन्होंने विजय सिन्हा के प्रभाव के कारण एनडीए सरकार का समर्थन किया या फिर कोई अन्य डील हुई, यह अभी रहस्य के परदे में है।

केवल एनडीए ने ही राजद के तीन विधायक नहीं तोड़े, बल्कि ऐसा लगता है कि राजद ने भी एनडीए के कई विधायकों को तोड़ने की भरपूर कोशिशें की। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के कम से कम पांच विधायकों को लेकर अंत तक सस्पेंस बना रहा, और वे काफी देर से सदन में हाजिर हुए। इनमें से एक जदयू विधायक संजीव का पता लगाने के लिए तो नीतीश सरकार को पुलिस का सहारा लेना पड़ा। आखिरकार पुलिस की निगरानी में ही उन्हें पटना लाया गया। चर्चा गरम है कि राजद के साथ मिलकर वे जदयू के कई विधायकों को तोड़ने की फिराक में थे। उनके खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में जदयू विधायक बीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण का केस भी दर्ज कराया गया है। विश्वास मत के परीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चेतावनी भी दी है कि जिन लोगों ने भी उनके विधायकों की खरीद-फरोख्त करने की कोशिशें की हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार ने खुला आरोप लगाया कि एनडीए के कई विधायकों को विरोधी खेमे ने अपने पाले में करने के लिए लाखों रुपए का ऑफर दिया था।

बिहार में खेला होने के दावों और कयासों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और उनके चार विधायकों को लेकर भी अफवाहों का बाजार गर्म रहा। जीतनराम मांझी ने नीतीश मंत्रिमंडल में अपनी पार्टी से केवल एक मंत्री बनाए जाने के प्रति खुलकर नाराजगी जताई थी और यह भी कहा था कि विपक्षी खेमे से उन्हें मुख्यमंत्री तक बनाए जाने के ऑफर मिल रहे हैं। ऐसे बयानों के कारण जीतनराम मांझी भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरकर सामने आए। हालात की गंभीरता को भांपते हुए भाजपा ने उन्हें संभालकर रखने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को मोर्चे पर लगाया। अगर जीतनराम मांझी को भाजपा ने न संभाला होता, तो नीतीश कुमार के संभालने से वे संभलने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्हें देने के लिए आज नीतीश कुमार के हाथ में कुछ भी नहीं है।

● **विनोद बक्सरी**

क्या गारंटी है फिर पलटी नहीं मारेंगे नीतीश कुमार

हालांकि नीतीश कुमार एक बार फिर से यह कह रहे हैं कि अब वे भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनकी बातों पर किसी को भरोसा नहीं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही है कि वे जिस भी गठबंधन में रहते हैं, एक न एक दिन उसकी थाली में छेद अवश्य ही करते हैं। नीतीश कुमार के इसी रिकॉर्ड को देखते हुए तेजस्वी यादव ने विधानसभा में व्यंग्य भी किया कि क्या मोदी की गारंटी देने वाले यह गारंटी दे सकते हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मारेंगे? सच भी है कि अपनी गारंटियों के लिए मशहूर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी आज नीतीश कुमार के बारे में यह गारंटी देने की स्थिति में नहीं होंगे। संभव है कि लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से वे पलटी मारकर महागठबंधन के साथ चले जाएं। नीतीश की आलोचना करते हुए एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने भाषा की पूरी सावधानी बरती, उन्हें आदरणीय बताया, पिता समान बताया और राजा दशरथ से उनकी तुलना की। वहीं नीतीश कुमार भी राजद के प्रति उस तरह से आक्रामक नहीं दिखे, जैसे कि भाजपा के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिखाई दिए। उन्होंने विपक्षी विधायकों की तरफ मुखातिब होकर कहा कि हम किसी को नुकसान नहीं करेंगे। हम आपके सबके हित में काम करेंगे। आप जिस समुदाय के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए भी हम काम करेंगे। संकेत साफ हैं कि बिहार की राजनीतिक घोड़ा-मंडी में खेला अभी खत्म नहीं हुआ है। बिहार के दुर्भाग्य से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का वातावरण अभी अगले कुछ और सालों तक बना ही रहेगा।

पाकिस्तान में सेना ही सरकार

पाकिस्तान की गाड़ी हमेशा की तरह अस्थिरता के गियर में फंसी हुई है। सेना के साए में 8 फरवरी को चुनाव हुए। अब नतीजे सबके सामने हैं। किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर लगे बैन के बाद पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्दलीय उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के बावजूद इमरान की पीटीआई और नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) दोनों पार्टियों ने सरकार बनाने का दावा किया है। इस बार सत्ता की लड़ाई दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के बीच है। कभी सेना के फेवरेट बॉय रहे इमरान खान अब उनकी आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। इमरान की पार्टी पर बैन लगाकर उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया। यही वजह थी कि उनके पार्टी के उम्मीदवारों को निर्दलीयों के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने को मजबूर होना पड़ा।

पाकिस्तानी सेना ने इस बार नवाज शरीफ पर दांव लगाया था। इसका लेआउट तैयार होते ही पिछले साल आनन-फानन में नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान वापस बुलाया गया। उन पर लगे भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को रद्द कर दिया गया और उन पर लगी चुनावी रोक भी हटाई गई। इस तरह से पाकिस्तान की सेना ही तय करती है कि सत्ता की कुर्सी पर किसे बैठाना है और किसे बेदखल करना है? ऐसे में सोचना लाजिमी है कि लोकतांत्रिक पाकिस्तान में सेना के पास इतनी ताकत कहां से आई? पाकिस्तानी सेना का कद इतना कैसे बढ़ा कि उसने सियासत तक में पैठ जमा ली? और सबसे जरूरी बात कि 1947 में अलग देश के रूप में अस्तित्व में आई पाकिस्तान की सेना भारत की सेना से इतनी अलग कैसे है कि वह राजनीति में इतनी गहराई तक रच-बस गई है? पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां सेना और सत्ता एक सिक्के के दो पहलू हैं। यही वजह है कि सेना में सत्ता और सत्ता में सेना की झलक दिख ही जाती है। पाकिस्तान में ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ, जो सेना के साए में ना हुआ हो।

ब्रिटिश हुकूमत से भारत को आजादी मिलने के बाद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान उभरा। धर्मनिरपेक्ष भारत से बिल्कुल जुदा पाकिस्तान का वजूद ही धर्म था। ये वो दौर था, जब दोनों देशों की सेनाओं का विस्तार भी हो रहा था। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लेखक स्टीवन विल्किनसन ने अपनी किताब आर्मी एंड नेशन: द मिलिट्री एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस में कहा है कि आजादी के बाद जब पहली बार भारत में अंतरिम सरकार बनी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सेना की बागडोर लोकतांत्रिक सरकार के नियंत्रण में सौंप दी थी। इस दिशा में सबसे पहले सेना में कमांडर इन चीफ का पद खत्म किया गया। यह पद अंग्रेजों के शासनकाल से चला आ रहा था। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने इसे अनावश्यक बताते हुए इसे खत्म कर दिया। बता दें कि सेना में कमांडर इन चीफ के पास एकमुश्त ताकत होती है। पाकिस्तान की सेना में अभी भी कमांडर इन चीफ का पद कायम है, जिसे सत्ता का केंद्र समझा जाता है।

विल्किनसन अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि नेहरू ने उस समय कहा था कि फौज के आधुनिकीकरण के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं की अहमियत बराबर की होनी चाहिए। इस वजह से तीनों सेनाओं के अलग-अलग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किए गए। इतना ही नहीं किसी भी तरह की तख्तापलट की संभावना ना हो इसलिए इन तीनों सेनाओं को रक्षामंत्री के अधीन रखा गया, जो चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के तहत काम करता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र शुरुआत से ही कमजोर था, जिसकी वजह सेना थी। पाकिस्तान के इतिहास में अब तक तीन बार तख्तापलट हुआ है। भारत में आजादी के बाद जिस समय लोकतंत्र का विस्तार हो रहा था, उस समय 1958 आते-आते पाकिस्तान में पहला तख्तापलट हो चुका था। पाकिस्तान में पहले लोकतांत्रिक चुनाव 1970 में हुए जबकि भारत में 1952 में ही पहला चुनाव हो चुका था। दरअसल सेना को ऐसी स्थिति में तख्तापलट का मौका मिलता है, जब देश में भारी अस्थिरता हो, राजनीतिक विभाजन चरम पर हो और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हों। भारत में ऐसी स्थिति कभी पैदा ही नहीं हुई। यहां तक कि इमरजेंसी के दौरान भी सेना राजनीति से अलग रही। 1946 में भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ क्लाउड ऑचिनलेक ने नेहरू से कहा था कि भारतीय सेना को पता है कि उनका काम सिर्फ भारत सरकार की नीतियों के तहत काम करना है। वहीं, आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ जनरल केएम करियप्पा ने फौज को लिखी चिट्ठी में कहा था कि सेना में राजनीति जहर की तरह है। इससे दूर ही रहना चाहिए।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

सत्ता पर कैसे हावी हुई सेना

साल 1953 में लाहौर में अहमदिया मुस्लिमों के विरोध में दंगे हुए थे। पाकिस्तान की सरकार इन दंगों को कंट्रोल नहीं कर पाई, जिस वजह से कानून एवं व्यवस्था को बहाल करने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और इस तरह पाकिस्तान में पहली बार मार्शल लॉ लगा। हालांकि, ऐसा करने पर देश में कानून एवं व्यवस्था तो बहाल हो गई लेकिन सेना तो सत्ता का स्वाद चख चुकी थी। कहा जाता है कि उस समय सेना ने सड़कें बनाने से लेकर कम्युनिकेशन नेटवर्क मजबूत करने तक कई तरह के काम कर आवाम का भरोसा जीत लिया था। पाकिस्तान की आवाम अब सरकार से ज्यादा सेना से उम्मीदें लगाने लगी थी। जिस वजह से 1958 में दूसरी बार पड़ोसी मुल्क में तख्तापलट हुआ और देशभर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगने के बाद पाकिस्तान का एक बड़ा वर्ग काफी खुश हुआ और कहा जाने लगा माशाअल्लाह...। अब तो पाकिस्तान में माशाअल्लाह (मार्शल लॉ) हो गया...। ये वही दौर था, जब पाकिस्तानी सत्ता पर सेना हावी हो गई थी। तख्तापलट का ये दौर यहीं नहीं रुका, इसके बाद 1977 और 1999 में भी देश में सेना ने सरकार पलट दी। यही हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। हाल ही में वॉयस ऑफ अमेरिका के एक सर्वे में सामने आया था कि पाकिस्तान के लोग सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा सेना पर भरोसा करते हैं। सर्वे में 74 फीसदी रेटिंग के साथ सेना को सबसे भरोसेमंद संस्थान बताया था। ये सर्वे इसी साल जनवरी में हुआ था। इस सर्वे में शामिल लोगों ने राजनीतिक दलों को 50 फीसदी रेटिंग दी थी।

आसान नहीं ट्रम्प की राह

संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में कुछ ही महीनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव होने हैं जिसको लेकर अमेरिकी चुनावी पार्टियों के बीच घमासान जारी है। अमेरिकी चुनाव व्यवस्था के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को हरेक राज्य में अपने-अपने दल के प्रत्याशियों संग प्रतिस्पर्धा में भाग लेना होता है। सबसे अधिक राज्यों में जीत दर्ज कराने वाला प्रत्याशी ही राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ता है। आयोवा और न्यू हैम्पशायर में ट्रम्प की जीत के बाद भारतीय मूल की नम्रता निक्की रंधावा हैली जो वर्तमान में दक्षिण कैरोलाइना प्रांत की गवर्नर हैं, ट्रम्प को चुनौती देती नजर आ रही हैं वहीं ट्रम्प की राह में कई कानूनी पेंच हैं जिन्हें पार पाना आसान नहीं लग रहा है।

दो बार महाभियोग का सामना कर चुके ट्रम्प पर 91 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में ट्रम्प पर 2020 के चुनाव नतीजों को पलटने का आरोप है। जिस पर अपील कोर्ट ने माना है कि 6 जनवरी 2021 को व्हाइट हाउस में किए गए कृत्यों के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। फेडरल अपील कोर्ट ने ट्रम्प के उस दावे को भी खारिज कर ट्रम्प को बड़ा झटका दिया है जिसमें उन्होंने मुकदमे से बचने के लिए कानूनी प्रतिरक्षा यानी लीगल इम्यूनिटी होने का दावा किया था। लीगल इम्यूनिटी असल में उस स्थिति में होती है जब किसी व्यक्ति या संस्था को कानून के उल्लंघन के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। खास बात यह है कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी अपील कोर्ट के सामने ऐसा केस आया जिसमें किसी पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने पर बहस हुई और फैसला भी आया। अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या किसी पूर्व राष्ट्रपति को सिर्फ इसलिए गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि घटना के समय वो देश का प्रेसिडेंट था। उसने पद पर रहते हुए इस तरह का अपराध किया है।

गौरतलब है कि अमेरिका में जजों की नियुक्ति राजनीतिक पार्टियां ही करती हैं। जिस पैनल ने गत सप्ताह 6 फरवरी को फैसला सुनाया उसमें शामिल दो जज डेमोक्रेट और एक रिपब्लिकन पार्टी ने नियुक्त किया था। पैनल ने कहा- ये सही है कि प्रेसिडेंट रहने की वजह से प्रेसिडेंट को काफी पावर्स हासिल हैं, लेकिन कानून सबके लिए एक ही है। हमारे लिए इस समय पूर्व राष्ट्रपति भी बाकी अमेरिकी नागरिकों की तरह ही है। ट्रम्प के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन और जांच एजेंसियों 2020 के बाद कई केस दर्ज कराए थे। इनमें चुनाव नतीजे पलटने की साजिश से लेकर संसद पर हमले को न रोक पाने का केस भी शामिल है। पिछले दिनों ट्रम्प की लीगल टीम ने इस केस की सुनवाई टलवाने की नाकाम कोशिश की थी। ट्रम्प इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अगले राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की रेस में सबसे आगे हैं। 13 फरवरी को कैरोलिना प्राइमरी में उनका मुकाबला निक्की हेली से होगा। ऐसे में ट्रम्प के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रम्प दूसरी बार राष्ट्रपति बन पाएंगे? ट्रम्प के चुनावी अभियान से क्या केस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? केस पेंडिंग होते हुए अगर ट्रम्प फिर से राष्ट्रपति बन गए तो क्या होगा?

अमेरिकी कानूनविदों की मानें तो अब ट्रम्प के पास दो विकल्प हैं। पहला ये कि वो अपील कोर्ट के फैसले को सीट्टो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें या फिर वो इसकी रिव्यू की अपील करें। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो मामले का निपटारा जल्द हो सकता है और हो सकता है कि फैसला उनके हक में न आए लेकिन अगर वो अपील कोर्ट में ही जाते हैं तो सुनवाई में वक्त लग सकता है और इससे ट्रम्प को ही फायदा होगा। अमेरिकी जानकारों का कहना है कि ट्रम्प को इन आरोपों का ताप झेलना पड़ सकता है। दोषी के रूप में उनकी प्रचार करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। वहीं ट्रम्प यूनिवर्सिटी लॉ एंड गवर्नमेंट के प्रोफेसर क्रेग ग्रीन ने कहा कि ट्रम्प का आपराधिक अभियोगों का सामना करना अभूतपूर्व है। वह प्राथमिक सीजन के दौरान परीक्षण के लिए जा सकते हैं। केवल आरोप तय होने से ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वह दोषी भी ठहराए जाते हैं तो कोई भी आरोप उन्हें राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से रोक नहीं सकता। भले ही उनके ऊपर कई मामले चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वह स्वतंत्र रूप से चुनाव प्रचार कर सकते हैं। ट्रम्प को अगर जेल भी भेजा जाता है, तो भी वह प्रचार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

● **कुमार विनोद**

चुनावी अभियान से केस पर कोई प्रभाव पड़ेगा

डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ संघीय आपराधिक आरोपों ने पूर्व राष्ट्रपति के बारे में अमेरिकियों के विचारों को बदला है। रॉयटर्स-इप्सोस पोल के मुताबिक, उन्हें रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन की दौड़ में कमांडिंग लीड बनाए हुए दिखाया गया है। ट्रम्प ने अपने केसों को एक फंड रेसिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने समर्थकों से हमेशा यही कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है और उन्हें पूरे सहयोग की जरूरत है। ट्रम्प के चुनावी अभियान के अनुसार, न्यूयॉर्क में अप्रैल महीने में जब उन पर अभियोग केस चला तो इस दौरान डोनेशन में वृद्धि हुई थी। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए ट्रम्प के अधिकांश प्रतिद्वंद्वी उनके समर्थन में आ गए हैं, रिपब्लिकन मतदाताओं के बीच उनके लिए व्यापक समर्थन दिया गया है। अगर ट्रम्प नवंबर 2024 का चुनाव जीतते हैं तो अभियोजन पक्ष के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। अमेरिकी न्याय विभाग कार्यकारी शाखा का हिस्सा है और राष्ट्रपति देश में शीर्ष संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं। अमेरिकी न्याय विभाग की दशकों पुरानी नीति है कि एक मौजूदा राष्ट्रपति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अदालत द्वारा ट्रम्प को दोषी पाया जाता है, तो भी वह कानूनी रूप से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकेंगे। अमेरिकी संविधान के लिए केवल यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अमेरिकी नागरिक हों जो कम से कम 35 वर्ष के हों और 14 वर्षों से देश में रह रहे हों। नियमों के मुताबिक, राष्ट्रपति के लिए दोषी अपराधी या यहां तक कि सलाखों के पीछे रहकर भी चुनाव लड़ने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है। इसलिए ट्रम्प दोषी पाए जाते हैं तो भी कानूनी रूप से चुनाव लड़ सकते हैं।

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

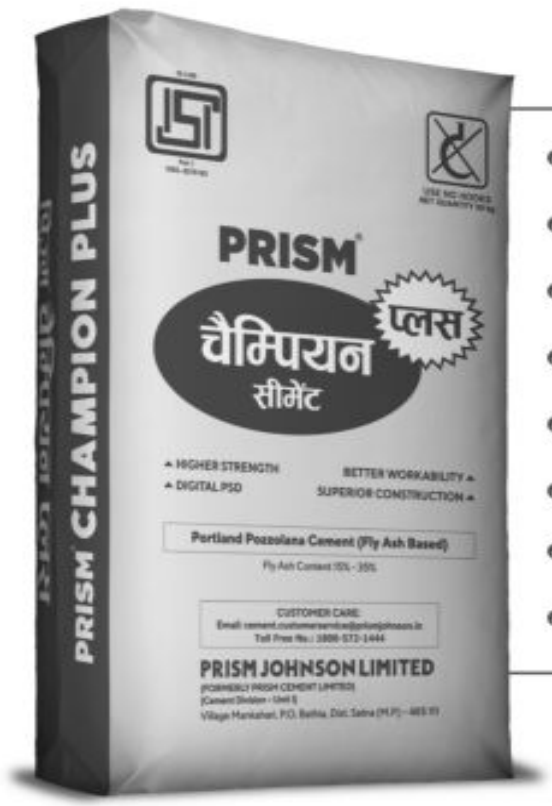

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दशरथ राघव कैसे कहलाए 'राम'

हिंदू धर्म में रामायण और रामचरित मानस को श्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ का माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरित मानस की रचना की गई है। रामचरित मानस में जहां रामजी के राज्याभिषेक तक का वर्णन मिलता है, तो वहीं रामायण में श्रीराम के महाप्रयाण (परलोक गमन) तक का वर्णन किया गया है।

कैसे रामलला के जन्म के बाद अवधपुरी में उत्सव सा माहौल था और नगर को ध्वजा, पताका और तोरणों से सजाया गया था। तुलसीदास अपनी चौपाई में इसका सुंदर वर्णन करते हुए लिखते हैं-

अवधपुरी सोहइ एहि भांती।
प्रभुहि मिलन आई जनु राती॥
देखि भानु जनु मन सकुचानी।
तदपि बनी संध्या अनुमानी॥

यानी राम के जन्म के बाद अवधपुरी ऐसे सुशोभित हो रही जैसे मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देख सकुचा गई हो। इस तरह मन में विचारकर वह संध्या बन गई। अब जानते हैं रामलला के जन्म के कितने दिन बाद और किसके द्वारा हुआ उनका नामकरण।

रामलला का नामकरण- रामलला के जन्म के बाद उनका नाम दशरथ राघव रखा गया। लेकिन बाद में रामजी का नामकरण रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार, राम शब्द दो बीजाणु से मिलकर बना है। इसमें पहला अग्नि बीज और दूसरा अमृत बीज है। राम के नाम का अर्थ प्रकाश विशेष से है। इसमें रा का अर्थ प्रकाश और म का अर्थ विशेष है। रामजी को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। लेकिन सिर्फ अवतार ही नहीं बल्कि राम का नाम भी विष्णु जी से जुड़ा है। दरअसल धार्मिक पुस्तिका सहस्त्राम में भगवान विष्णु के हजार नामों का उल्लेख मिलता है, जिसमें विष्णुजी का 394वां नाम राम है। रामजी के साथ ही महर्षि वशिष्ठ ने ही भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का भी नामकरण किया था।

कछुक दिवस बीते एहि भांती।
जात न जानिअ दिन अरु राती॥
नामकरन कर अवसरु जानी।
भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी।।

इस तरह से रामलला के जन्म के कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय आया और राजा दशरथ ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठजी को बुलाया।

करि पूजा भूपति अस भाषा।
धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा॥
इन्ह के नाम अनेक अनूपा।
मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा॥

मुनि की पूजा कर राजा बोले- हे मुनि! आपके मन में जो विचार हो सो नाम रखिए। मुनि ने कहा- हे राजन! इनके अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा।

जो आनंद सिंधु सुखरासी।
सीकर तें त्रैलोक सुपासी॥
सो सुखधाम राम अस नामा।
अखिल लोक दायक बिश्रामा॥

ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिसके कण से तीनों लोक सुखी हैं, उनका (दशरथ के बड़े पुत्र का) नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। रानी कौशल्या और राजा दशरथ के बड़े पुत्र का नामकरण करने के बाद महर्षि वशिष्ठ सुभद्रा और कैकयी के पुत्रों का भी नामकरण करते हैं।

बिस्व भरन पोषन कर जोई।
ताकर नाम भरत अस होई॥
जाके सुमिरन तें रिपु नासा।
नाम सत्रुहन बेद प्रकासा॥

जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनका (दशरथ के दूसरे पुत्र) का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रुओं का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है।

लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार।
गुरु बसिष्ठ तेहि राखा लछिमन नाम उदार॥

जो शुभ लक्षणों के धाम श्री रामजी के अत्यंत प्यारे और संपूर्ण जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठजी द्वारा उनका श्रेष्ठ नाम लक्ष्मण रखा गया।

हिंदू धर्म में रामायण और रामचरित मानस को श्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ की मान्यता प्राप्त है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरित मानस की रचना की गई है। रामचरित मानस में जहां रामजी के राज्याभिषेक तक का वर्णन मिलता है, तो वहीं रामायण में श्रीराम के महाप्रयाण (परलोक गमन) तक का वर्णन किया गया है। रामलला के जन्म से प्रसन्न और गौरान्वित होकर राजा दशरथ ने नेग देने का निश्चय कर लिया था, लेकिन सभी ने नेग लेने से इंकार कर दिया। क्योंकि जनमानस को तो केवल अपने इष्ट रामलला के दर्शन मात्र की लालसा थी। ऐसे में किन्नर समाज के लोगों ने राजा के भेंट को स्वीकार किया और नवपुल्लवित पुष्प को सकल ब्रह्मांड के आदित्य होने का वरदान दिया।

अब जानेंगे कि त्रेतायुग में रामलला के जन्म के बाद कैसी सजी थी अवधपुरी। हिंदू धर्म में चार युग बताए गए हैं। त्रेतायुग इन्हीं युगों में दूसरा युग है। सतयुग के समाप्त होने के बाद त्रेतायुग की शुरुआत मानी जाती है। यह युग 12 लाख 96 हजार वर्ष का था। कहा जाता है कि, इस युग में मानव की आयु करीब 10 हजार वर्ष साल होती है। इस युग में भगवान विष्णु ने पांचवे अवतार वानम, छठा अवतार परशुराम और सातवां अवतार श्रीराम के रूप में जन्म लिया। त्रेतायुग से श्रीराम का संबंध इसलिए भी गहरा है, क्योंकि इस युग के आखिरी और सातवें अवतार श्रीराम थे, जिनका जन्म अयोध्या के महराजा दशरथ के घर हुआ था। त्रेतायुग में भगवान राम के सरयू नदी में जल समाधि लेने के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ।

● **ओम**

आस्था के पुष्प

प्रात: काल का समय, पर्वतों की ओट से सूर्य की सुनहरी आभा आसमान को सिंदूरी लाली से भर रही थी। पंछीगण चहचहाते हुए, सूर्योदय का अभिनंदन कर रहे थे। मंदिरों से घंटियों और शंख की ध्वनि, वातावरण झंकृत कर रही थी। ठीक ऐसे पावन समय में, कहीं से दूर से- सीताराम! सीताराम! जाप करने की आवाज आती है।

कुछ ही पल में एक पंडितजी दूर से आता हुआ दिखाई दिया। दरअसल वह स्नान करके मंदिरों की ओर पूजा करने आ रहा था। तभी वह बिल्कुल पास ही आ गया, और मंदिर में न प्रवेश करके वह पुष्प उद्यानों की ओर बढ़ गया। और जैसे ही उद्यान में पहुंचा, वह पुष्पों के झाड़ियों की ओर लपका। पर ये क्या? वह पंडित जी, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी, दूसरी से तीसरी झाड़ी, और कई झाड़ियों के पास गया पर वह पुष्प नहीं तोड़ पाया। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, पंडित जी को प्रणाम करता है- पंडित जी प्रणाम! इसके इस शिष्टाचार को वह अनदेखा कर देता है। और वह पंडित जी अपने पुष्पों की तलाश में इधर-उधर चहल कदमी कर ही रहा था। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति आया, और झट से पुष्प तोड़ के मंदिर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह मंदिर में प्रविष्ठ हुआ, पंडित जी ने टोकते हुए कहा- ठहरो! ठहरो!!

ये क्या कर रहे हो वह पुष्प पवित्र नहीं है!

क्यों पंडित जी! उस बुजुर्ग ने कहा।

पंडित जी ने कहा- वह पुष्प का पेड़ अपवित्र स्थान पर है अत: वह पुष्प भी...! अत: वह चढ़ाने योग्य नहीं है?

तब फिर उस बुजुर्ग ने गंभीर मुद्रा में कहा- पंडित जी पवित्रता हमारे मन में होनी चाहिए, मन में आस्था के पुष्प होने चाहिए। कोई पेड़ अपवित्र जगह में है इसका यह मतलब नहीं की वह पुष्प अपवित्र हो गया। कमल भी तो कीचड़ में ही खिलता है पर वह कभी अपवित्र नहीं होता! हमारा जन्म भी तो इसी प्रकार से हुआ है, तो क्या हम अपवित्र हो गए?

बुजुर्ग की बात ने पंडित जी की आत्मा में पड़े पर्दे को हटा दिया था। पंडित जी को बात समझ में आ गई थी, उसने निश्छल होकर पुन: सीताराम! सीताराम! कहते हुए पुष्प तोड़ना शुरू कर दिया।

- अशोक पटेल 'आशु'

भाभी की चूड़ियां

भैया और भाभी के बीच कुछ अनबन हुई तो सरला से रहा नहीं गया कि भैया भाभी के साथ जरूर कुछ ऐसा व्यवहार किए होंगे जिसे वह मुझसे फोन पर बतलाई नहीं। सिसक कर रह गई। आखिर कोई मर्द नशे में आकर नारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करता है, कि नारी हृदय से कांप जाती है। वह मादक चीज पीने के बाद कभी कलाई मरोड़ देता है तो कभी चूड़ियां ही फोड़ देता है। पगला कहीं का। सरला ने आते के साथ आवाज दी- कहां हो भाभी, जरा सामने तो आओ तुम, कैसी हो?

अरे सरला, आपको आने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही कुछ होते रहता है पति-पत्नी के बीच। सारी बातें वह एक स्वर में कह गई।

लेकिन भाभी की दोनों कलाई तो सुनी थी। जिसे देख सरला ने कहा- भाभी, चुड़ियां की कीमत कुछ और होती है। तुम इसे पहले पहनो।

ठीक है बाबा, पहन लेती हूं, मैं।

सरला मुस्कुरा उठी और... और भाभी की चूड़ियां नशे की बुरी आदत के मुंह पर थप्पड़ जड़ रही थी।

- विद्या शंकर विद्यार्थी

मील का पत्थर

मैं सड़क किनारे वर्षों से गड़ा
मील का पत्थर हूं।
गड़ा जब से अब तक
सड़क के कई रंग रूप बदले
लंबे समय तक कच्ची राहों से गुजरते
वाहनों की उड़ती धूल माटी से
बलरंग होता रहा।
फिर लंबे इंतजार के बाद
मुझ पर चढ़ा दी डामर की परत
देखते ही देखते वाहनों की गति फर्राटे
भरने लगी
लोगों के पहुंचने की जल्दबाजी में
होने लगी वाहन दुर्घटनाएं
सड़के होने लगी लहूलुहान
मचने लगी घायल लोगों की चीख
पुकार।
मुझे और गौरवशाली व उपयोगी
बनाने के लिए
कर दिया महिमा मंडित सीमेंट कांक्रीट
के चिकने पन से
हवा से बातें करने लगे वाहन
दूर होने लगी सहज आनंद भरी यात्राएं
वर्षों से निभा रहा हूं अपना धर्म
लोगों को दे रहा हूं यात्रा की जानकारी
कितनी कर चुके और कितनी है
करनी
पथ राही तो मुझे देख लगते हैं सोचने
बस थोड़ा और चलना है पहुंच जाएंगे
समय रहते
दुनियाभर में अपनी उपयोगिता के
कारण ही
प्रसिद्ध दुआ मैं
मील का पत्थर नाम से।

- दिनेश विजयवर्गीय

टीम इंडिया की नई पीढ़ी

हैदराबाद में जब इंग्लिश टीम के बैजबॉल और स्पिन बॉल के सामने मेजबान जब औंधे मुंह गिरे तो सवाल कई उठे। खराब फॉर्म की वजह से बाहर किए अनुभवी टेस्ट बल्लेबाजों को वापस बुलाने की मांग भी उठने लगी। हालांकि यूथ ब्रिगेड ने इसका जवाब वाइजेग में बल्ले से मैदान पर विजय की कहानी लिखकर दिया। उसने इशारा कर दिया है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या फिर रेड बॉल फॉर्मेट, अपने हुनर से हार को जीत में बदलना उन्हें आता है। सबसे पहले बात उस चेहरे की जिसकी चमक देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी यशस्वी भव: का आशीर्वाद दिया। अगर कोई बल्लेबाज 22 साल की उम्र पूरा करते-करते मैदान पर दोहरा शतक जड़ने की कहानी लिख दे तो ऐसा होना लाजमी है। यशस्वी जायसवाल ने साबित कर दिया कि जिंदगी की जंग हो या फिर क्रिकेट का मैदान, उन्होंने ठान लिया है कि हार नहीं मानूंगा।

क्रिकेट गेंद का रंग चाहे सफेद हो या फिर रंगीन, रनों की भूख और खेल के लिए यशस्वी का जुनून नहीं बदलता। विरोधियों पर छा जाने के उनके आक्रामक अंदाज को इसी बात से समझिए कि उन्होंने अपना शतक छक्के के साथ और दोहरा शतक चौका जड़कर पूरा किया। यही बात उन्हें दूसरे बल्लेबाजों से अलग बनाती है। इसीलिए तो ये भी कहा जा रहा है कि मैदान पर बैजबॉल नहीं जैशबॉल का जलवा दिख रहा है। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी का लोहा बड़े-बड़े दिग्गज इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उनकी 209 रन की पारी टर्न और बाउंस भरे विकेट तथा ऐसे वक्त पर आई जब दूसरे छोर से बड़े-बड़े बल्लेबाजों के आने और जाने का सिलसिला जारी था।

कभी डेयरी में काम करने और गोल गप्पे बेचने के दौर से गुजर चुके यशस्वी मिले मौके को भुनाने का मतलब अच्छी तरह जानते हैं। उनकी इसी काबिलियत ने उन्हें सचिन, काबंली और शास्त्री के साथ उस एलीट क्लब में शामिल करा दिया जिन्होंने अपने 23वें बर्थडे से पहले घरेलू मैदान और विदेशी जमीन, दोनों ही जगहों पर शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। आत्मविश्वास से भरे यशस्वी जायसवाल के तरकश में हर वो तीर मौजूद है जो विरोधी गेंदबाजों को परेशान कर सकता है और उनकी लाइन-लेंग्थ को बिगाड़ सकता है। वाइजेग टेस्ट की पहली पारी में उनकी बल्लेबाजी इसकी बानगी है। यशस्वी ने न सिर्फ बड़े आराम से जमीनी शॉट खेले, बल्कि हवाई शॉट खेलने में भी उनकी सहजता देखते ही बनी। पारी में खेले उनके कट शॉट, ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट बताते हैं कि उनकी तकनीक कितनी मजबूत है।

यशस्वी ने अपनी बल्लेबाजी से ये अहसास करा दिया है कि वो तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। हालांकि यशस्वी खुद ये बात कहते हैं कि हर फॉर्मेट अलग होता है, गेंद अलग होती है, मैदान अलग होता है, इसलिए वे अलग माइंडसेट के साथ खेलने उतरते हैं। वहीं उनके सलामी जोड़ीदार कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि यशस्वी खेल को अच्छी तरह समझते हैं और वे टीम के लिए बेहतरीन योगदान दे सकते हैं लेकिन उन्हें अभी लंबा सफर तय करना है, ऐसे में जरूरत है कि वे विनम्र रहें यानी उनके पैर जमीन पर रहें।

एक और युवा बल्लेबाज ने अपनी बल्लेबाजी से फिर अहसास करा दिया कि फॉर्म इज टेंपरेरी बट क्लास इज परमानेंट। नाम है शुभमन गिल। 2023 में क्रिकेट के हर फॉर्मेट में गिल का बल्ला रन उगलता दिखा था। हालांकि 2024 में टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने पारी की शुरुआत करने के बजाय तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की गुजारिश की। टीम मैनेजमेंट ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उन पर भरोसा भी जताया लेकिन पहली तीन पारियों में मिली नाकामी के बाद उन पर उंगलियां भी उठने लगीं। तीन में से दो पारियों में वो अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। हैदराबाद टेस्ट की पहली पारी में गिल ने 23 रन बनाए तो वहीं दूसरी पारी में वो खाता भी नहीं खोल पाए। वाइजेग टेस्ट की पहली पारी में भी यही कहानी जारी रही और वे सिर्फ 34 रन बना पाए। हालांकि दूसरी पारी में उनसे उम्मीदें ज्यादा थी क्योंकि टीम इंडिया बैकफुट पर थी। टीम से बाहर होने का खतरा टालने के लिए उन्हें बड़ी पारी की दरकार थी। साथ ही रणजी ट्रॉफी में अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का शानदार फॉर्म भी उनके लिए खतरे की घंटी बजा रहा था। ऐसे में उनकी किस्मत ने साथ दिया और वो टीम के लिए संकटमोचक साबित हुए। उनकी 104 रन की शतकीय पारी ने टीम इंडिया का मेहमान टीम से फासला इतना बड़ा कर दिया कि उसे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा।

इतना ही नहीं ये पिछले सात साल में घरेलू मैदान पर नंबर तीन पर किसी भारतीय बल्लेबाज का पहला शतक भी रहा। शुभमन गिल के बल्ले से 11 महीने बाद टेस्ट शतक निकला। हालांकि शतक पूरा करने के बाद गिल ने अपने खास अंदाज में इसका जश्न नहीं मनाया क्योंकि उन्हें मालूम था कि टीम के लिए उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उनकी ये सोच बताती है कि भले ही वो युवा हों लेकिन टीम के लिए उन्हें अपनी जिम्मेदारी का अहसास है। इस शतक ने गिल को इस बात का अहसास जरूर कराया कि बल्लेबाजी के वक्त संयम और बेसिक्स पर टिके रहना जरूरी है। साथ ही रनों का अंबार लगाने के लिए अपने अंदाज में बदलाव करने की सोच बनाने के बजाय जैसा खेलते आए हैं उसी तरह खेलते रहना और खुद पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है।

● **आशीष नेमा**

युवा क्रिकेटरों की सोच भारतीय क्रिकेट के लिए शुभ संकेत

टेस्ट क्रिकेट को क्रिकेट का सबसे खालिस अंदाज माना जाता है। ऐसे में इस फॉर्मेट में खुद को साबित करने की युवा क्रिकेटरों की सोच भारतीय क्रिकेट के लिए शुभ संकेत है। टेस्ट टीम में हाल के दिनों में अनुभवी लेकिन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे चेहरों पर भरोसा करने के बजाय युवा जोश और घरेलू क्रिकेट में उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को तरजीह दी गई है। यशस्वी जायसवाल और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ियों को उनकी कड़ी मेहनत का ईनाम मिल गया है, तो वहीं घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाले सरफराज खान भी टीम का हिस्सा हैं। उन्हें भी जल्द ही डेब्यू का मौका मिल सकता है। कप्तान रोहित शर्मा तो खुद मानते हैं कि उनकी यंग टेस्ट टीम में टैलेंट की भरमार है। वो चाहते हैं कि इन युवा खिलाड़ियों को मैदान पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता रहे। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज इन युवाओं के लिए गोल्डन चांस है। हालांकि कप्तान के भरोसे पर खरा उतरने का बड़ा चैलेंज भी उनके सामने है। युवा खिलाड़ियों को भी इस बात का अहसास होगा कि चूकने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि उनकी जगह लेने वालों की कतार काफी लंबी है।

मां-पापा और भाई, सब हैं सुपरस्टार, 21 फिल्मों में हुई फ्लॉप...

सिंगल हिट नहीं दे सकी स्टार बेटी

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भारतीय सिनेमा में अब भी राज कर रहे हैं। दोनों ने पर्दे पर भी अभिनय के जरिए लोगों को इंप्रेस किया और फिर ये जोड़ी असल जिंदगी में सभी का अटेंशन लेती है। वहीं धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी सुपरस्टार हैं। बॉबी देओल का करियर बीच में डाउन हो गया था लेकिन अब वे फिर से सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। हालांकि, धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल वो मुकाम हासिल नहीं कर सकीं और अब उनका परिवार भी बिखर चुका है। यहां हम ईशा देओल के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं।

हेमा *मालिनी और धर्मेंद्र दोनों ही सुपरस्टाप रहे। कपल की बेटी ने भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा लेकिन वो बॉलीवुड में सफल करियर बरकरार नहीं रख सकीं। वहीं उनका निजी जीवन भी हाल ही में उथल-पुथल भरे दौर से गुजरा जब वो एक दशक साथ बिताने के बाद अब अपने पति से अलग हो गई हैं।*

आपको बता दें कि हेमा मालिनी ने ही ईशा को बॉलीवुड में शामिल होने और फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने की सलाह दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से ईशा देओल अपनी मां हेमा मालिनी और पिता धर्मेंद्र की तरह स्टारडम हासिल नहीं कर पाईं। ईशा देओल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत विनय शुक्ला की कोई मेरे दिल से पूछे (2002) में आफताब शिवदासानी के साथ मुख्य भूमिका से की थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अपने डेब्यू के बाद ईशा ने लगातार फ्लॉप फिल्में दीं। 2002 से 2004 तक ईशा देओल अभिनीत 6 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। इस लिस्ट में ना तुम जानो ना हम, क्या दिल ने कहा, कुछ तो है, चुरा लिया है तुमने, एलओसी कारगिल और युवा जैसी फिल्में शामिल थीं।

अमिताभ ही नहीं, सुपरस्टार राजेश खन्ना से भी टूटी थी दोस्ती, शत्रुघ्न सिन्हा मांगना चाहते थे माफी, तभी हो गया बड़ा हादसा

बॉलीवुड *के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं, जो आए दिन सामने आती रहती हैं। हाल ही में, उन्होंने मीडिया से बातचीत में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्तों पर बात की। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उनकी दोस्ती टूट गई थी और क्यों शत्रुध्न सिन्हा उनसे खफा थे।*

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती सिर्फ अमिताभ के साथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ भी थी, और उनके साथ भी शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती टूट गई थी और फिर दोनों की दोस्ती हो भी नहीं पाई, हालांकि शत्रुघ्न पैचअप करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा हादसा हो गया। हाल ही में एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राजनीति की वजह से दोनों की दोस्ती में दरार पड़ी थी। उन्होंने बताया कि इस राजनीति ने ही उन दोनों के रिश्तों को काफी नुकसान पहुंचाया। दरअसल, बात 1992 की है, जब एक उपचुनाव के दौरान राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा आमने-सामने थे।

कुंवारा बैठा है 46 साल का ये एक्टर, कर रहा है सलमान खान के निकाह का इंतजार, बोला- जब बड़े भैया शादी कर लेंगे, मैं भी...

बॉलीवुड *सुपरस्टार सलमान खान की लव लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है। भले ही अभिनेता 58 साल के हो चुके हैं, लेकिन फीमेल फैंस के बीच उनकी दीवानगी का आलम आज भी कम नहीं हुआ है। सलमान खान का नाम बॉलीवुड की कई हसीनाओं से जुड़ा, लेकिन आज तक अभिनेता ने शादी नहीं की है। इस बीच वेलेंटाइन डे पर अपनी शादी के बारे में बात करते हुए अभिनेता अश्मित पटेल ने कहा कि वह बड़े भैया सलमान खान के बाद ही शादी करेंगे। थोड़े समय पहले सीरीज स्टेट वर्सेज आहूजा के साथ स्क्रीन पर लौटे अश्मित ने वेलेंटाइन डे पर अपनी शादी के बारे में बात की। अश्मित ने हंसते हुए कहा, बड़े भैया सलमान खान की शादी के बाद ही मैं शादी करूंगा।*

फिल्म दिल दिया है में अपने काम के लिए मशहूर अभिनेता ने कहा, प्यार विशेष रूप से रोमांटिक रिश्तों में उस व्यक्ति या रिश्ते को विशेष बनाने के लिए एक रोजमर्रा की चीज है। अश्मित ने कहा, यह रोमांटिक नोबल्स या फिल्मों में चित्रित कल्पना नहीं बल्कि कड़ी मेहनत है।

अगले जनम मोहे कूनो न भेजियो!

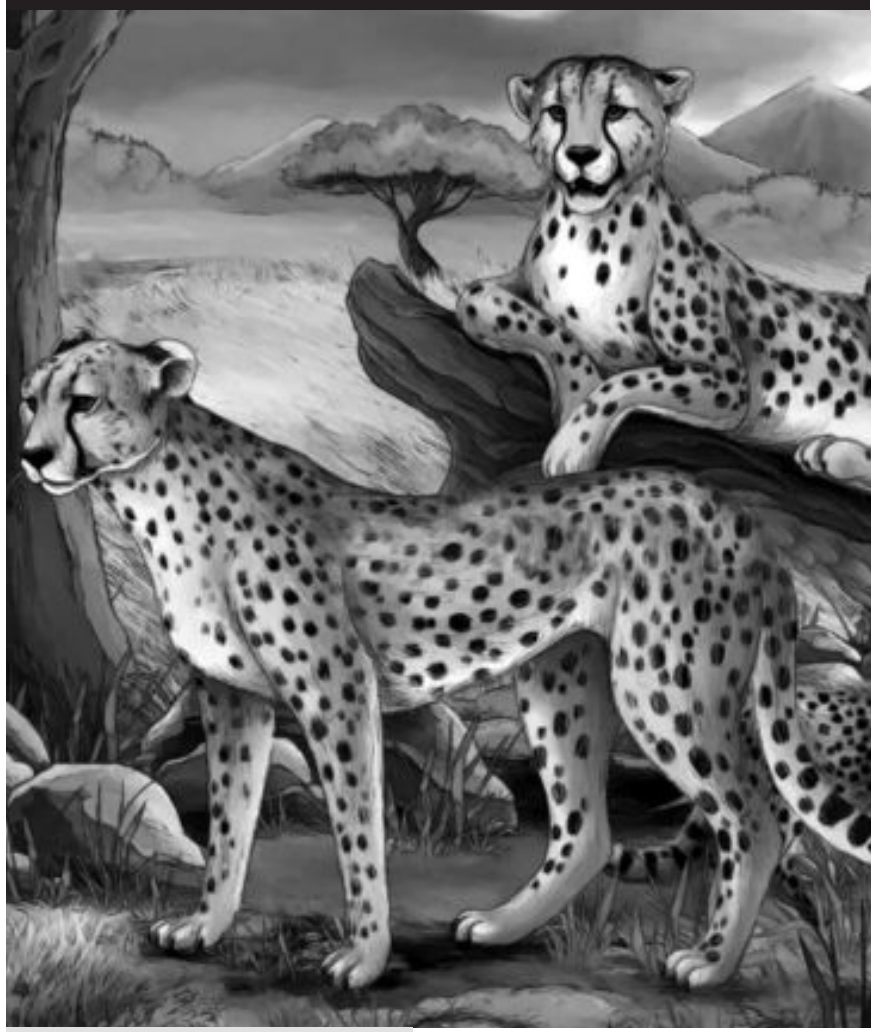

गुफा की घंटी बजी। सावित्री ने दौड़कर गुफा का दरवाजा खोला तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसके सामने हटटा-कट्टा स्वादिष्ट भैंसा खड़ा था।

अब खबरें तफसील से सुनिए। बहुत पुरानी बात है। अफ्रीका के एक जंगल में सावित्री नामक मादा चीता अपने पति सत्यवान के साथ हैपी-हैपी रहती थी। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिनों की नहीं थी। वैसे भी जब इस फैशन के दौर में गारंटी की कोई गारंटी नहीं है तो खुशी की कोई कैसे गारंटी दे? हुआ यह कि एक दिन चीतों का समूह जंगल में घूम रहा था, तभी अचानक सावित्री-सत्यवान समेत कुछ और चीतों को पकड़कर भारत के कूनो में भेज दिया गया।

नया देश, नई आबोहवा और नया पॉलिटिकल एटफोस्फेयर। जब तक वह कुछ समझते अचानक कूनो में किसी महामारी के बहाने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया। सारे पशु अपनी गुफाओं में और पक्षी अपने घोंसलों में दुबक गए। शाकाहारी जानवर तो अपनी गुफाओं के आसपास के घास-पत्ते खाकर गुजारा कर रहे थे पर मांसाहारियों पर इस लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ा। सावित्री-सत्यवान जैसे चीतों को खाने के लाले पड़ गए। दोनों अपनी गुफा के अंदर भूख से बिलबिला रहे थे। दोनों अपने-अपने फोन से तमाम फूड डिलिवरी ऐप को खटखटा चुके थे कि नीलगाय या जंगली भैंस नहीं तो एक-आध हिरन ही आ जाए।

अचानक गुफा के दरवाजे की घंटी बजी और सावित्री ने लपक कर यह सोचते हुए दरवाजा खोला कि शायद ऑनलाइन फूड डिलिवरी से कोई आया है। दरवाजा खोलते ही उसे सामने एक मोटा-ताजा भैंसा दिखा।

पर जैसे ही सावित्री उस भैंसे पर लपकी स्वयं यमराज ने उसका रास्ता रोक लिया। अपना आधार कार्ड दिखाते हुए यमराज ने कहा, मैं वाई डॉट राज उर्फ यमराज हूं और सत्यवान को लेने आया हूं जिसने अभी-अभी भूख से बिलबिला कर दम तोड़ा है।

इतना कहते हुए वह सत्यवान को लेकर चीतों के स्वर्ग की ओर चल पड़े। सावित्री असमंजस में थी। एक ओर सत्यवान था, दूसरी ओर लाइफ इंश्योरेंस के करोड़ों रुपए और सत्यवान की सरकारी नौकरी जो उसे मिलने वाली थी। कूनों की भूमि को धन्य करते हुए सावित्री ने सत्यवान को चुना और यमराज से बोली, प्रभु मुझे सत्यवान चाहिए!

जैसा कि कहानी में होना था, यमराज ने कहा, तुम चाहो तो तीन वर मांग लो पर सत्यवान को मैं ले जाऊंगा। सावित्री बोली, प्रभु मुझे पहला वर यह दीजिए कि मैं कौन बनेगा करोड़पति का जैकपॉट जीत जाऊं जिससे एक छोटा-मोटा स्टार्ट अप शुरू कर सकूं।

> “ *प्रभु मुझे कूनो नहीं भा रहा है। मैं चाहती हूं कि आप मुझे नामीबिया भेज दें जहां मैं सत्यवान के बच्चों की मां बन सकूं।* ”

यमराज बोले, तथास्तु!

सावित्री के जनधन खाते में टुन्न की घंटी बजी और एक करोड़ रुपए आ गए।

सावित्री बोली, मुझे दूसरा वर यह दीजिए कि मेरे स्टार्ट अप को शार्क-टैंक में एक धमाकेदार डील मिल जाए। यमराज बोले, स्मार्ट लेडी! तथास्तु! अब जल्दी बताओ तीसरा वर क्या है?

सावित्री बोली, प्रभु मुझे कूनो नहीं भा रहा है। रह-रह कर नामीबिया के जंगलों की याद आती है। मैं चाहती हूं कि आप मुझे नामीबिया भेज दें जहां मैं सत्यवान के बच्चों की मां बन सकूं।

यमराज बोले, तथास्तु!

सावित्री इठलाकर बोली, प्रभु सत्यवान को आप ले जाओगे तो मैं भला उसके बच्चों की मां कैसे बन पाऊंगी? अब यमराज को अपनी गलती का पता चला पर बहुत देर हो चुकी थी।

जल्द ही सावित्री अपने सत्यवान, करोड़ रुपए और शार्क टैंक की एक धमाकेदार डील के साथ एयर नामीबिया के प्राइवेट जेट में सवार थी।

सावित्री ने दूर तक फैले कूनो के जंगलों को आखिरी बार के लिए देखा जहां उसके साथ आए चीतों में दस मर चुके थे। उसने बुदबुदा कर कहा, अगले जनम मोहे कूनो न भेजियो!

● **प्रमोद दीक्षित 'मलय'**

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

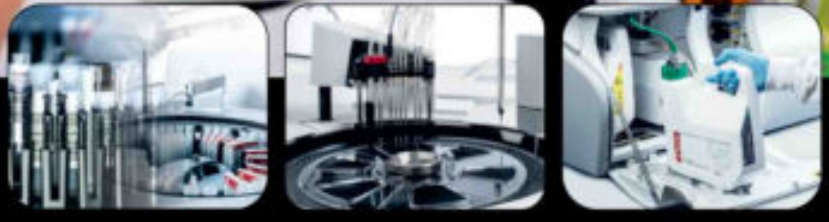

BA200

BioSystems

The Highest Flexibility

Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

Mahesh Patidar
Builder & Promoter

We Build Your
DREAM HOUSE